चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

लोकसभा की कार्यवाही में चौथी दुनिया और रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट

पेज 3

राज्यसभा में चौथी दुनिया

पेज 5

नरेगा में फेरबदल क्यों

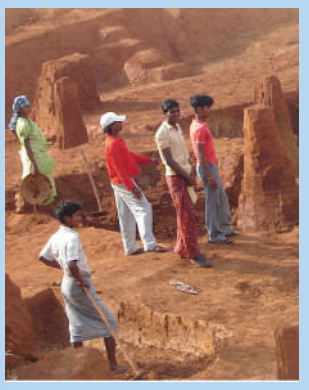

पेज 6

विवाद में डीयू कुलपति की नियुक्ति चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल

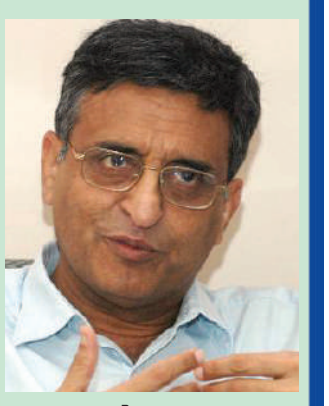

पेज 7

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

वे आठ मिनट जिन्होंने इतिहास रचा

संसद में चौथी दुनिया

राज्यसभा के सांसदों ने सात दिसंबर को नोटिस सभापति को दिया, आठ दिसंबर को उसे सदन में रखा, जिस पर सभापति ने संतोष भारतीय और चौथी दुनिया को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. दूसरी ओर नौ दिसंबर को ही लोकसभा में मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को लोकसभा में इसी सत्र में रखने का आश्वासन दिया.

क्या सचमुच रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी?

मनीष कुमार

संसद में चौथी दुनिया की गूंज जारी है. कई सालों बाद किसी अख़बार में छपी रिपोर्ट पर संसद में हंगामा हो रहा है. जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों ने आपके अख़बार चौथी दुनिया के हवाले से रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आखिरकार झुकना ही पड़ा. उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिया है कि संसद के वर्तमान सत्र के अंत तक रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. राज्यसभा में भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा जारी रहा. इन दोनों सदनों में क्या हुआ, इसका पूरा विवरण आप इस अख़बार के पेज नंबर 3 और 5 पर पढ़ सकते हैं. लेकिन इससे पहले इस मामले से जुड़े ऐसे दो पहलुओं के बारे में जानना ज़रूरी है, जो दुनिया की नजर में आने से रह गए. दोनों ही बातें चौंकाने वाली हैं. पहली तो यह है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आश्वासन के बावजूद रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाएगा. दूसरी बात यह है कि चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय को सच बोलने की सज़ा मिलने जा रही है. उन्हें राज्यसभा से नोटिस मिला है जिसमें यह कहा गया है कि चौथी दुनिया में छपे लेख से सांसदों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है.

क्या सचमुच रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश होगी?

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे पर मुलायम सिंह ने लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी. 9 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के सांसद और मुलायम सिंह ने चौथी दुनिया अख़बार लोकसभा में लहराया. जब उन्होंने इस अख़बार में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया तो प्रधानमंत्री को इस मसले पर बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कई दिनों से राज्यसभा में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा होता रहा. राज्यसभा में अलग-अलग दलों के सांसदों ने रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मांग की थी. राज्यसभा में इस मामले पर इतना ज़बर्दस्त हंगामा हुआ कि कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. सरकार इस बात से वाक़िफ़ थी कि जिस मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, वह मामला लोकसभा में भी उठ सकता है. इसलिए यह यक़ीन किया जा सकता है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए रणनीति ज़रूर बनाई होगी. सरकार ने इस पर क्या रणनीति बनाई, इसकी जानकारी हमें कांग्रेस के सूत्रों से मिली.

लोकसभा में हंगामे की घटना के ठीक दो दिन बाद यानी 11 तारीख़ को कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया जाएगा. लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी चिंतित है. मुलायम सिंह ने जिस तरह के तेवर दिखाए, और उस वक़्त लोकसभा में जिस तरह हंगामा चल रहा था, उसे शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह बयान दे दिया कि रिपोर्ट को इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा.

कांग्रेस पार्टी इसे एक ऐसा मुद्दा मानती है, जिससे विपक्ष में फूट पड़ जाएगी. इसलिए इस मामले को जितना टाला जाए, उतना ही सरकार के लिए लाभदायक है. हमारे सूत्रों के मुताबिक़, दलित मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण की सुविधा देने का सुझाव देने वाली रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को दबाने के लिए अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे को हवा दी गई है, ताकि मीडिया और विपक्ष का ध्यान बंट जाए. यही वजह है कि राज्यसभा में भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने की मांग पर सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मॉडल की बात कहकर असली मुद्दे को टाल दिया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह के तेवर को शांत करने के लिए यह तो कह दिया कि रिपोर्ट को इस सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन कब पेश किया जाएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया. कांग्रेस पार्टी इस बात से भी नाराज़ है कि झारखंड में मुसलमान कांग्रेस का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं. ग़ौर करने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह जी 17 तारीख़ को कोपेनहेगन जा रहे हैं. कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक़, उनके जाने के बाद तेलंगाना के मामले को और हवा दी जाएगी और ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री के कोपेनहेगन जाने के अगले दिन ही संसद के वर्तमान सत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा.

अगर हमारे सूत्रों की ख़बर सही है तो दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के आरक्षण का मामला ठंडे बस्ते में जाना तय है. कमज़ोर और ग़रीब अल्पसंख्यकों के साथ यह बड़ी नाइंसाफ़ी होगी. हमारी हार्दिक इच्छा है कि चौथी दुनिया की यह ख़बर झूठी साबित हो. अगर ऐसा होता है तो हमें इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी होगी. और अगर हमारी ख़बर सही साबित हुई तो संसद के इतिहास में इसे काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा. सदन में वादा करने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री उससे मुकर जाते हैं तो यह गलत परंपरा को प्रोत्साहित करेगी. अफ़सोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार और साफ़ छवि वाले व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो देश की जनता आखिर किस नेता पर विश्वास करे!

सभी चित्र टीवी द्वारा खींचे गए

संतोष भारतीय के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

सच की राह पर चलना कठिन है, यह हम जानते हैं. क़ानून के डर से सच का साथ छोड़ देने वाली पत्रकारिता हमने नहीं सीखी है. यही वजह है कि चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय को राज्यसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. इस नोटिस की वजह है रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को पेश न करना राज्यसभा का अपमान नामक लेख, जिसे चौथी दुनिया के पिछले अंक में छापा गया. इस लेख को आपके संपादक संतोष भारतीय ने लिखा. इस लेख को पढ़कर राज्यसभा के कई सांसद इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार और इसके संपादक संतोष भारतीय के ख़िलाफ़ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. नोटिस देने वाले सांसदों में अली अनवर (जदयू), अजीज़ पाशा (सीपीआई), राजनीति प्रसाद (राजद) और साबिर अली (लोजपा) हैं. इन सांसदों ने यह नोटिस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अली अंसारी को दी. उपराष्ट्रपति ने इन सांसदों को यह विश्वास दिलाया है कि चौथी दुनिया और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

संपादक संतोष भारतीय को विशेषाधिकार हनन का नोटिस

पांच बेहतर और पांच बेकार मुख्य सूचना आयुक्तों के लिए आरटीआई अवार्ड की घोषणा ने हबीबुल्लाह की त्यौरियां चढ़ाने का काम किया है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सूचना आयोग में खेल शुरू

केंद्रीय सूचना आयोग में वजाहत हबीबुल्लाह का उत्तराधिकारी ढूंढने में सरकार को उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही वक़्त लग रहा है. सूचना आयुक्त एम ए अंसारी या सूचना आयुक्त ए एन तिवारी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने की सरकार की योजना नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी की स्वीकृति न मिल पाने के कारण कार्यान्वित नहीं हो पाई है. उन्होंने संकेत दिया है कि अगर पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण बेदी या आरटीआई एक्टिविस्ट शेखर सिंह को हबीबुल्लाह का उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. संभव है, किरण बेदी के अभियान में आडवाणी के समर्थन ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई हो, उन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन हासिल है.

दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने आयोग में एक और विवाद को जन्म दे दिया है. पांच बेहतर और पांच बेकार मुख्य सूचना आयुक्तों के लिए आरटीआई अवार्ड की घोषणा ने हबीबुल्लाह की त्यौरियां चढ़ाने का काम किया है. हबीबुल्लाह जो कि अभी जम्मू–कश्मीर के सूचना आयुक्त हैं, ने इसे शर्मनाक करार दिया है. किसे कौन सा अवार्ड मिलता है, यह तो अलग बात है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार नए मुखिया को नियुक्त करने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं गंवाएगी.

उत्तर प्रदेश के बाबुओं की दुविधा

हरमिंदर राज सिंह 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे और प्रधान सचिव–हाउसिंग के पद पर थे. उनके द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने की घटना के बाद मायावती के अधीन काम करने वाले बाबुओं को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वे खुलकर सामने आ गई हैं. सिंह को प्रधान सचिव–सिंचाई के पद से स्थानांतरित करके प्रधान सचिव–हाउसिंग बनाया गया था. मायावती के वर्तमान शासनकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों की ज़िम्मेदारियां संभालीं. वह कृषि, वित्त, सिंचाई और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में प्रधान सचिव रहे. असमय काल के गाल में समाने तक वह लखनऊ के अंबेडकर पार्क से संबंधित क़ानूनी मामले को देखने की ज़िम्मेदारी संभाले हुए थे. इस मामले की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले हुई उनकी मौत ने उत्तर प्रदेश सरकार को संदेह के घेरे में डाल दिया है. सूत्रों के मुताबिक़, सूबे के कुछ बाबू लोग उनकी मौत को लखनऊ और नोएडा की ग्रीन बेल्ट की भूमि निजी बिल्डरों को वापस करने के निर्णय के ख़िलाफ़ उनकी असहमति से जोड़कर देखते हैं. ज़ाहिर है कि सिंह की मौत आने वाले कुछ समय तक यहां के बाबुओं को भयभीत करती रहेगी.

ई–पथ पर महाराष्ट्र के बाबू

मुख्यमंत्री अगर तकनीक पसंद हों तो संभव है कि कुछ राज्यों को इससे काफ़ी मदद मिलती हो. आईटी पॉलिसी भले ही दशकों पुरानी बात हो गई हो, लेकिन महाराष्ट्र में बाबू लोग अब इसका उपयोग करेंगे. अपने आधिकारिक ई–मेल पते का इस्तेमाल अब वे अंतर्विभागीय बैठकों के लिए अपने सहकर्मियों से संवाद एवं संपर्क करने में करेंगे.

दरअसल मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ई–गवर्नेंस के विचार को राज्य में बढ़ावा देने की मंशा से इस नियम को सख्ती से लागू करवाना चाह रहे हैं. जानकारों के मुताबिक़, महाराष्ट्र में केवल बीस प्रतिशत बाबू ही अब तक ऑनलाइन हो पाए हैं. लेकिन, यदि चव्हाण अपने निर्णय पर कायम रहते हैं और उनकी चल पाती है तो महाराष्ट्र में बाबू लोग आपसी संचार के लिए ई–मेल का इस्तेमाल कर सकेंगे.

सूत्रों के मुताबिक़, अक़्सर बाबू लोग मीटिंग में न आने की स्थिति में समय से सूचना न मिल पाने का बहाना बनाते हैं. इसके बाद अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.

संसद में चौथी दुनिया

पृष्ठ एक का शेष

इसके संपादक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सांसदों के आवेदन का संज्ञान लेते हुए राज्यसभा सचिवालय ने संतोष भारतीय को नोटिस भेज दिया.

हमने अपने 07–13 दिसंबर 2009 के अंक में रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान शीर्षक से लीड स्टोरी छापी. राज्यसभा के सांसदों को लगता है कि इस लेख से राज्यसभा का अपमान हुआ है और वे अपमानित महसूस कर रहे हैं. इसलिए इन सांसदों ने उपराष्ट्रपति से यह अनुरोध किया है कि चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार और इसके संपादक संतोष भारतीय पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाए, ताकि इस प्रकार के अपमानजनक और आपराधिक कृत्य के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा सके.

इस लेख में संतोष भारतीय ने सच्चाई और निर्भीकता से राज्यसभा की सार्थकता पर सवाल उठाया था.

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सदन में लगातार हंगामा होता रहा. सांसद वेल में जाकर प्रदर्शन और नारेबाज़ी करते रहे. लगभग हर दल के सांसद चाहते थे कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए, पर वे न सरकार को तैयार कर सके और न ही चेयर पर दबाव डाल सके. यही वजह है कि सरकार ने रिपोर्ट को लेकर न तो कोई क़दम उठाए और न ही कोई सकारात्मक बयान दिया. यूं कहें कि राज्यसभा के सांसदों की मांगों को टाल दिया. अब ऐसी राज्यसभा के बारे में क्या कहा जाए, जो कमज़ोर वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रहने के कारण अपनी सार्थकता खोती जा रही है. क्या राज्यसभा के सभापति की यह ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वह रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दे देते. इससे राज्यसभा में लोगों का भरोसा मज़बूत होता. कमीशन द्वारा पहचाने गए क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज के दलितों के लिए आरक्षण का फ़ायदा उठाने का दरवाजा खुल जाता. यही सच संतोष भारतीय ने अपने लेख में लिखा था कि क्या राज्यसभा जिस पर लोकतंत्र को संभालने की ज़िम्मेवारी है, उच्च सदन कहा जाता है, शक्तिहीनों और निर्वीर्य लोगों के बैठने का एक क्लब भर रह गया है. क्या राज्यसभा से जनता को अपना भरोसा ख़त्म कर लेना चाहिए. संतोष भारतीय ने अपने लेख में एक निर्भीक पत्रकार की भूमिका निभाई और सभापति महोदय से यह गुज़ारिश की कि राज्यसभा की गरिमा को बचाने के लिए सदस्यों की मांगों पर ध्यान दीजिए और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश कराइए. लेकिन चौथी दुनिया के इस लेख के लिए लेखक को राज्यसभा सचिवालय ने नोटिस दे दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि लेख से राज्यसभा और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है. सोचने वाली बात यह है कि जो मामला पिछले कई दिनों से राज्यसभा में उठता रहा, जिस पर हंगामा होता रहा, हर दल के लोग मांग करते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, उसी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जब मुलायम सिंह ने लोकसभा में हंगामा किया तो प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देने के लिए बाध्य होना पड़ा कि रिपोर्ट को इस सत्र में पेश किया जाएगा. सभापति जी को यह समझना चाहिए कि यह कैसे हुआ. मुद्दा एक, लेकिन अलग–अलग सदनों में सरकार का जवाब अलग, कार्रवाई अलग. रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट से जुड़े घटनाक्रम से यह डर पैदा होता है कि लोकसभा के मुक़ाबले कहीं राज्यसभा अपनी सार्थकता तो खोती नहीं जा रही है. आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसदों ने 7 दिसंबर को नोटिस सभापति को दिया, आठ दिसंबर को उसे सदन में रखा, जिसके ऊपर सभापति ने संतोष भारतीय और चौथी दुनिया को 9 दिसंबर को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. दूसरी ओर 9 दिसंबर को ही लोकसभा में मुलायम सिंह और कई सांसदों के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को लोकसभा में इसी सत्र में रखने का स्पष्ट आश्वासन दिया. यह कैसा अंतर्विरोध है? रिपोर्ट रखने की मांग करने पर राज्यसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस और उसी अख़बार के आधार पर लोकसभा में मुलायम सिंह की मांग पर प्रधानमंत्री का रिपोर्ट को रखने का आश्वासन. इस घटनाक्रम ने संतोष भारतीय के लेख को सही साबित किया है.

manish@chauthiduniya.com

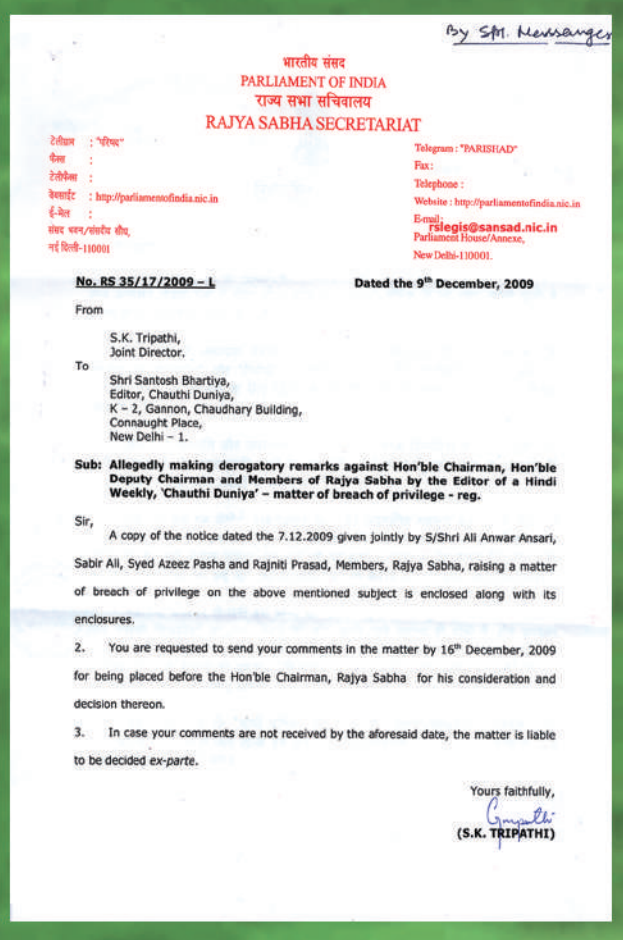

By SM. Messenger

भारतीय संसद
PARLIAMENT OF INDIA
राज्य सभा सचिवालय
RAJYA SABHA SECRETARIAT

टेलीग्राम : "परिषद"
फैक्स :
टेलीफैक्स :
वेबसाईट : http://parliamentofindia.nic.in
ई-मेल :
संसद भवन/संसद सौध,
नई दिल्ली-110001

Telegram : "PARISHAD"
Fax :
Telephone :
Website : http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rslegis@sansad.nic.in
Parliament House/Annexe,
New Delhi-110001.

No. RS 35/17/2009 – L — Dated the 9th December, 2009

From

S.K. Tripathi,
Joint Director.

To

Shri Santosh Bhartiya,
Editor, Chauthi Duniya,
K – 2, Gannon, Chaudhary Building,
Connaught Place,
New Delhi – 1.

Sub: Allegedly making derogatory remarks against Hon'ble Chairman, Hon'ble Deputy Chairman and Members of Rajya Sabha by the Editor of a Hindi Weekly, 'Chauthi Duniya' – matter of breach of privilege - reg.

Sir,

A copy of the notice dated the 7.12.2009 given jointly by S/Shri Ali Anwar Ansari, Sabir Ali, Syed Azeez Pasha and Rajniti Prasad, Members, Rajya Sabha, raising a matter of breach of privilege on the above mentioned subject is enclosed along with its enclosures.

2. You are requested to send your comments in the matter by 16th December, 2009 for being placed before the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha for his consideration and decision thereon.

3. In case your comments are not received by the aforesaid date, the matter is liable to be decided *ex-parte*.

Yours faithfully,

(S.K. TRIPATHI)

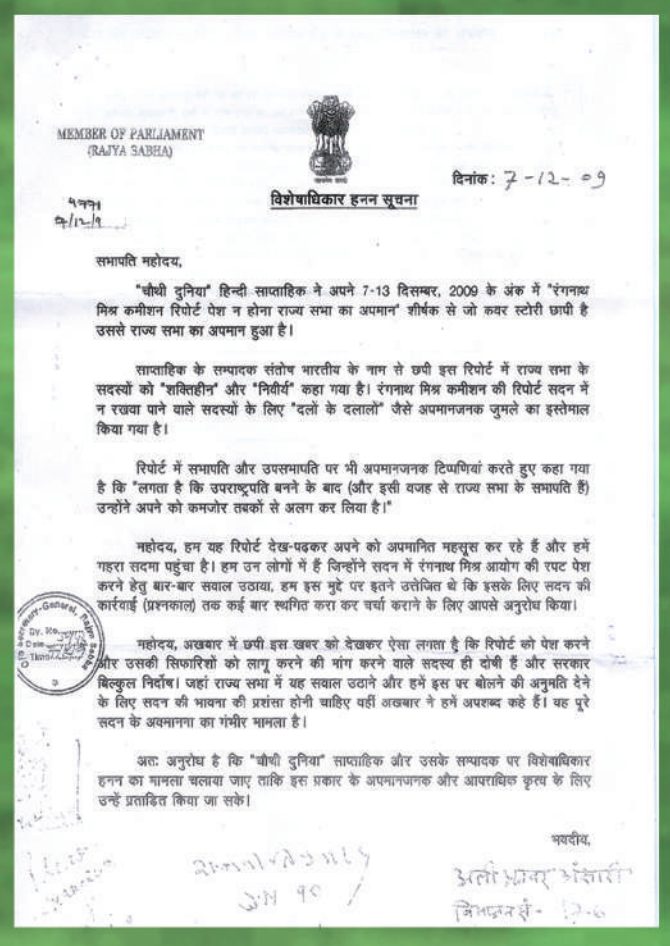

MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

दिनांक : 7-12-09

विशेषाधिकार हनन सूचना

सभापति महोदय,

"चौथी दुनिया" हिन्दी साप्ताहिक ने अपने 7-13 दिसम्बर, 2009 के अंक में "रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट पेश न होना राज्य सभा का अपमान" शीर्षक से जो कवर स्टोरी छापी है उससे राज्य सभा का अपमान हुआ है।

साप्ताहिक के सम्पादक संतोष भारतीय के नाम से छपी इस रिपोर्ट में राज्य सभा के सदस्यों को "शक्तिहीन" और "निर्वीर्य" कहा गया है। रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन में न रखवा पाने वाले सदस्यों के लिए "दलों के दलालों" जैसे अपमानजनक जुमले का इस्तेमाल किया गया है।

रिपोर्ट में सभापति और उपसभापति पर भी अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए कहा गया है कि "लगता है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद (और इसी वजह से राज्य सभा के सभापति हैं) उन्होंने अपने को कमजोर तबकों से अलग कर लिया है।"

महोदय, हम यह रिपोर्ट देख-पढ़कर अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं और हमें गहरा सदमा पहुंचा है। हम उन लोगों में हैं जिन्होंने सदन में रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट पेश करने हेतु बार-बार सवाल उठाया, हम इस मुद्दे पर इतने उत्तेजित थे कि इसके लिए सदन की कार्रवाई (प्रश्नकाल) तक कई बार स्थगित करा कर चर्चा कराने के लिए आपसे अनुरोध किया।

महोदय, अखबार में छपी इस खबर को देखकर ऐसा लगता है कि रिपोर्ट को पेश करने और उसकी सिफारिशों को लागू करने की मांग करने वाले सदस्य ही दोषी हैं और सरकार बिल्कुल निर्दोष। जहां राज्य सभा में यह सवाल उठाने और हमें इस पर बोलने की अनुमति देने के लिए सदन की भावना की प्रशंसा होनी चाहिए वहीं अखबार ने हमें अपशब्द कहे हैं। यह पूरे सदन के अवमानना का गंभीर मामला है।

अतः अनुरोध है कि "चौथी दुनिया" साप्ताहिक और उसके सम्पादक पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाए ताकि इस प्रकार के अपमानजनक और आपराधिक कृत्य के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा सके।

भवदीय,

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सदन में लगातार हंगामा होता रहा. सांसद वेल में जाकर प्रदर्शन और नारेबाज़ी करते रहे. लगभग हर दल के सांसद चाहते थे कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए, पर वे न सरकार को तैयार कर सकेऔर न ही चेयर पर दबाव डाल सके.

चौथी दुनिया
देश का पहला सामाहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 41, 21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश – 201301

फोन न.
संपादकीय 011–23418962
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर लोकसभा में ज़बर्दस्त हंगामा हुआ, नतीजा सकारात्मक रहा और प्रधानमंत्री ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग इसी सत्र में पूरी होगी.

लोकसभा की कार्यवाही में चौथी दुनिया और रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट

दिनांक– 9 दिसंबर, 2009, समय– पूर्वान्ह 11 बजे.

स्पीकर के आने की घोषणा– माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्षा जी...

हाथ जोड़कर अध्यक्षा जी कुर्सी की तरफ़ बढ़ रही हैं. तभी मुलायम सिंह यादव सहित कई सांसद चौथी दुनिया अख़बार की प्रति हवा में लहराते हुए रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पेश करने को लेकर सवाल करने लगते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को सदन में कब पेश करेगी?

स्पीकर : (शोर सुनकर) कृपया बैठ जाइए....

प्रश्न संख्या 281, श्री अमरनाथ प्रधान..

(शोर फिर से शुरू, सदस्यगण चौथी दुनिया अख़बार लहराते हैं)

स्पीकर : कृपया बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए, यह, इसे इस तरह नहीं दिखाएंगे. कृपया शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए. यह इस तरह न दिखाएं. इस तरह से अख़बार न दिखाएं और अपनी जगह ग्रहण कर लें. हम आपको..

तभी मुलायम सिंह फिर कुछ बोलते हैं...

स्पीकर : हां मुलायम सिंह जी, हम आपसे... कृपया बैठ जाइए, यह इस तरह न दिखाएं, इस तरह न दिखाएं, जो भी गंभीर हैं. हम इस पर आपसे बात कर लेंगे. (शोर हो रहा है) जी हां, आपसे बात करेंगे.

मुलायम सिंह : यह कोई मामूली बात नहीं है.

स्पीकर : जी हां, यह कोई मामूली बात नहीं है. इस तरह अख़बार न दिखाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, इस पर बात करेंगे. बैठ जाइए–बैठ जाइए... (दो–तीन बार कहती हैं)

(शोर फिर से शुरू)

स्पीकर : कृपया बैठ जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं., सुषमा जी स्थान ग्रहण कीजिए.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती है.

बाकी लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है. सुनाई नहीं दे रहा है...

(शोरगुल हो रहा है)

स्पीकर : प्रश्नकाल, जी हां इसको हम शून्य प्रहर में उठा लेंगे., सबसे पहले उठा लेंगे.

(शोर– सबसे पहले... सभी के हाथों में चौथी दुनिया की प्रति है)

स्पीकर : कृपया अख़बार न दिखाइए. इस तरह अख़बार न दिखाइए. अख़बार नीचे रख लीजिए.

मुलायम सिंह अख़बार लेकर बोले जा रहे हैं कि रिपोर्ट कैसे लीक हुई, हमें बताया जाना चाहिए.

स्पीकर : मुलायम सिंह जी, आप एक मिनट में अपनी बात कह लेंगे. एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए, अख़बार नीचे रखिए.

मुलायम सिंह : हम चाहते हैं कि वह इसे न बताएं, प्रधानमंत्री जी यहां आकर बता देंगे, हम बैठ जाएंगे.

स्पीकर : क्या चीज़?

मुलायम सिंह : रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट जुलाई में पेश हुई, 2007 में. दो साल से छिपा रही है सरकार. और आज अख़बारों में लाखों में आ गया. अब तक लोकसभा में पेश नहीं हुई. तो यह कोई मामूली बात है अध्यक्षा जी? नहीं. एक हो, दो हो, रोज़ाना यही हो रहा है. लिब्रहान का इसी तरह हुआ. आख़िर क्यों नहीं बहस कराई दो साल तक. यह मैं पूछना चाहता हूं. प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मुझे खुशी है.

पीछे से आवाज़ आती है–कब पेश होगी? और इस पर चर्चा कब कराएंगे? चर्चा अभी हो, पेश करें, तारीख़ बताएं. प्रधानमंत्री जी बताएं कब चर्चा कराएंगे?

स्पीकर : अभी इसकी नोटिस नहीं है. अभी आपने यह बात कह ली. इसके बाद में जो भी उचित होगा..

मुलायम सिंह बात काटते हैं– अभी प्रधानमंत्री... यह ठीक नहीं है.

स्पीकर : अभी तुरंत–तुरंत ऐसे कह देंगे, अचानक में बात हो गई है. बैठ जाइए. आप स्थान ग्रहण कर लीजिए. अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ठीक है आपने अपनी बात कह ली.

फिर शोर मचता है–आश्वासन मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें.

स्पीकर: ठीक है आपने अपनी बात कह ली, अब प्रश्नकाल चलाएं.

मुलायम सिंह सहित बाक़ी लोग शोर कर रहे हैं– आश्वासन मिलना चाहिए. अध्यक्षा जी, ऐसी मनमानी मत कीजिए.

स्पीकर : सबने आपकी बात सुन ली, तुरंत इस चीज पर सरकार की तरफ़ से प्रतिक्रिया नहीं आ सकती. स्थान ग्रहण कीजिए.

मुलायम सिंह : यह ठीक नहीं है, हमें यहां से चलना पड़ेगा.. आप चाहती हैं अध्यक्षा जी, आप चाहती हैं, माने आप चाहती हैं कि हम इसके अंदर आएं. हम इसमें अंदर नहीं आना चाहते, मजबूर करेंगे तो आएंगे..

स्पीकर : ठीक है, आप इसमें नोटिस दे देते.

मुलायम सिंह : हमें बता दीजिए, कब पेश करेंगे इतना ही.

स्पीकर– तुरंत कैसे बता सकते हैं? आपने बता दिया है, उन्होंने (प्रधानमंत्री जी) सुन लिया है.

मुलायम सिंह : आप बात सुनना ही नहीं चाहतीं.

स्पीकर : आप इस तरह से अख़बार लहराइए मत, लहराइए मत...

मुलायम सिंह : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जब ज़ाहिर हो गई है तो कब पेश करेंगे सदन में?

(शोर में सुनाई पड़ता है कि समय निश्चित करके बतलाइए...)

स्पीकर: उन्होंने सुन लिया है.

मुलायम सिंह : आप बताने नहीं देना चाहतीं. यह क्या बात हुई? हम चेयर के लिए ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते.

स्पीकर : क्या नहीं कहना चाहते?

मुलायम सिंह : आप संरक्षण दे रहे हैं?

स्पीकर : नहीं, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं. हमने तो आपको बुलवाया है. अब आप हर चीज में कहेंगे कि तुरंत रिएक्ट करें तो हम कैसे करें? (बात काटते हुए) आपने नोटिस नहीं दिया था मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी...

मुलायम सिंह : रिपोर्ट कब पेश करेंगे?

स्पीकर : अब यह नोटिस नहीं आई थी मेरे पास, आपने कहा यह गंभीर है, हमने आपको बोलने दिया.

मुलायम सिंह : प्रधानमंत्री ने दो बार खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन आपने नहीं माना. यह क्या तरीक़ा है?

स्पीकर : कब?

मुलायम सिंह : आपसे मदद चाहिए मुझे, आप संरक्षण हमें दें.

स्पीकर : आपको हमने इसलिए बोलने दिया, अब आराम से बैठ जाइए और प्रश्नकाल चलने दीजिए.

(पीछे से आवाज़ आती है कि सरकार आश्वासन दे, आश्वासन दे... सब चिल्लाते हैं कि सरकार कोई आश्वासन दे)

क्वेश्चन नंबर 281...

स्पीकर : आप क्यों खड़े हो गए वासुदेव आचार्य जी, आप बैठ जाइए. यस ऑनरेबल मिनिस्टर्स, योर्स फर्स्ट सप्लीमेंटरी प्लीज.....देखिए हमने कई दफ़ा कहा है कि बैठ जाइए. सभी को चुप कराते हुए स्पीकर कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं.

मनमोहन सिंह : Madam, the honourable Mulayam Singh ji and other friends raised this issue. We had no notice but I take note of their sentiments and we will place the report before the house, before the end of the present session. (मैडम, सम्मानीय मुलायम सिंह जी और दूसरे मित्रों ने यह मुद्दा उठाया है. हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं का संज्ञान लिया और हम चालू सत्र की समाप्ति के पहले इसे सदन के पटल पर रखेंगे.)

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सिंगुर मसले पर पश्चिमी बंगाल सरकार और ममता बनर्जी एक बार फिर आमने-सामने हैं. दोनों के बीच शह और मात का खेल जारी है.

नैनो नहीं तो रेल ही सही

बिमल राय

सिंगुर एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. बंगाल की सबसे बड़ी घटना से झुलसे सिंगुर के दिन फिरने वाले हैं. पिछले लोकसभा चुनावों में टाटा की नैनो फैक्ट्री के गुजरात चले जाने से वाममोर्चा को जिस राजनीतिक लाभ की उम्मीद थी, वह तो बदलाव की आंधी में उड़ गया. वाममोर्चा ने ममता की उद्योग विरोधी छवि बनाकर ख़ासकर शहरी मतदाताओं को लुभाने की पुरज़ोर कोशिश की, पर उसे हार का ऐसा सदमा पहुंचा कि ज़मीन विवाद वाली ज़्यादातर परियोजनाओं को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

लेकिन सिंगुर को लेकर शुरू हुए नए खेल में ममता बनर्जी और वाममोर्चा दोनों अपनी-अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं. लोकसभा चुनावों, विधानसभा उपचुनावों और पालिका चुनावों में कामयाबी के बाद ममता ने नई परियोजनाओं के उद्घाटनों और घोषणाओं का सिलसिला चलाया तो सिंगुर भला कैसे छूट सकता था. 997.11 एकड़ में फैला सिंगुर परिसर पक्ष-विपक्ष दोनों को बदहाली की याद दिला रहा था. अब जब 2011 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सभी अपनी-अपनी गोटियां बैठाने में लगे हैं तो वाममोर्चा ने ममता के पाले में यह कहकर गेंद डाल दी कि वह सिंगुर में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने के पक्ष में है. राज्य सरकार ने रेलमंत्री को घेरने के लिए तुरंत हामी भर दी और इस तरह सिंगुर प्रकरण आज एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है.

हालांकि पेंच काफ़ी उलझे हुए हैं. ममता के ऐलान के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर प्रस्ताव के लिए हां किया और उसी मुस्तैदी से रेलवे बोर्ड ने जवाब भी दिया कि वह सिंगुर की 997.11 एकड़ ज़मीन वापस लेकर 400 एकड़ ज़मीन अनिच्छुक किसानों को वापस करना चाहती है. हालांकि राज्य सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन एस एस खुराना को सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया है कि एक बार अधिगृहित हो चुकी ज़मीन वापस नहीं लौटाई जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि सार्वजनिक मक़सद से ली गई भूमि किसी भी हालत में उसके मूल मालिक को नहीं लौटाई जा सकती और उस ज़मीन का दोबारा सार्वजनिक कार्य के लिए ही उपयोग हो सकता है. ममता कहती रही हैं कि 400 एकड़ ज़मीन किसानों से ज़बरन ली गई है. अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो यह साबित हो जाएगा कि ममता का रुख़ सही था.

राज्य सरकार सोच रही है कि वह सिंगुर की क़िस्मत पलट कर अपनी औद्योगिकीकरण की मुहिम का कम से कम एक प्रतीक बचा सकती है. वह कह सकती है कि ममता जो नहीं कर सकीं, उसे हमने कर दिखाया. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ज़मीन विवाद सुलझाना ममता के लिए सिरदर्द हो जाएगा. वैसे देखा जाए तो ममता के दोनों हाथों में लड्डू हैं. वह अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ ज़मीन लौटाने के मामले पर अड़कर इस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकती हैं. इसके अलावा परियोजना में राज्य सरकार को शामिल न करने का विकल्प भी उनके सामने है. तृणमूल ने लालगढ़ अथवा क़ानून व्यवस्था के मामले पर हुई सर्वदलीय बैठकों के बहिष्कार का रवैया अपनाया है और विधानसभा चुनावों से पहले वह हर स्तर पर असहयोग के रुख़ पर अड़ी हैं. अगर ममता इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेती हैं तो उद्योग विरोधी छवि से मुक्त होने में थोड़ी मदद मिलेगी. रेल कोच कारखाने के सहायक कार्य और नौकरियां देकर वह काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगी. हालांकि वह ऐसा कोई क़दम नहीं उठाएंगी, जिससे उनके किसान वोट बैंक पर असर पड़े. हरिपुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध पार्टी इसी वजह से कर रही है. वह इलाक़ा तृणमूल के केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है.

दूसरी तरफ़ ज़मीन को लीज पर लेने वाली टाटा मोटर्स ने कहा है कि पर्याप्त मुआवज़ा मिलने के बाद वह ज़मीन छोड़ सकती है. यह भी एक टेढ़ा मसला है. ज़मीन की पूरी क़ीमत 130 करोड़ रुपये के आसपास है. टाटा और उसके वेंडरों को 300 से 400 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. टाटा ने बाज़ार से जो क़र्ज़ा लिया है, उसका ब्याज भी वह जोड़ ले तो रक़म काफ़ी बड़ी हो जाएगी. एक सूत्र के मुताबिक़, टाटा ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से 1500 करोड़ रुपये मांगे हैं, लेकिन इतनी रक़म देना उसके वश की बात नहीं है. कुल भूमि में से 645.67 एकड़ टाटा के पास और 225 एकड़ कार के पुर्ज़े बनाने वाली कंपनियों के मालिकों के पास है. बाक़ी 97 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार के विभिन्न निकायों की है. इन सबसे निपटना आसान नहीं है.

अब यह राज्य सरकार का सिरदर्द है कि वह टाटा को नुक़सान का एक हिस्सा ख़ुद उठाने के लिए तैयार कर पाती है या नहीं. नुक़सान की भरपाई किए बिना पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम टाटा को लीज रद्द करने की नोटिस नहीं दे सकता. अभी सरकार टाटा मोटर्स से बात करना ज़रूरी नहीं समझती. सरकार पहले रेलवे बोर्ड से सफ़ाई चाहती है कि वह कोच कारखाना उसके साथ मिलकर संयुक्त उद्यम में लगाना चाहता है या केवल अपने मालिकाने में. एक पेंच यह भी है कि हर्ज़ाना देने के बाद रेलवे ज़मीन की नई क़ीमत, जो ज़ाहिर है कि बढ़ जाएगी, देने के लिए राजी होगी या नहीं? राज्य सरकार उस ज़मीन पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ मिलकर 1600 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना लगाने का प्रस्ताव लाई थी. कंपनी के कुछ अधिकारियों ने सिंगुर जाकर मुआयना भी किया, पर बात नहीं बनी. भेल ने इस परियोजना को लाभप्रद नहीं माना.

बाधाएं क़ानूनी भी हैं. सुप्रीम कोर्ट में सिंगुर विवाद पर चार अवकाश याचिकाएं लंबित हैं और इनका निपटारा हुए बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. वाममोर्चा ने सिंगुर की गुगली फेंकी है. अब देखना यह है कि ममता आउट होती हैं या इसे रनों में बदल पाने में कामयाब हो जाती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

बैगा आदिवासियों के नाम पर करोड़ों की लूट

संध्या पांडे

करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश में आदिवासी बैगा जनजाति अभी भी भुखमरी की शिकार है. एक अनुमान के अनुसार, सरकार की ओर से अब तक जितना अनुदान बैगा जनजाति के कल्याण कार्यों के लिए मिला है, यदि उसे बैगा परिवारों में बांट दिया जाता तो प्रत्येक परिवार को लगभग साढ़े सात लाख रुपये अपनी हालत सुधारने के लिए सीधे मिल सकते थे. सरकारी तंत्र ने बैगाओं के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पिछले डेढ़ दशक के दौरान जमकर लूटी.

आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सामान्य बजट से हर साल करोड़ों रुपये ख़र्च करती हैं. इसके अलावा बैगा विकास प्राधिकरण को केंद्र ने करोड़ों रुपये की सहायता अलग से दी है, लेकिन इसके बावजूद बैगाचक का न तो कोई विकास हुआ है और न ही बैगाओं की हालत में कोई सुधार दिखाई देता है. आजादी के बाद से वर्ष 2002 तक केंद्र एवं राज्य सरकार के आदिवासी बजट और बैगा विकास प्राधिकरण के लिए प्राप्त केंद्रीय सहायता की कुल धनराशि 95 अरब 93 करोड़ रुपये थी. यह पूरा धन बैगाचक के विकास और बैगाओं के सामाजिक- आर्थिक कल्याण के लिए ख़र्च बताया जाता है, लेकिन बैगाचक और बैगाओं की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ.

मध्य प्रदेश के पांच ज़िलों में बैगा प्राधिकरण कार्यरत हैं. मंडला प्राधिकरण में 249 गांव हैं, जिनमें 23509 बैगा निवास करते हैं. डिंडौरी ज़िले में 217 गांवों में 21239, शहडोल ज़िले में 238 गांवों में 35120, उमरिया ज़िले के 248 गांवों में 37600 और बालाघाट ज़िले में 191 गांवों में 13957 बैगा निवास करते हैं. इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,31,425 बैगा हैं. लगभग डेढ़ लाख बैगा छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों में रहते हैं. सरकार ने इन बैगाओं के उत्थान और विकास के लिए जो धन सीधे ख़र्च होना बताया है, यदि उसे सीधे बैगाओं में बांट दिया जाता तो हर परिवार के हिस्से में 7.30 लाख रुपये आते. लेकिन सरकार के इरादे चाहे जितने पवित्र क्यों न हों, सरकारी तंत्र ने जिस प्रकार काम किया, उससे बैगाओं के कल्याण और विकास का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के हवन में स्वाहा हो गया.

चौथी दुनिया ने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बैगाओं की स्थिति का जायज़ा लिया. बालाघाट ज़िले के हर्राटोला, गुदमा, कुमादेही और महुरदा गांव में तो बैगा जनजाति भगवान भरोसे ही रहती है. सरकार की ओर से इन गांवों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं. पास ही विद्युत लाइन और खंभे हैं, लेकिन गांव में बिजली का एक भी कनेक्शन नहीं है. सरकार ने ग्रामीण रोज़गार गारंटी समेत कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन गांवों में बैगाओं को आज भी मध्ययुगीन अर्थ व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है. यहां के बैगा वनोपजों के संग्रह और मोटे अनाज एवं साग-सब्जी की खेती के ज़रिए अपना पेट पालते हैं. कभीकभार वन विभाग में बैगाओं को कुछ दिनों की दैनिक मज़दूरी मिल जाती है तो वे स्वयं को धन्य समझने लगते हैं. मंडला ज़िले में आदिवासी उपयोजना के तहत बैगाओं के लिए कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू किया गया है, लेकिन नौकरशाही की सुस्ती और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उक्त योजनाओं का लाभ बैगाओं को नहीं मिल पाता है. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के किसी भी सरकारी कार्यक्रम से बैगाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता. धनगांव की 70 वर्षीय वृद्धा बस्तो बैगा बताती हैं कि सुपात्र होते हुए भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेंशन के लिए ज़रूरी काग़जात तैयार करने और पेंशन मंजूर करने के लिए सरकारी कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगते हैं. ग़रीबी के कारण वह रिश्वत नहीं दे सकती हैं, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट पाल रही हैं. कलिराम बैगा का कहना है कि सरकार ने ग्रामीण मज़दूरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा और मुआवज़े की योजना लागू की है, लेकिन एक दुर्घटना में एक आंख पूरी तरह खो देने के बाद भी उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं.

सरकार की जनश्री बीमा योजना के तहत जन्म लेते ही प्रत्येक बैगा का 50 से 75 हज़ार रुपये का बीमा हो जाता है, लेकिन इस योजना का लाभ किसे मिल रहा है, यह तो सरकारी कर्मचारी ही बेहतर जानते हैं. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना और ग़रीबों की मुफ्त चिकित्सा के सरकारी कार्यक्रम का जमकर प्रचार-प्रसार हुआ, लेकिन कोयलीबाई बैगा बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों से पेट में ट्यूमर के कारण वह ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं, पर सरकारी अस्पताल में उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है. डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगते हैं. पैसा न मिलने पर वे जबलपुर जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सलाह देते हैं. दूसरी ओर सरकार के बैगा विकास प्राधिकरण और आदिम जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न सेवाओं में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की माली हालत देखकर लगता है कि बैगाओं का तो नहीं, लेकिन उनका ज़रूर कल्याण और विकास हुआ है. यह एक जांच का विषय है.

feedback@chauthiduniya.com

तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को पूरा यक़ीन है कि चीन में एक दिन लोकतंत्र ज़रूर आएगा, क्योंकि वहां की स्थितियां लगातार बदल रही हैं. लोग मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं.

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट

सरकार को घेरने की तैयारी

चौथी दुनिया अख़बार में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने ख़ासी एकजुटता दिखाई है. आसार इस बात के हैं कि आने वाले दिन सरकार के लिए भारी साबित हो सकते हैं.

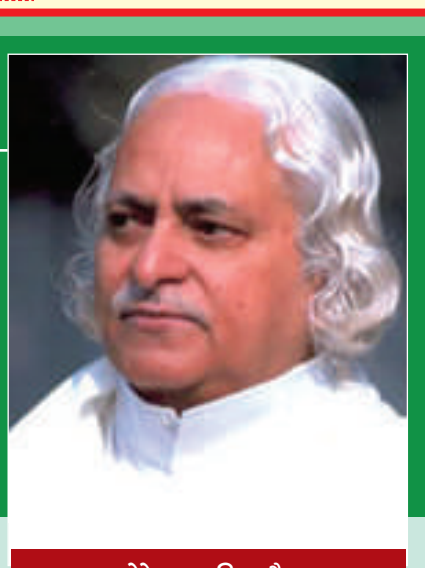

प्रोफेसर जाबिर हुसैन

मुलायम सिंह यादव

अली अनवर

अमर सिंह

एन के सिंह

रूबी अरुण

राजनीतिक दलों में उबाल आ चुका है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं को संसद में पेश करने की मांग को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं. समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने वाली है. भाजपा, जदयू, राजद एवं लोजपा के सांसद भी संसद और चौथी दुनिया अख़बार के ज़रिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. इस मसले पर कोहराम मचा हुआ है, पर सरकार ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है. लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट लीक होने के मुद्दे पर चौतरफ़ा घिरी यूपीए सरकार अब रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट चौथी दुनिया में छप जाने के बाद सांसत में पड़ी दिख रही है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि सरकार तो इस कमीशन की अनुशंसाओं पर ग़र्द डाल चुकी थी. अगर चौथी दुनिया ने इस रिपोर्ट को नहीं छापा होता तो यूपीए सरकार देश के ग़रीब दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों के हक़ों के साथ खिलवाड़ करने का पूरा मन बना चुकी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौथी दुनिया अख़बार और इसके संपादक संतोष भारतीय ने देश की राजनीतिक पार्टियों को सरकार के ख़िलाफ़ एक पुख्ता आधार दे दिया है. इसकी बिना पर हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं पर न सिर्फ़ संसद में बहस कराए, बल्कि उन्हें लागू भी करे. समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ख़ासे उत्तेजित हैं. इस मसले पर वह यूपीए सरकार पर बरस पड़ते हैं. कहते हैं कि सरकार ने कमीशन का गठन दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया. दरअसल सरकार यह चाहती ही नहीं कि देश का यह कमज़ोर तबका तरक्की करे या आगे बढ़े. यूपीए सरकार सिर्फ़ अपने मतलब का खेल, खेल रही है. अमर सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2010 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार अपने वोट बैंक की चिंता में कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं कर रही है. अमर सिंह सवाल करते हैं कि जब दूसरी जाति के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो मुसलमानों को बाहर क्यों रखा जा रहा है? सरकार आरक्षण के मसले पर दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है? सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा.

ज़ाहिर है, चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद सरकार पर इसे संसद में पेश करने को लेकर दबाव बेहद बढ़ चुका है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफ़ारिशें ऐसी हैं, जिन पर आसानी से अमल नहीं हो सकता. कमीशन ने जो सिफ़ारिशें दी हैं, उनके मुताबिक़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में सभी कैडर और ग्रेड के पदों पर अल्पसंख्यकों को 15 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा. शिक्षा में भी यह आरक्षण 15 फ़ीसदी होगा. इसमें दस फ़ीसदी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा. जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार सामान्य मेरिट लिस्ट में होंगे, वे आरक्षण सीमा से बाहर होंगे. मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा.

राजद के राज्यसभा सांसद जाबिर हुसैन कहते हैं कि सरकार जानबूझ कर कमीशन की सिफ़ारिशों पर चर्चा करने से बच रही है. सरकार को पता है कि इस पर चर्चा होते ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उसे घेर लेंगी. आयोग की रिपोर्ट पिछले दो सालों से धूल खा रही है, पर सरकार ने जानबूझ कर इसे हाशिए पर डाल दिया है. सरकार के लिए कमीशन की रिपोर्ट गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे वह न निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है. सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का मसला बेहद ही संवेदनशील है.

जदयू के राज्यसभा सांसद एन के सिंह भी जाबिर हुसैन की बातों पर सहमति जताते हैं. वह कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश पर हुआ बवाल सरकार भूली नहीं है. वह रिपोर्ट टेबल करने के पहले सभी पहलुओं का नफ़ा-नुक़सान आंक लेना चाहती है. अगर सरकार अल्पसंख्यकों को आरक्षण देती है तो उसे बहुसंख्यकों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी. और, अगर ज़्यादा दिनों तक सरकार इस मसले को लटकाती है तो अल्पसंख्यकों का गुस्सा उस पर उतर सकता है. ऐसी हालत सरकार के लिए बेहद दुरूह है.

बात बिल्कुल सही है. फ़िलहाल सरकार इस स्थिति में तो है ही नहीं कि वह कमीशन की रिपोर्ट में ज़्यादा बड़ा फेरबदल किए बग़ैर उसे लागू करा सके. हालांकि इसी साल के लोकसभा चुनाव के दरम्यान अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने यह कहा था कि वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की आरक्षण नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है, पर अब सरकार अलग राग अलाप रही है. कांग्रेस प्रवक्ता जयंती नटराजन कहती हैं कि हमें पूरे मुद्दे की जांच करनी होगी. हम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते, जो क़ानूनन नामुमकिन हो.

चौथी दुनिया अख़बार को राज्यसभा में लहराकर इस मसले को ज़ोर-शोर से उठाने वाले जदयू सांसद अली अनवर अंसारी और राजद सांसद राजनीति प्रसाद का मानना है कि सरकार के अलावा विपक्षी दलों में बैठे कुछ ऐसे मुस्लिम सांसद हैं, जो नहीं चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू हो. उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर किसी भी तरह रिपोर्ट की अनुशंसाएं लागू हो गईं और मुसलमानों को आरक्षण मिल गया तो वे पढ़-लिखकर तरक्की कर जाएंगे. फिर उनके बीच धर्म आधारित सियासत का गंदा खेल नहीं खेला जा सकता. वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कमाल अख्तर दावे के साथ कहते हैं कि चाहे राजनीतिक पार्टियां जितना भी ज़ोर लगा लें, रिपोर्ट की अनुशंसाएं सरकार लागू करने वाली नहीं. क्योंकि, जब इस मसले पर बहस होगी तो सवाल यह भी उठेगा कि आख़िर ऐसी क्या वजह रही कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मुसलमान और ईसाई इतने पिछड़े हुए हैं? तब ठीकरा कांग्रेस के सिर ही फूटेगा. ज़ाहिर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ऐसी तोहमत नहीं लेना चाहेगी. फिर भी विपक्षी दलों की यह पुरज़ोर कोशिश होगी कि सरकार को इस मसले पर इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे संसद में इस पर बहस करानी ही पड़े.

बहरहाल, सरकार के ख़िलाफ़ इस मुद्दे पर जो राजनीतिक गोलबंदी दिख रही है, उस लिहाज़ से लिब्रहान कमीशन पर चर्चा होने के बाद रंगनाथ कमीशन पर संसद में हंगामा होने के पूरे आसार हैं. यक़ीनन इसका सेहरा चौथी दुनिया के माथे ही बंधता है.

ruby@chauthiduniya.com

दलाई लामा को चीन में लोकतंत्र आने की उम्मीद

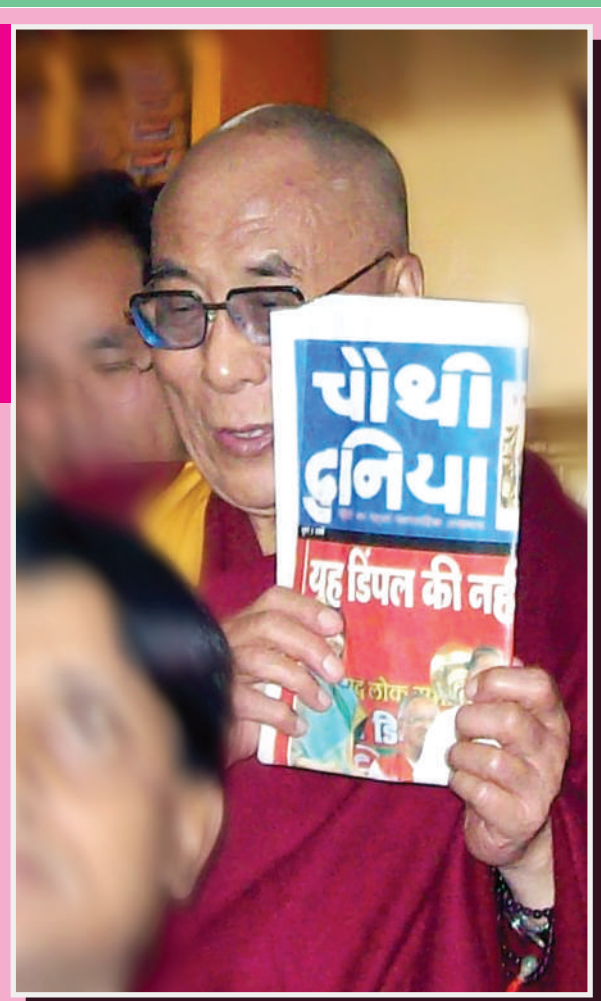

राजकुमार शर्मा

तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को पूरी उम्मीद है कि चीन में लोकतंत्र के आगमन में अब ज़्यादा देर नहीं है. वह कहते हैं कि गांधीजी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम पूरे चीन में लोकतंत्र लाना चाहते हैं. पूरा विश्वास है कि पूरे चीन में लोकतंत्र के पक्ष में जो हवा चल रही है, उसे किसी भी हालत में वहां की सत्ता के शिखर पर बैठे लोग रोक नहीं पाएंगे. दलाई लामा ने कहा कि अमेरिका की तिब्बत के प्रति प्रतिबद्धता की बात पर उन्हें किसी तरह की आशंका नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तिब्बत की स्वायत्तता का संरक्षण करते हैं. दलाई लामा पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैलोडगंज के चुगंलाखंग बौद्धमठ में आईएफडब्ल्यूजे के बैनर तले पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

दलाई लामा के अनुसार, ओबामा ने अपने चुनाव के समय भी उनसे बात कर तिब्बत की स्वायत्तता का समर्थन किया था. उन्होंने ओबामा के चीन जाने से पहले उनसे इसलिए मुलाकात नहीं की, ताकि चीन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो जाए. उनसे मिलकर जाने पर इस बात की आशंका थी कि चीन अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई भी कड़ा रुख अपना सकता था. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल ओबामा से उनकी मुलाकात ज़रूर होगी. दलाई लामा कहते हैं, हमने चीन के संविधान के अंतर्गत रहकर ही तिब्बत की स्वायत्तता की मांग की है, लेकिन चीन के मन में भय है, इसलिए वह हमें अलगाववादी के रूप में प्रचारित करता रहता है. हमारे प्रयास के ठोस नतीजे अभी तक भले ही न निकले हों, लेकिन आज स्थितियां पूरे चीन में बदल रही हैं. जनता का भी मन बदल रहा है. वहां के हजारों शिक्षकों, पत्रकारों, लेखकों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों ने हमसे मिलकर बदलाव की बात कही है. चीन की वर्तमान शासन व्यवस्था काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जनता अब बदलाव का मन बना रही है. लोग चाहते हैं कि मीडिया एवं न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और लोकतंत्र क़ायम हो.

दलाई लामा ने बताया कि तिब्बत की स्वायत्तता के सवाल पर अब तक आठ बार उनकी चीन से वार्ता हो चुकी है. वह कहते हैं कि मैं तो गांधीजी के जीवन के एक छोटे से भाग अहिंसा के मार्ग का अनुयायी हूं. उन्होंने नेल्सन मंडेला की भी सराहना की और कहा कि उनकी पहली प्रतिबद्धता सद्भावना एवं अहिंसा के सिद्धांत को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना है, क्योंकि इसके बिना न कोई लक्ष्य हासिल हो सकता है और न ही विश्व में शांति कायम हो सकती है.

आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दलाई लामा ने कहा कि इसका मुक़ाबला जनता को शिक्षा एवं जनजागरण के हथियार से लैस करके अहिंसा के मार्ग को अपनाने के आत्मबल द्वारा ही किया जा सकता है. वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सीमाएं महत्वहीन होती जा रही हैं. पूरा विश्व एक देश के रूप में विकसित हो रहा है और सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं. ऐसे में अकेले रहकर कोई महान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, धर्मशाला और भारत हमारे घर जैसा है. हमने भारत में 50 वर्ष रहकर लोकतंत्र को पलते-बढ़ते देखा है. हमने यहीं रहकर सीखा कि लोकतंत्र क्या है? इसी से प्रभावित होकर हमने अपने स्तर पर 2001 से निर्वासित तिब्बतियों की भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया है.

feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों को चीनी हथियार!

भारत के नक्सलियों को चीन द्वारा घातक हथियार एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस बात का ख़ुलासा तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री प्राफ़ेसर सेमडोंग रिनपोछे ने किया. 1959 में चीन के तिब्बत पर हमले के समय दलाई लामा के साथ भारत आए बौद्ध दर्शन के प्रचारक प्रोफ़ेसर रिनपोछे ने आतंकवाद के पोषक राष्ट्रों की तुलना उन मूर्खों से की, जो उसी डाल को काटते हैं, जिस पर वे बैठे होते हैं. उन्होंने भारतीय बाज़ार में चीन के माल की बिक्री को लघु उद्योगों के लिए ख़तरा बताते हुए सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया.

विद्यालयों को यातनागृह बनने से बचाने के लिए एक कारगर सामाजिक पहल बहुत ज़रूरी है. इस दिशा में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और सरकार को आगे आना चाहिए.

इस भटकाव की वजह क्या है

महेंद्र अवधेश

अनुशासन के नाम पर छात्रों के प्रति शिक्षकों का रवैया कभी-कभी ख़ासा अमानवीय हो जाता है. हाल की कुछ घटनाएं इसका प्रमाण हैं. आख़िर क्या हो गया है हमारे गुरुजनों को?

बीती 15 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने एक ऐसे शिक्षक को एक लाख रुपये मुआवजे की सजा से दंडित किया, जिसने आज से 12 वर्ष पहले एक छात्र को पूरे दिन निर्वस्त्र खड़ा रखा था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने अपने फैसले में उक्त शिक्षक को निर्देश दिया कि वह बतौर मुआवजा एक लाख रुपये पीड़ित छात्र को अदा करे. घटना 25 मई 1997 की है. दिल्ली के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पी सी गुप्ता ने अपनी कक्षा के एक तेरह वर्षीय छात्र को विद्यालय के तालाब में नहाते हुए पकड़ लिया. गुप्ता उस छात्र के कृत्य से इतने नाराज हुए कि उन्होंने पहले उसे जमकर पीटा, फिर पूरे समय तक विद्यालय में निर्वस्त्र खड़ा रखा. बाद में अभिभावकों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मुकदमा चला और 19 मार्च 2007 को निचली अदालत ने गुप्ता को एक वर्ष की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी. गुप्ता इन दिनों अपनी सजा काट रहे थे. उन्होंने निचली अदालत के उसी फैसले को चुनौती दी थी. उनकी अपील के आलोक में न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने अपना ताजा फैसला दिया है. अच्छे व्यवहार की शर्त पर गुप्ता को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने से पहले न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने उनकी हरकत की कड़े शब्दों में निंदा भी की.

पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं अक्सर ही सुनने-पढ़ने को मिलती रहती हैं, जिनमें मामूली सी गलती पर शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को बड़ी बेरहमी से दंडित किए जाने की बात सामने आती है. ऐसी घटनाएं जनसामान्य को सहज ही चिंतित कर देती हैं. स्वाभाविक है, अभिभावक या माता-पिता बच्चों को बहुत विश्वास के साथ विद्यालय भेजते हैं, उनके भविष्य और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहते हैं. लेकिन, जब ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो उनका सारा विश्वास डगमगा जाता है. पिछले एक वर्ष के अंदर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं. 7 अगस्त 2009 को फरीदाबाद में एक इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने बारहवीं कक्षा के छात्र मनदीप को पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. पिटाई से मनदीप के हाथ की नस कट गई और उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा. इसी तरह 25 जुलाई 2009 को कानपुर में कक्षा नौ के छात्र नमन प्रजापति को उसके शिक्षक ने ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि उसके कान का पर्दा ही फट गया.

ऐसी घटनाएं हमारी उस चिंता को और गहरा करती हैं, जो गत वर्ष 24 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा आठवीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तोड़ने, उससे पहले टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा सातवीं कक्षा की छात्रा पर तमाचों की बौछार कर उसके कान का पर्दा फाड़ने, ग्रेटर नोयडा के सिरसा स्थित ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल की शिक्षिका द्वारा चौथी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से पीटे जाने और फरीदाबाद जिले के गौंछी गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा के चेहरे पर उसकी शिक्षिका द्वारा ये लड़की पढ़ नहीं सकती लिखकर पूरी क्लास में घुमाने से उपजी थी. फरीदाबाद का मनदीप उन पांच छात्रों में शामिल था, जिन्हें कुछ दिन पूर्व एक मामूली शरारत की वजह से कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था. माफी मांगने गए मनदीप को वाइस प्रिंसिपल ने इस कदर पीटा कि उसके हाथ की नस ही कट गई. खबर पाकर मौके पर पहुंचे उसके पिता ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया. शिकायत करने पर कॉलेज प्रबंधन ने उल्टे मनदीप को ही कुसूरवार ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया.

कानपुर की घटना में नमन का अपराध मात्र इतना था कि वह अपने शिक्षक मयंक पाल राठौर से बिना अनुमति लिए पानी पीने चला गया था. जब इस बात की शिकायत

अभिभावकों ने प्रिंसिपल से की तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि बच्चे का दाखिला किसी दूसरे विद्यालय में करा लीजिए. यानी दोषी शिक्षक बगैर किसी जांच-कार्यवाही के साफ बरी निकल गया. राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र गर्वित को उसके अशोक चौहान सर ने डंडे से इस कदर पीटा कि उसका हाथ टूट गया. पिटाई से बेहाल गर्वित घर पहुंचते ही बेहोश हो गया. मां मंजू गोला उसे लेकर तुरंत बाड़ा हिंदूराव अस्पताल भागीं. खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने संबंधित शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. बाद में पता चला कि गर्वित का कुसूर यह था कि वह अपने उन सीनियर सहपाठियों के साथ खड़ा था, जिन्होंने आरोपी शिक्षक को कुछ देर पहले अपशब्द कहे थे. टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वाली घटना में लव दुआ और प्रकृति दुआ नामक भाई-बहन यहां क्रमश: पहली व सातवीं कक्षा के विद्यार्थी थे. एक दिन प्रिंसिपल ने उनकी मां को बुलाकर बच्चों की शिकायत की. इसी दौरान प्रिंसिपल को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने प्रकृति की कमीज का कॉलर और बाल पकड़कर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी. पिटाई के बाद छात्रा की श्रवण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव हुआ. डॉक्टरी जांच में पता चला कि उसके कान का पर्दा ही फट चुका है. अभिभावकों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. लिहाजा उन्होंने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया.

सिरसा (ग्रेटर नोयडा) स्थित ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा आयुष सेन को उसकी शिक्षिका ममता ने लोहे के स्केल से बुरी तरह पीटा था. वजह, आयुष ने लंचटाइम में अपने सहपाठियों से गप्प लड़ाने की जुर्रत कर डाली थी. घायल आयुष को अस्पताल ले जाना पड़ा. बाद में उसकी मां ने कासना थाने में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. गौंछी (फरीदाबाद) वाले प्रकरण में शिक्षिका संगीता की करतूत पीड़ित छात्रा के डर के चलते शायद दबी ही रह जाती, लेकिन उसकी चचेरी बहन ने घर आकर पूरी कहानी परिवारवालों को बता दी. यहां छात्रा का अपराध सिर्फ इतना था कि वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाई थी. जानकारी मिलते ही गांववालों ने विद्यालय को घेर लिया. छात्रा के पिता ने प्रधानाचार्य से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न होने से मामला बिगड़ गया और फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया. राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आएदिन ऐसी घटनाएं सुनने-पढ़ने को मिलती रहती हैं. इससे अभिभावकों के दिल हमेशा आशंकित रहते हैं कि कब कौन सा शिक्षक-शिक्षिका उनके बच्चे के साथ बदसलूकी कर गुजरे. कई घटनाएं तो ऐसी भी हो चुकी हैं कि मामूली सी गलती पर बच्चे को ऐसी सजा दे दी गई कि अभिभावकों ने भयवश उसे स्कूल से ही निकाल लिया. सच तो यह है कि गली-मुहल्ले में खुलने वाले कथित मांटेसरी पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएं अपनी अल्प, अपर्याप्त और सीमित आमदनी के चलते अक्सर अनेक दिक्कतों से दो-चार रहते हैं. उन्हें अपनी काबिलियत का सही मोल न मिल पाने की कुंठा वक्त-बेवक्त सताती रहती है.

लेकिन, इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि नियोजकों के प्रति उपजा गुस्सा किसी मासूम पर उतारा जाए. सरकारी स्कूलों के शिक्षक तो इसके अपवाद हैं. उन्हें पर्याप्त वेतन और सुविधाएं हासिल हैं, बावजूद इसके वे भी संवेदनशून्य होते जा रहे हैं. असल चिंता तो यह है कि आखिर शिक्षकों को होता क्या जा रहा है? उनमें हिंसा कैसे और क्यों घुसपैठ करती जा रही है? कहीं उनके प्रशिक्षण में तो कोई कमी नहीं रह जाती अथवा बाल मनोविज्ञान न समझ पाने की खीझ उन्हें हिंसक व अमानवीय बनने को मजबूर कर रही है? वजह चाहे जो भी हो, हालात बहुत गंभीर हैं. बच्चों के मन में स्कूल और शिक्षकों के प्रति जो भय घर करता जा रहा है, वह बहुत चिंतनीय है. इसका इलाज कानूनी कार्यवाही, निलंबन या बदले में मार-पिटाई से संभव नहीं है. बल्कि, इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर ही कोई सार्थक समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों और शिक्षा के मंदिरों की गरिमा बरकरार रहे तथा अभिभावकों के लगातार दरकते विश्वास को तार-तार होने से बचाया जा सके.

mahendra@chauthiduniya.com

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक पेंटल अपनी नियुक्ति से जुड़े विवाद में फंस गए हैं. उनकी नियुक्ति को अवैध बताने का आरोप कहीं बाहर से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ही एकेडमिक काउंसिल की तरफ़ से लगाए जा रहे हैं.

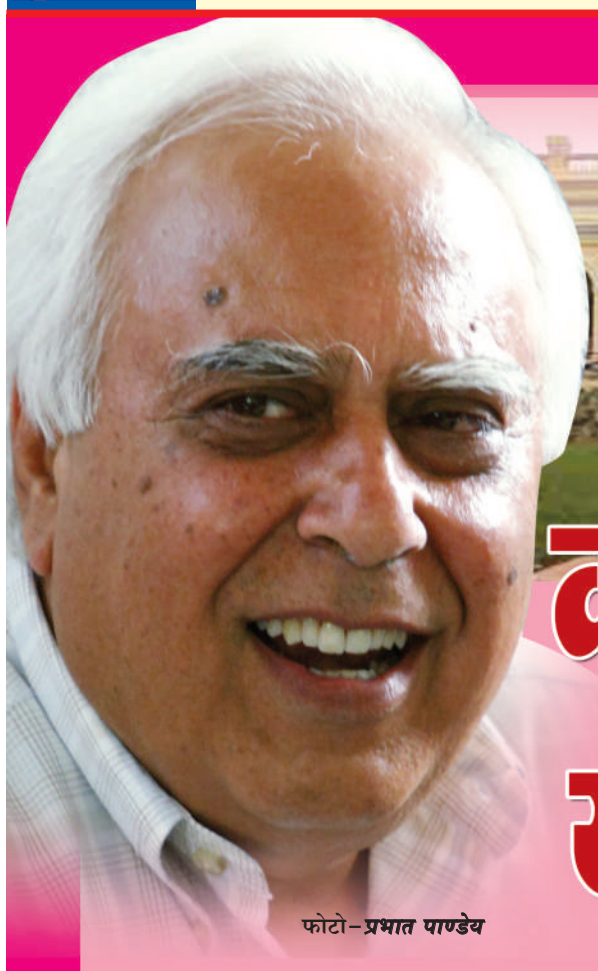

फोटो–प्रभात पाण्डेय

कपिल सिब्बल जी, यह क्या हो रहा है!

दीपक पेंटल, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय

शशि शेखर

एक कहावत है, अंत भला तो सब भला. लेकिन देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति के लिए मानो यह कहावत झूठी साबित होने जा रही है. अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के अंतिम वर्ष में डीयू के कुलपति दीपक पेंटल अपनी नियुक्ति से जुड़े विवाद में फंस गए हैं. कुलपति पर उक्त आरोप कहीं बाहर से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ही एकेडमिक काउंसिल की तरफ़ से लगाए जा रहे हैं और बाक़ायदा इसके काग़ज़ी सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं. चौथी दुनिया के पास वे सभी दस्तावेज़ मौजूद हैं, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नियमों की अनदेखी की और अपने चहेते दीपक पेंटल को कुलपति बनवा दिया.

इस प्रकरण का सबसे अहम तथ्य यह है कि दीपक पेंटल की नियुक्ति विजिटर के हस्ताक्षर बिना हुई है. डीयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसके विजिटर होते हैं राष्ट्रपति. डीयू एक्ट 1922 के मुताबिक़, कुलपति की नियुक्ति विजिटर करते हैं. दीपक पेंटल की नियुक्ति से संबंधित पूरी फ़ाइल की जांच के दौरान ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें कुलपति नियुक्त करने के लिए विजिटर ने अपने हस्ताक्षर से कोई आदेश जारी किया हो. अलबत्ता, तत्कालीन राष्ट्रपति के सचिव पी एम नायर ने ज़रूर अपना हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र 30 अगस्त 2005 को मानव संसाधन मंत्रालय को भेजकर पेंटल की कुलपति पद पर नियुक्ति की सूचना दी थी. हालांकि ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि यह पत्र अनाधिकारिक (अन–ऑफिसियल) तौर पर लिखा गया था. मज़े की बात यह है कि इसी पत्र के आधार पर एक सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के अवर सचिव एस एस महलावत पेंटल की नियुक्ति की सूचना डीयू रजिस्ट्रार को देते हैं, एक सितंबर को ही रजिस्ट्रार नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना भी जारी करते हैं और पेंटल इसी दिन अपना पदभार भी संभाल लेते हैं. यानी यह सब कुछ चट मंगनी, पट ब्याह की तर्ज़ पर होता गया. मज़े की बात यह है कि इस नियुक्ति की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सर्वेसर्वा, जो कि उप राष्ट्रपति होते हैं, को भी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई. पेंटल ने पदभार ग्रहण करते वक़्त सिर्फ़ एक पत्र रजिस्ट्रार के नाम से यह अनुरोध करते हुए भेजा कि इसे अधिसूचित कर दिया जाए.

ग़ौरतलब है कि डीयू एक्ट की धारा 11–एफ के मुताबिक़, कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा की जाती है. विजिटर एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें तीन सदस्य होते हैं और इन्हीं तीनों में से किसी एक को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. यह कमेटी कुलपति पद के लिए आए आवेदनों में से नामों का चयन करती है और विजिटर के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजती है. 2005 में डीयू में कुलपति की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही एक कमेटी का गठन किया गया. रोमिला थापर एवं डॉ. आबिद हुसैन सदस्य बनाए गए और अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए पूर्व न्यायाधीश पी एन भगवती. विजिटर द्वारा कुलपति नियुक्त किए जाने का मतलब यह है कि कमेटी जिन नामों को भेजेगी, उनमें से किसी एक नाम पर विजिटर अपनी मुहर लगाएंगे. ज़ाहिर है, नियुक्ति के लिए जारी पत्र या किसी आदेश पर कहीं न कहीं विजिटर के हस्ताक्षर भी होंगे, लेकिन इस मामले में तो कुलपति की नियुक्ति एक आईएएस अधिकारी के हस्ताक्षर से ही हो गई. चौथी दुनिया ने इस मामले की तफ़्तीश के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एवं रामजस कॉलेज के प्रोफेसर धनीराम से बातचीत की. उनका कहना था कि यह सब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है. प्रो. धनीराम राष्ट्रपति से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी करते हैं. वह बताते हैं कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो कुलपति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए.

दरअसल 2005 में जब डीयू के कुलपति की नियुक्ति की जानी थी, तभी से यह पूरा मामला संदेह के घेरे में आता चला गया. चौथी दुनिया के पास कुलपति की नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज़ मौजूद हैं. इन दस्तावेज़ों से यह साफ़ पता चलता है कि कैसे कुछ आवेदकों (कुलपति पद के लिए) को लेकर चयन समिति और उसके अध्यक्ष के मन में दुराग्रह था. इसकी एक मिसाल हैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता. प्रोफेसर गुप्ता का नाम भी कुलपति पद की दौड़ में था, लेकिन उनके नाम पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि चयन समिति के अध्यक्ष पी एन भगवती का मानना था कि प्रोफेसर गुप्ता ने एक पत्रिका में छपे अपने लेख में कुछ राजनीतिक हस्तियों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. अब यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यूपीए के शासनकाल में ऐसी किस राजनीतिक हस्ती के बारे में टिप्पणी करना किसी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है. जबकि दीपांकर गुप्ता का नाम ख़ुद डीयू के तत्कालीन कुलपति दीपक नैय्यर ने ही प्रस्तावित किया था. चयन समिति के इस रवैये से इतना तो साफ़ हो जाता है कि देश की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में ऊंचे पदों पर नियुक्ति के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक एवं प्रख्यात शिक्षाविद् जगमोहन सिंह राजपूत कहते हैं कि शैक्षणिक सुधार और शिक्षा में उच्च गुणवत्ता के लिए परम आवश्यक है कि संस्थाओं में अध्यक्षों और कुलपतियों की नियुक्ति में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और इसे किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाए. यहां यह बताना ज़रूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में 37 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले जगमोहन सिंह राजपूत का नाम भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने प्रस्तावित किया था, लेकिन उनके नाम पर भी विचार नहीं हुआ था. हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अपने नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

मंत्रालय के पास शुरुआत में कुलपति पद के लिए कुल 33 नाम उपलब्ध थे. एक से बढ़कर एक दिग्गज़. 39 वर्षों तक के अनुभव वाले लोग इसमें शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि इस प्रारंभिक सूची में दीपक पेंटल का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जिन चार लोगों के नाम पर चयन समिति ने विचार किया, उनमें एक नाम पेंटल का भी था. अन्य लोगों में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस, बंगलुरू) के पी बलराम, अजय सूद और डीयू की ही नीरा चंडोक आदि शामिल थे. जब इन चार नामों को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजा गया तो राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि चूंकि अजय सूद इस पद के लिए ख़ुद दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और पी बलराम को आईआईएस, बंगलुरू का निदेशक बना दिया गया है, ऐसे में हमारे पास अब सिर्फ़ दो ही विकल्प बचते हैं, इसलिए दो और नाम विचारार्थ भेजे जाएं. लेकिन चयन समिति ने बाद में दो के बजाय सिर्फ़ एक ही नाम और भेजा. दीपांकर गुप्ता के नाम पर चर्चा ही नहीं की गई, क्योंकि चयन समिति के अध्यक्ष को दीपांकर का वह लेख पसंद नहीं आया था, जिसमें उन्होंने किसी भारतीय राजनेता के बारे में टिप्पणी की थी. इस बारे में चयन समिति का मानना था कि किसी भी विवादास्पद व्यक्ति को डीयू का कुलपति नहीं बनना चाहिए. ज़ाहिर है, चयन समिति की इस सोच से यह तो पता चल ही जाता है कि 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर हुई नियुक्ति के पीछे भी कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव या प्रभाव ज़रूर काम कर रहा था. बहरहाल, धुंआ वहीं उठता है, जहां आग होती है. इसलिए अगर एकेडमिक काउंसिल के सदस्य डीयू के कुलपति दीपक पेंटल की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं तो बाक़ायदा इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच लोगों के सामने आ सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

कुलपति दीपक पेंटल की नियुक्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज़

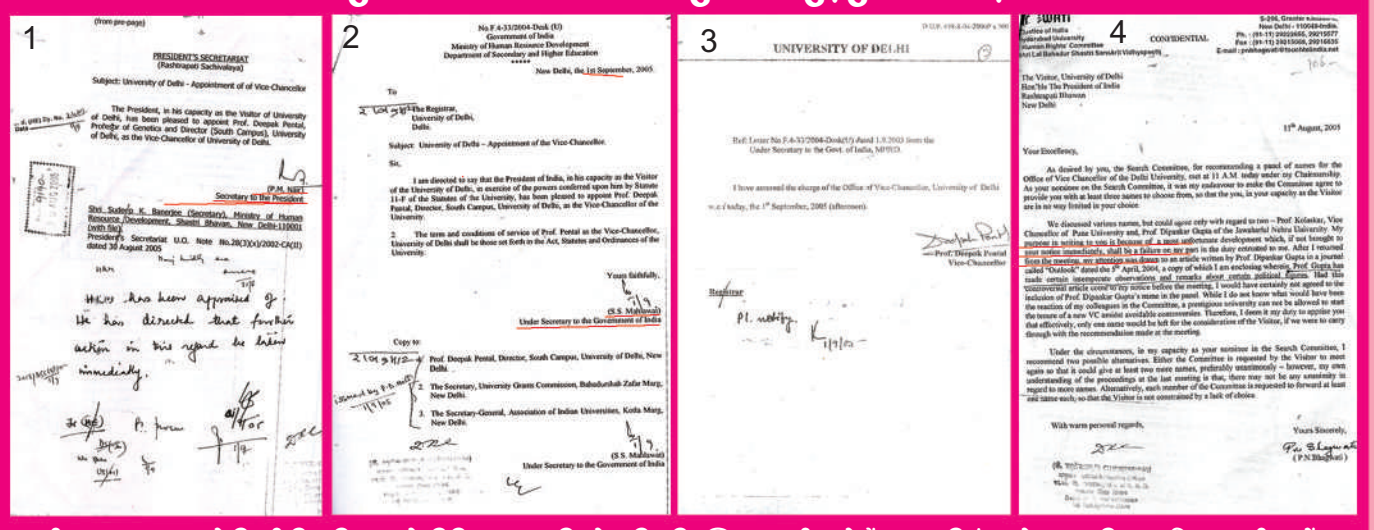

1. तीस अगस्त 2005 को दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटर (राष्ट्रपति) के सचिव नियुक्ति पत्र जारी करते हैं. 2. एक सितंबर को अवर सचिव इसकी सूचना दीपक पेंटल को देते हैं. 3. एक सितंबर को ही दीपक पेंटल पदभार भी ग्रहण कर लेते हैं और उसी दिन डीयू के रजिस्ट्रार इसकी अधिसूचना भी जारी कर देते हैं. 4. सर्च कमेटी के चेयरमैन पी एन भगवती का विजिटर को भेजा गया पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि आख़िर क्यों प्रो. दीपांकर गुप्ता के नाम पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

पेंटल की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है. महामहिम राष्ट्रपति को इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए.

डॉ. धनीराम
प्रोफेसर एवं सदस्य डीयू एकेडमिक काउंसिल

शैक्षणिक सुधार और शिक्षा में उच्च गुणवत्ता के लिए परम आवश्यक है कि संस्थाओं में अध्यक्षों और कुलपतियों की नियुक्ति में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और इसे किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाए.

जगमोहन सिंह राजपूत
एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक एवं शिक्षाविद्

मेरी दुनिया.... रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट ...धीर

देश की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए कई बार यह विचार अनायास ही आ जाता है कि हमारी शासन पद्धति में शायद कोई खोट है और इसके स्वरूप में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए.

मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है. अक्सर उन्हें गंभीर मसलों के फ़ैसले में शामिल नहीं किया जाता.

खुल गया विवादों का पिटारा

एम जे अकबर

राजनीति के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई का बस एक ही विषय है घटना. केंद्र के राजनेताओं ने चुप्पी साध कर विवाद को सुलगने दिया. पांच वर्षों के दौरान मिली दो कामयाबी से वे आश्वस्त हैं कि विलंब ही निदान है. इस विलंब के चेतावनी संकेत को आप कमतर न आंके. जब आपको विभाजन और एकता जैसी असंगत मांगों पर चलना होता है तो टालमटोल हमेशा से एक विकल्प रहा है. फ़र्ज़ी विवाद के ज़रिए तेलंगाना राज्य के गठन के लिए ज़रूरी प्रक्रिया में देरी की अब भी कोशिश की जा सकती है. यह कोशिश हैदराबाद की स्थिति को लेकर हो सकती है. हैदराबाद भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों ही लिहाज़ से तेलंगाना की स्वाभाविक राजधानी है. अगर दिल्ली को हैदराबाद के राजनीतिक मौसम में हो रहे बदलाव की चिंता होती, जैसा कि कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन को लेकर वह चिंतित है, तो उसे सुनामी की भी भनक मिल गई होती. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम तेलंगाना पर तब तक कुछ नहीं बोले, जब तक कि वह इसके लिए मजबूर नहीं हो गए.

सरकार जिस गति से फिसली है, उसने उन लोगों के क्रोध को भड़काने का काम किया, जो यह सोच रहे थे कि वे तो सब कुछ गंवा चुके हैं. सरकार के पास सुलह के लिए पांच साल थे, पर उसने कुछ भी नहीं किया. चंद्र बाबू नायडू की पराजय सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने 2004 में के चंद्रशेखर राव के साथ समझौता किया था, लेकिन नदी पार करते ही कांग्रेस उस नाविक को भूल गई, जिसने उसे नदी पार करवाया था.

सार्वजनिक जीवन में आत्म संतुष्टि एक अपराधिक कृत्य है. फ़ैसले में देरी भले हो सकती है, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता. वर्ष 2009 में दो निर्वाचन क्षेत्रों ने कांग्रेस को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया, जहां वह मित्रों और विद्रोहियों (आंध्र प्रदेश और मुस्लिम वोट) की धमकी से सुरक्षित थी. छह माह के अंदर ही दोनों ने मज़बूत संदेश दे दिए कि परिणाम तो, नहीं तो क़ीमत चुकाओ. इस भटकाव से सरकार पराजय की स्थिति में आ गई. अगर कांग्रेस चंद्रशेखर राव के अनशन के एक दिन पहले तेलंगाना की मांग को स्वीकार कर लेती तो राव ऐतिहासिक शख़्सियत बनने की बजाय इतिहास की बात बन गए होते.

भारत के नए मानचित्र पर आधा दर्ज़न हितधारकों को दिल्ली ने एक ख़तरनाक संकेत भी दिया है. सिर्फ़ रोने- धोने से कुछ भी हासिल नहीं होता. इन तमाम आवाज़ों, गुस्से, ग़लतियों और उत्तेजना के पीछे तेलंगाना का वादा महत्वपूर्ण है, लेकिन संघवाद की गतिशीलता में मोटे तौर पर किसी ने इस बदलाव की ओर ध्यान नहीं दिया. फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर शामिल थे, का आधार भाषा ही था. इसने भारत के आंतरिक भूगोल को एक नया स्वरूप प्रदान किया. 1960 में महाराष्ट्र और 1966 में पंजाब का गठन हुआ, लेकिन एक बार फिर गठन का आधार भाषा ही था. केवल पर्वतीय इलाक़ों और उत्तर पूर्व राज्यों के गठन के लिए जो आधार तय किए गए, वे थोड़े अलग थे. बदलाव आया. यह काफ़ी तार्किक भी था. राष्ट्र की प्राथमिकता बदल गई. एक बार फिर यह स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा या संस्कृति की पहचान को कोई ख़तरा नहीं है.

नई संघीय राजनीति अर्थशास्त्र से निर्धारित होती है. तेलंगाना और शेष आंध्र के लोग समान भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके बीच आर्थिक मसले को लेकर विवाद है. तटीय आंध्र पर तेलंगाना, वास्तव में संसाधनों के दोहन का आरोप लगाता है. मूलभूत बदलाव वर्ष 2000 में देखा गया, जब अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ. नवसृजित

राज्य और जिन राज्यों से काट कर इन्हें अलग किया गया, दोनों ही राज्यों की जनता समान भाषा बोलती है. दरअसल, नौ साल पहले अगर कोई उपद्रव नहीं हुआ तो यह आम सहमति बनने के प्रतिमान में बातचीत और दुश्चिंता के बीच का अंतर है. इससे पहले कि फोड़ा घाव का रूप लेता, उसका सही इलाज कर लिया गया. प्रत्येक मांग की बुनियाद आर्थिक उपेक्षा की अवधारणा में निहित है. लोग यह मान बैठते हैं कि भारत उदय की गाथा में उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है. बड़े फ़र्ज़ी साबित हो जाते हैं, इसलिए छोटे समझदार हो जाते हैं.

मुस्लिम, कांग्रेस के लिए दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष हैं. उनमें उबाल के पीछे भी मूल वजह आर्थिक ही है. इस तर्क का आधार विश्वास है, क्योंकि मुसलमान की उपस्थिति स्थान आधारित न होकर राष्ट्रव्यापी है. डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद के वर्तमान सत्र के आख़िर में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का वादा किया है. उन्हें इससे होने वाली परेशानियों का पूर्वाभास है, लेकिन यह उनकी परेशानियों की तो अब शुरुआत होगी. कमीशन ने सभी सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए 15 फ़ीसदी आरक्षण की अनुशंसा की है. इसमें से दस फ़ीसदी मुसलमानों को आवंटित होना है. मुसलमान इसे एक मानक के रूप में देख रहे हैं और इस पर क्या कार्रवाई हुई, यह बताने की मांग भी कर रहे हैं.

सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी क़दम एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया को सुलगाने का काम कर सकता है. निश्चितता से कांग्रेस को फ़ायदा ही हुआ है. पिछले चुनाव में मुसलमानों के लिए इस मुद्दे को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि राजनीतिक नेताओं को भांप गए थे. लेकिन यह सफ़ाई तो पहले ही दी जा चुकी है कि इसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता. जो चुनाव जीत चुके हैं, उनके लिए कांग्रेस की दुविधा जानी-पहचानी है. एक वादा जो आपको फिर से स्थापित करता है, आपको परेशान करने के लिए दोबारा लौटता है.

feedback@chauthiduniya.com

क्या भारत को राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ज़रूरत है?

रवि किशोर

आधी सदी के बाद भी भारत के संसदीय लोकतंत्र की तस्वीर धूमिल नज़र आती है. संसदीय पद्धति में चुनावी अंकगणित की मजबूरियां होती हैं, जिनकी वजह से भारत पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बंटा हुआ और बिखरा हुआ नज़र आता है. आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था जाति, मज़हब और संप्रदायों में बंटी हुई है. आज भारत में कोई भी राजनीतिक दल ख़ुद का राष्ट्रीय स्तर का होने का दावा नहीं कर सकता है. इन दलों का प्रभाव कुछ क्षेत्र विशेष में ही हो सकता है, लेकिन सभी जगहों पर इनका प्रभाव नहीं है. सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावों में अपनी पत्नियों, क़रीबियों और निजी सहायकों को ही टिकट देते हैं. इनकी योग्यता अथवा जनसेवा से चुनावी टिकट का कोई मतलब नहीं होता है.

इन तथाकथित नेताओं ने ही अपराधी और बाहुबली क़िस्म के नेताओं को बढ़ावा दिया है. इन नेताओं का ध्यान सिर्फ़ इसी बात पर होता है कि उक्त असामाजिक तत्व उनके लिए कितनी सीटें जीत सकते हैं. स्पष्ट जनादेश के अभाव में भारत गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश कर चुका है, जहां दलबदल रोज़मर्रा की बात है और राजनीतिक दलों की ईमानदारी पैसे से तय होती है. सरकार में मंत्रियों को कार्यभार उनकी कार्यक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि समर्थन के आधार पर दिया जाता है. यदि उन्हें अहम मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो वे समर्थन वापस लेने की धमकी देने लगते हैं. जबकि उनमें से कई नेताओं पर अपराध के मामले चल रहे होते हैं. इन वजहों से भारत की विदेश नीति साधारण और सांप्रदायिक होती जा रही है. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता को भी ताक पर रखा जा रहा है.

संविधान निर्माताओं ने जिन्हें सरकार चलाने का अधिकार दिया है, वही इसके खिलाफ़ हो रहे हैं. इस मामले में पहला झटका इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, जब उन्होंने संविधान में 42वें संशोधन के ज़रिए यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करेंगे. आज भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ काफ़ी हद तक समझौता किया जा रहा है. हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था बनाई थी, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. संविधान की बिगड़ी शक्ल-ओ-सूरत और संसदीय प्रणाली की विद्रूपता को देखकर इसके निर्माता अपनी क़ब्रों में भी शर्म महसूस कर रहे होंगे.

भारत विविधताओं का देश है, इसीलिए इसकी विविधता की एकता को बरकरार रखने के लिए एक ख़ास तरह के संविधान की ज़रूरत है. हमारे निर्माताओं ने इसके लिए इंग्लैंड, फ्रांस और कनाडा जैसे प्रारूप की तलाश की. वे चाहते थे कि हर जाति, धर्म, भाषा के लोग अपनी ख़ास पहचान बनाए रखें, लेकिन वे इस विविधता की एकता को बनाए रखने के लिए मज़बूत बुनियाद अपनाने की सलाह देने में नाकाम रहे. इसीलिए शासन में राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है.

दुनिया के कई देशों में राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई है. कुछ हिस्सों जैसे दक्षिण अमेरिका में तानाशाही है, जबकि कुछ हिस्सों जैसे अमेरिका, फ्रांस, स्विटज़रलैंड आदि में राष्ट्रपति शासन की उदार व्यवस्था अपनाई गई है. उक्त सभी देश उतने ही लोकतांत्रिक हैं, जितना हमारा देश. हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों राष्ट्रपति प्रणाली की वकालत नहीं की? यदि हम देखें तो इसकी एक ही वजह थी कि वे किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारी सत्ता नहीं सौंपना चाहते थे. फिर भी, आज भारतीय प्रधानमंत्री के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तियां हैं. इस तरह सारा मामला राष्ट्रपति प्रणाली के चुनाव पर निर्भर करता है. इसी से यह तय होता है कि एक देश कितना उदार और लोकतांत्रिक होगा.

उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ निश्चित फ़ायदे हैं. यही प्रणाली अमेरिका में है. सबसे अहम फ़ायदा यह है कि इस तरह की व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास अपने मंत्रिमंडल के चयन का अधिकार होता है. जबकि हमारे यहां ऐसा नहीं है. इस प्रणाली में राष्ट्रपति को यह पूरी आज़ादी होती है कि वह उसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे, जो सबसे योग्य हो.

राष्ट्रपति शासन का अमेरिकी प्रारूप भारत के लिए सबसे उपयुक्त है. राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चार साल के लिए किया जाता है. यह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो सिर्फ़ उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं. इसी तरह अमेरिकी संघीय राज्य में एक गवर्नर होता है. हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा दो साल के लिए किया जाता है. यदि राष्ट्रपति शासन प्रणाली भारत में भी शुरू हो जाए तो सांसद और विधायक प्रशासन के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष तौर पर दख़ल नहीं दे पाएंगे. केंद्र और राज्यों में अधिकारी बिना भय और पक्षपात के काम कर सकेंगे. तयशुदा अवधि से पहले उनका तबादला नहीं होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति या गवर्नर योग्य और क़ाबिल लोगों को ही ज़िम्मेदार ओहदे पर एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करते हैं. यदि हम भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाते हैं तो हमें भी

दलबदल के नाटक और गठबंधन की राजनीति से दो-चार नहीं होना पड़ेगा.

मौजूदा व्यवस्था ने हमारे सामाजिक जीवन को भ्रष्ट बना दिया है. इसने चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में पूरी सत्ता सौंप दी है. वे किसी भी तरह सत्ता में बने रहते हैं और इन्हीं लोगों ने समाज को जाति एवं मज़हब की संकीर्ण गलियों में बांट दिया है. एकता की भावना या राष्ट्रीयता को वोट बैंक की वेदी पर कुर्बान कर दिया गया है. इसीलिए जनहित में यह ज़रूरी है कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जाए. यहां यह चर्चा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बदलने के लिए की जा रही है. शासन का मौजूदा स्वरूप सबसे अधिक ख़र्चीला और विभाजित करने वाला साबित हुआ है. यहां यह डर है कि कहीं राष्ट्रपति तानाशाह न हो जाए, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में ज़बरदस्त बहुमत हासिल करने वाला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी एक तानाशाह में बदल सकता है. वित्तीय तौर पर भी संसदीय प्रणाली अपने भारी-भरकम मंत्रिमंडल के कारण सरकारी ख़जाने पर बोझ ही साबित होती है. दोनों सदनों के 800 से अधिक सदस्यों पर होने वाले तमाम ख़र्चों का बोझ भी सरकार ही उठाती है. यही बात राज्य सरकारों पर भी लागू होती है. राजनीतिक दलबदल के कारण मध्यावधि चुनाव होने से फ़िज़ूल व्यय का बोझ भी चिंता की बात है. इसलिए कई लोगों को यह लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि भारत में भी संसदीय व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यह अपना प्रभाव और उपयोगिता साबित करने में असफल रही है. भारत को भी शासन की राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष मतदान के ज़रिए राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के लिए किया जाता है. वह राज्य और केंद्र सरकार दोनों का ही प्रमुख होगा. यह प्रणाली राज्य स्तर पर भी अपनाई जानी चाहिए, जिसमें गवर्नर का भी चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के ज़रिए होता है.

अमेरिकी और फ्रेंच व्यवस्था की राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अमेरिकी प्रणाली भारत के लिए अधिक उपयुक्त है. इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि जो भी राज्य और केंद्र सरकार का मुखिया बनेगा, वह भारत के लिए अपना सबसे बेहतर योगदान देने में भी सक्षम होगा. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बौद्धिकता और व्यक्तिगत निष्ठा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. इससे अपराधी और दाग़ी लोगों को सरकार से दूर रखने में मदद मिलेगी. सबसे अहम बात यह है कि हर भारतीय के लिए वोट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए. इस प्रणाली के ज़रिए देशवासी ख़ुद भारत का भविष्य तय कर सकेंगे.

यह सही है कि कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं है, लेकिन इस समय जब हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा तय किए गए मानकों के मुताबिक़ काम नहीं कर रही हैं तो शासन में राष्ट्रपति प्रणाली लागू होना समय की मांग है. यह वक़्त की दरकार है कि क़ानून निर्माता अपना पूरा समय लें, वर्तमान स्थिति पर पैनी नज़र रखें और अमेरिकी प्रारूप के मुताबिक़ भारत में भी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाए जाने के संबंध में अपनी एक स्पष्ट राय ज़ाहिर करें.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

समाचारपत्र, नमक और माचिस

चौथी दुनिया का अंक 36 और 37 पहली बार देखा. अच्छा लगा. कलेवर, लेख और मुद्रण आदि सभी श्रेष्ठ हैं. भारतीय समाचारपत्र अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ते हैं. संभवत: अच्छे भी. सउदी अरब में एक समाचारपत्र का मूल्य 26 रुपये और बांग्लादेश में 10 रुपये है. अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों में समाचारपत्र और भी महंगे हैं, जबकि भारत में एक रुपये से लेकर पांच रुपये में सहज उपलब्ध हैं. इस समय तीन चीजें सस्ती लगती हैं, समाचारपत्र, नमक और माचिस. चौथी दुनिया प्रकाशन के पहले वर्ष में है, इससे आशाएं हैं.

डॉ. शरीफ़ुद्दीन खान, *आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़.*

प्रभाष जोशी ज्ञान का सागर थे

वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी के निधन से हिंदी पत्रकारिता जगत को निस्संदेह अपूरणीय क्षति हुई है. वह ज्ञान का अथाह समुद्र थे. उनके विचार सदैव सकारात्मक होते थे. अधिनायकवादी नीतियों के वह प्रबल विरोधी थे. पत्रकारिता के आधार स्तंभ को प्रणाम.

प्रदीप सिंह, *मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

दमदार चौथी दुनिया

यह देखकर काफ़ी खुशी हुई कि चौथी दुनिया दमदार ढंग से प्रकाशित हो रहा है. आपने साहित्य को भी अपने अख़बार में स्थान दिया है, यह अच्छी बात है.

केशव शरण, सिकरौल, *वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

धारदार अंदाज़

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश न होना- राज्यसभा का अपमान शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा. व्यवस्था पर करारी चोट करने का आपका हौसला क़ाबिलेतारीफ़ है. उम्मीद है, चौथी दुनिया पत्रकारिता की इस पैनी धार को यूं ही बरकरार रखेगा.

राजेंद्र विश्नोई, *स्टेशन रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

लिब्रहान का सच

वरिष्ठ पत्रकार एम जे अकबर का लेख लिब्रहान: सत्रह साल और कुछ आश्चर्य यह साबित करता है कि देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकतर लोगों में चरित्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है. ऐसे उत्कृष्ट आलेख चौथी दुनिया में आगे भी छपते रहेंगे, हम यही आशा करते हैं.

सोमनाथ झा, *कंकड़बाग, पटना, बिहार.*

एक सुखद एहसास

पाकिस्तानी पत्रकारों-लेखकों के आलेख अपने देश और अपनी भाषा में पढ़ना एक सुखद एहसास है. तालिबानके सरगना मुल्ला उमर और अमेरिकी नीतियों के बारे में जानकारी लाभप्रद है. अंतरराष्ट्रीय पृष्ठ हमें दुनिया के अन्य देशों से जोड़ता है और यह बताता है कि कहां क्या चल रहा है.

सुषमा सिंह, *दरियागंज, दिल्ली.*

सिर्फ़ बरसी मनती रहेगी?

भोपाल गैस त्रासदी से दुनिया वाक़िफ़ है, इसके बावजूद पीड़ितों की दिक्कतें दूर करने की दिशा में कोई ठोस क़दम नहीं उठाए जा रहे हैं. लगता है कि कंपनी का ज़हरीला कचरा यूं ही पड़ा सड़ता रहेगा और एक साल बाद हम फिर भोपाल गैस कांड की बरसी मनाएंगे. आख़िर ऐसा कब तक?

नवीन कुमार अग्रवाल, *छतरपुर, मध्य प्रदेश.*

गंभीर लेख ज़रूरी हैं

जगमग दुनिया पढ़ना अच्छा लगता है. चित्रों का चयन भी ठीक है, लेकिन फ़िल्मी गॉसिप के अलावा इस पेज पर गंभीर लेख भी दिए जाएं तो यह और भी अच्छा हो सकता है. चौथी दुनिया ने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है.

रीना कुमारी, *जोधपुर, राजस्थान.*

क़ानून तो वाकई अंधा है

एक क़ानून ने ज़िंदगी... लेख पढ़ा, आश्चर्य होता है कि सुरक्षाबलों द्वारा क़ानून का इस तरह दुरुपयोग होता है. जिनकी रक्षा के लिए क़ानून बनाए जाते हैं, जब वही उससे पीड़ित होने लगें तो यह अफ़सोस की बात है.

बृजेंद्र यादव, *नंदनगरी, नई दिल्ली.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

लोकसभा और राज्यसभा में इतना अंतर्विरोध क्यों

संतोष भारतीय

अली अनवर जदयू के राज्यसभा सांसद हैं और पसमांदा मुसलमानों के नेता हैं. 24 नवंबर को उन्होंने राज्यसभा में चौथी दुनिया की प्रति लहराई और मांग की कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट इस अख़बार में छप गई है. उनका यह भी कहना था कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफ़ारिशों का भी उतना ही महत्व है, जितना लिब्रहान कमीशन की सिफ़ारिशों का, तब क्यों सरकार दोहरा मानदंड अपना रही है. उसने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी, पर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है. उनका समर्थन तारिक अनवर, अमर सिंह, कमाल अख्तर, एस एस अहलूवालिया, जयंती नटराजन, सीताराम येचुरी और डी राजा ने किया. इनकी इस मांग का, कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया में छप गई है तो उसे संसद में तत्काल पेश किया जाना चाहिए, का समर्थन एन के सिंह, वेंकैया नायडू, राजनीति प्रसाद और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी किया. राज्यसभा दो बार स्थगित भी हुई पर इन सांसदों को, जो हर दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जवाब नहीं मिला.

बीस साल से सदन में किसी ने यह नज़ारा नहीं देखा था कि सांसद अपनी मांग पर ज़ोर देने के लिए हवा में अख़बार लहरा रहे हों. प्रधानमंत्री नज़ाकत समझ गए और उन्होंने उठकर आश्वासन दिया कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन में इसी सत्र में पेश कर दी जाएगी.

अली अनवर के मन में सवाल उठा कि उनका राज्यसभा का सदस्य रहना कितना सही है, क्योंकि जब वे और हर दल के सदस्य मिलकर भी सही बात नहीं मनवा सकते तो क्या वे अप्रासंगिक हो रहे हैं? उन्होंने अपनी व्यथा अपने साथियों से कही. उधर लिब्रहान रिपोर्ट को लेकर देश में बयानबाज़ी शुरू हो चुकी थी और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज़ हो गई थीं.

कोई नहीं था जो कहता कि रंगनाथ मिश्र कमीशन बुनियादी समस्याओं के हल के सुझाव के लिए बना था, जबकि लिब्रहान कमीशन की पूरी रिपोर्ट पिछले सत्रह सालों में छपी अख़बारों की कतरनों का, कहें तो संग्रह भर है, जिसने देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया है. रंगनाथ कमीशन सफलतापूर्वक दबा दिया गया, तब फिर चौथी दुनिया को आगे आना पड़ा. चौथी दुनिया ने कहा कि रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान है. राज्यसभा के सदस्य चाहकर भी रिपोर्ट पेश न करा पाए तो उन्हें क्या कहा जाए. हालांकि 24 नवंबर को अली अनवर और सांसदों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए. यह रिपोर्ट 7 दिसंबर के अंक में छपी तो राज्यसभा के कुछ सांसदों को लगा कि वे इस बार फिर कोशिश कर सकते हैं. उन्होंने चौथी दुनिया के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार का नोटिस दिया तथा कहा कि यह अख़बार हम लोगों को शक्तिहीन और निर्वीर्य लिख रहा है.

जैसे ही आठ दिसंबर को राज्यसभा शुरू हुई, अली अनवर, साबिर अली, अजीज़ पाशा और राजनीति प्रसाद ने शून्यकाल में ज़ोरदार ढंग से चौथी दुनिया के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया तथा कहा कि यह सरकार रिपोर्ट पेश न कर सभी सांसदों को शक्तिहीन कह रही है. यह सरकार हम सांसदों की मानहानि करा रही है. इन सांसदों ने विशेषाधिकार हनन के बहाने सरकार पर ज़ोरदार दबाव डाला कि वह रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करे. वृंदा करात, जया बच्चन, डी राजा सहित सदन के महत्वपूर्ण सदस्य इस मांग का समर्थन करने लगे, पर अमर सिंह ने इस बहस से अपने को अलग रखा. क्यों, यह आगे बताते हैं.

सलमान ख़ुर्शीद बुलाए गए, हालांकि वे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री नहीं. वह आए और यह कहकर कि सरकार कुछ दक्षिणी राज्यों की तरह पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है, चलते बने. विषय यह था ही नहीं, विषय था मुसलमान और ईसाई समाज के उन लोगों की पहचान, जो दलित पेशा करते हैं तथा उन्हें पहचान कर दलितों को मिली सुविधाएं दिलवाना. और यह सुप्रीम कोर्ट की सलाह से हुआ था. सलमान ख़ुर्शीद उलझा कर चले गए. अगले दिन साबिर अली ने सलमान ख़ुर्शीद के बयान पर उन्हें विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया तथा कहा कि कल उन्होंने हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया. आज भी राज्यसभा सरकार से कोई आश्वासन नहीं ले पाई.

अब आया अगला दिन यानी नौ दिसंबर. लोकसभा का प्रश्नकाल शुरू होने वाला था, स्पीकर के आने से पहले प्रधानमंत्री आ चुके थे. जैसे ही स्पीकर मीरा कुमार आईं, मुलायम सिंह यादव खड़े हो गए. उनके हाथ में चौथी दुनिया था. उनके साथ ही चालीस के लगभग सांसद खड़े हो गए. सभी के हाथ में चौथी दुनिया का अंक था, जिसमें रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपी थी, जिसका शीर्षक था, सरकार कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है. मीरा कुमार ने कहा कि वे इस सवाल को शून्यकाल में उठाएं, पर मुलायम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना होगा कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट कब सदन में रखी जाएगी. इसके एक हफ़्ते पहले मुलायम सिंह ने अमर सिंह के घर पर एक प्रेस कांफ्रेंस कर यह घोषणा कर दी थी कि वे रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन में रखवाने के लिए धरना-प्रदर्शन करेंगे.

मुलायम सिंह ने लोकसभा न चलने देने की रणनीति इस होशियारी से बनाई कि किसी को कानोंकान ख़बर नहीं हुई. बीस साल से सदन में किसी ने यह नज़ारा नहीं देखा था कि सांसद अपनी मांग पर ज़ोर देने के लिए हवा में अख़बार लहरा रहे हों. प्रधानमंत्री नज़ाकत समझ गए और उन्होंने उठकर आश्वासन दिया कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन में इसी सत्र में पेश कर दी जाएगी. नौ दिसंबर को समझ में आया कि क्यों आठ दिसंबर को अमर सिंह ने राज्यसभा में उठी मांग के समय अनुपस्थित रहना पसंद किया.

प्रधानमंत्री से आश्वासन लेने का श्रेय मुलायम सिंह को जाता है, पर इस सवाल को पहले उठाने का श्रेय अली अनवर, साबिर अली, राजनीति प्रसाद, अजीज़ पाशा, तारिक अनवर, वृंदा करात, जया बच्चन, जयंती नटराजन, एन के सिंह, अमर सिंह, अहलूवालिया, वेंकैया नायडू सहित बाकी सदस्यों को भी जाता है. अगर वे इस सवाल को ज़ोर-शोर से न उठाते और लोकसभा में मुलायम सिंह अपने साथियों सहित सख्त रुख़ न अपनाते तो रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट बहुत सी दूसरी रिपोर्टों की तरह अंधेरे कमरे की शोभा बढ़ाती.

अब राज्यसभा और लोकसभा को रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को परखना है. भाजपा इसका विरोध करेगी. अदालत इसे किस रूप में देखेगी, कह नहीं सकते. रिपोर्ट लागू होगी या नहीं, यह भी नहीं पता, पर रिपोर्ट संसद में रखवाने के लिए जिन सांसदों ने अपना हौसला दिखाया हम उनकी प्रशंसा करते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री को भी आश्वासन देने के लिए धन्यवाद देते हैं. यही लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ सुनिए

ज़ाकिया सोमन

भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी आज़ादी के 62 साल बीत जाने के बाद भी ग़रीबी और सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार की हालत में रहती है. पूरे देश में मुसलमान भय और असुरक्षा की भावना के साथ बस्तियों में रहते हैं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़, तकरीबन चार फ़ीसदी मुसलमान स्नातक हो पाए हैं. बैंक, विश्वविद्यालय और सरकारी सेवाओं में मुसलमान काफ़ी कम हैं. यह सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन कोई रातोंरात नहीं आया है. एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारें भारतीय लोकतंत्र में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रहीं. ख़ुद को समुदाय का नेता बताने वाले वोट के ठेकेदारों और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के बीच की साठगांठ ने मुसलमानों का ग़रीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और असुरक्षा में रहना सुनिश्चित कर दिया. सांप्रदायिकता के साथ ज़िंदगी जीना आम मुसलमानों की नियति बन चुकी है. 1947 से ही मुसलमान हाशिए पर हैं. इतने हाशिए पर कि कई विशेषज्ञों को लगता है कि वे कल के दलित हैं. उनकी स्थिति दलितों की तरह ही बदतर है. मुसलमानों की सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक जागरूकता की कोई विरासत नहीं है. दलित तो फिर भी क़िस्मत वाले थे कि उन्हें भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे युगद्रष्टा मिले. मुसलमानों का कोई नेता ऐसा नहीं है, जो बड़ा नाम हो. और, जो समुदाय का नेता होने का दावा करते हैं, वे हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हैं.

बदतर दशा के लिए कई कारण ज़िम्मेदार हैं, जिनमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं. पहला, संविधान में गारंटी देने के बाद भी कल्याणकारी राज्य नागरिकों के प्रति अपनी कल्याणकारी ज़िम्मेदारियों को निभा पाने में नाकाम रहा है. दूसरा यह कि मुस्लिम नेतृत्व, अगर आप इसका अस्तित्व मानते हों तो, पूरी तरह असफल साबित हुआ है. हम सभी इस बात से परिचित हैं कि भ्रष्ट और असजग राजनीति, जिसका किसी भी नागरिक चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों, मुस्लिम हों, मज़दूर हों या फिर औरतें हों, के कल्याण में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, ने किस तरह हमारे लोकतंत्र का बुरा हाल कर रखा है. मुसलमानों के मामले में तो वह सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उनकी जानमाल की सुरक्षा में भी नाकाम रही है. पुलिस और नौकरशाही के लोगों की सांप्रदायिक मन:स्थिति के कारण मुसलमानों के साथ भेदभाव एक आम सच्चाई है.

अशिक्षा को छोड़ दें तो मुख्यत: इस सांप्रदायिक सोच के कारण ही कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच इस समुदाय तक नहीं है या फिर बहुत थोड़ी है. सांप्रदायिक और फासिस्टवादी राजनीतिक दलों के उदय के कारण मुसलमानों में डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है. दूसरा कारण, नेतृत्व का अभाव है. कल्याणकारी योजनाओं से उनके वंचित रहने के लिए यह भी समान रूप से ज़िम्मेदार है. इस बात को लेकर सहमति है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मुसलमान एक अखंड समुदाय नहीं है. उर्दू भाषाभाषी मुसलमान हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि तमिल और बंगाली मुसलमान हैं. यहां सुन्नी हैं, शिया हैं, निम्न और अन्य पिछड़ी जातियों के भी मुसलमान हैं. पुरुष हैं, महिलाएं हैं, नौजवान भी हैं जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं.

कई और भी कारक हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में बहुत महत्व हासिल कर लिया है. वृहत विश्व द्वारा एक समुदाय के तौर पर उन्हें किस नज़रिए से देखा जाता है, वह इस बारे में है. मुसलमान गंदे हैं, मुसलमान पिछड़े हैं; मुसलमान देशभक्त नहीं हैं या फिर यह कि मुसलमान आतंकवादी हैं.

एक ओर जहां समुदाय को पेश आ रही चुनौतियां विशाल हैं तो दूसरी ओर खंडित मुस्लिम नेतृत्व में न तो प्रतिबद्धता दिखती है और न ही इन समस्याओं से निबट पाने की क़ाबिलियत. वे ग़ैर वाजिब और मूल रूप से भावनात्मक मुद्दों से ग्रस्त रहे हैं. दुर्भाग्यवश, यह विभिन्न सरकारों को निशाने पर लेता है, क्योंकि किसी ने भी सरकार से शिक्षा, रोज़गार, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा आदि को लेकर मांग नहीं उठाई.

समुदाय को इस वजह से भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है. नेतृत्व को चुनौती नहीं मिली और सरकार बिना कल्याणकारी दायित्वों को पूरा किए दूर हो गई. आखिर मुस्लिम नेतृत्व एक ख़ास तरह का ही क्यों होगा? मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार आमतौर पर धार्मिक पहचान वाले लोगों से ही मशविरा क्यों करती है? आख़िर मुख्यधारा का मीडिया दाढ़ी और टोपी वाले कुछ लोगों के नज़रिए पर ही अपना ध्यान केंद्रित क्यों करता है? आख़िर क्यों सभी सिर्फ़ पुरुषों को ही इसमें शामिल करते हैं? आख़िर मुसलमान औरतों को वे क्यों भूल जाते हैं, जो समुदाय की आबादी का आधा हिस्सा हैं? कोई मत जिसमें समुदाय के आधे लोगों की अनदेखी की गई हो, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुसलमान नेतृत्व महत्वपूर्ण मसलों का कोई समाधान ढूंढ पाने में नाकाम रहा है.

यह पूरी तरह से मेरे और अल्लाह के बीच की बात है. इस मामले में मैं किसी भी बिचौलिए को नहीं जानती. क्या इस्लाम न्याय, समानता, दयाभाव और मानवता का धर्म नहीं है? किसी एक को अधिकार देकर दूसरे को इससे वंचित कैसे कर सकते हैं? यह पक्षपात है, अन्याय है.

जहां तक मुसलमानों की वतनपरस्ती पर सवालिया निशान लगाने की बात है तो सवालिया निशान दरअसल राष्ट्र के अपने अंदाज़ के अभिभावकों की भारतीयता पर है. हक़ीक़त यह है कि मुसलमान उतने ही देशभक्त हैं, जितने कि कोई दूसरे लोग. इस मुद्दे पर बहस दरअसल पाखंड है, जिसे स्वार्थी तत्वों ने पैदा किया है. ये स्वार्थी तत्व भगवा वस्त्रधारी हो सकते हैं और हरे लिबास वाले भी. आप पहले मुसलमान हैं या भारतीय हैं, ग़ैर ज़रूरी सवाल है, जिसे नेक इरादे से नहीं उठाया गया है. बेहतर है कि इसकी अनदेखी ही की जाए.

समुदाय और समाज के लिए आम लोग भी कुछ करना चाहते हैं. इन आम लोगों में शिक्षक हैं, छात्र हैं, व्यवसायी हैं, पेशेवर हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कि महिलाएं हैं. दूसरे ज़्यादातर भारतीयों की तरह ही ऐसे लोग हैं, जिनकी कई पहचान हैं. हज़ारों सामान्य महिलाएं पूरे देश में फैली हैं, जो पूरे निश्चय और ज़िम्मेदारी के साथ भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी की दिशा में काम कर रही हैं. वे संविधान में व्यक्त समानता, न्याय और लोकतंत्र की भावना में विश्वास करती हैं. वे लोकतंत्र को हक़ीक़त बनाने के लिए काम कर रही हैं. उनमें से ज़्यादातर को कठिन व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा. स्वतंत्र भारत के इतिहास में गुजरात 2002 एक काले धब्बे की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे कि 1984. लेकिन ज़्यादातर लोग 2002 के सकारात्मक नतीजे से वाक़िफ़ नहीं होंगे.

दंगाग्रस्त गुजरात की महिलाओं ने जिस तरह से न्याय के लिए संघर्ष किया, वह अपने आप में मिसाल है. लेकिन यह शर्म की बात है कि हमारे पुरुषवादी नेता इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं. हमें इंसाफ़ चाहिए, मदद नहीं की आवाज़ हमें पूरे गुजरात में बार-बार सुनाई दी. वह कहती हैं कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? क्या हम संसद नहीं जा सकते हैं? जब मासूम लड़कों को पोटा जैसे कठोर क़ानून के तहत जेल भेजा गया तो हज़ारों लोग अहमदाबाद की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने बहादुरी के साथ अपराधियों को, जिनमें से कुछ सरकार में बैठे थे, की गिरफ्तारी की मांग की. ऐसी ही घटनाएं 1992 के दंगों के बाद मुंबई और अन्य जगहों पर हुईं.

कहानी की शुरुआत तो 2009 में हुई. हज़ारों महिला मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने समुदाय की वैकल्पिक और प्रगतिशील आवाज़ को बुलंद करने के लिए संघर्ष का बिगुल फूंका. ये महिलाएं सच्चर कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की मांग कर रही हैं. ये सरकारी अधिकारियों से यह सवाल पूछ रही हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या किया. विभिन्न सरकारी संस्थाओं में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ये सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं. धीरे-धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं की सामूहिक आवाज़ उभर कर सामने आ रही है. आख़िर हम भी मनुष्य हैं और चाहते हैं कि हमारी भी पहचान हो. हम रोज़गार चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहते हैं, सम्मान की ज़िंदगी चाहते हैं. हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं. हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, जहां सभी के लिए जगह हो, भले ही वे किसी भी धर्म, जाति और लिंग के हों. हम ख़ुद और अपने भाई-बहनों की भी स्वतंत्रता चाहते हैं. कुछ स्वनामधन्य नेताओं की तानाशाही हमें बर्दाश्त नहीं. हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं, जितना कि हिंदुत्व सांप्रदायिकता का. हम सांप्रदायिक ताक़तों और पितृसत्तात्मक उन्मादियों से समान संकल्प के साथ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन-मरण का सवाल है. अल्लाह ने हमें सोचने-समझने के क़ाबिल बनाया है. हम वह निर्णय लेते हैं, जो हमारे, परिवार, समाज और दुनिया के हित में है. हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने आसपास इसकी अनुमति भी नहीं देंगे. हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे. देश के नागरिक के रूप में हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे और वैश्विक गतिविधियों में भागीदार होंगे.

मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय के पीछे धर्म नहीं, बल्कि धार्मिक माने जाने वाले लोग हैं. कुछ उलेमाओं द्वारा इस्लाम की ग़लत व्याख्या के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है. दु:ख की बात यह है कि उलेमा सारा कुछ धर्म के नाम पर कर रहे हैं. मेरे जैसे एक नहीं, बल्कि हज़ारों हैं, जो इस बात की तह में नहीं जाना चाहते कि कौन सी पंक्ति, कौन सी आयतें, कौन सा अध्याय औरतों को फलां-फलां चीजों से रोकता है. सत्ता का यह खेल खेलने से मैं इंकार करती हूं. मुझे किसी संशयी विशेषज्ञ की दरकार नहीं है, जो मुझे यह बताए कि क्या सही और क्या ग़लत है. यह पूरी तरह से मेरे और अल्लाह के बीच की बात है. इस मामले में मैं किसी भी बिचौलिए को नहीं जानती. क्या इस्लाम न्याय, समानता, दयाभाव और मानवता का धर्म नहीं है? किसी एक को अधिकार देकर दूसरे को इससे वंचित कैसे कर सकते हैं? यह पक्षपात है, अन्याय है. कहने की ज़रूरत नहीं कि पक्षपात और अन्याय इस्लाम के ख़िलाफ़ है.

(लेखिका भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक सदस्या हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

शराब के सेवन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं. कुछ अध्ययन इसके सेवन से होने वाले नुक़सान को ज़ाहिर करते हैं तो कुछ इससे होने वाले फ़ायदों की बात करते हैं. शराब पीने से दिल की बीमारी का ख़तरा एक तिहाई कम होने की बात भी कुछ ऐसी ही है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

मोसाद का मिशन या युगांडा पर हमला

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि किस तरह एयर फ्रांस के विमान का अपहरण किया गया और इस वारदात में कैसे एक राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका निभाई. एक समय तो इज़रायली सरकार इन अपहरणकर्ताओं के सामने घुटने टेक चुकी थी, लेकिन मोसाद ने अपनी चालाकी से इज़रायल को न सिर्फ़ मुसीबत से बाहर निकाला, बल्कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया. आख़िर मोसाद ने कैसे इस मिशन को अंजाम दिया, आइए जानते हैं इस अंक में...

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

(ऊपर) इज़रायली मिशन प्रमुख योनातन नेतन्याहू और (नीचे) तत्कालीन युगांडाई राष्ट्रपति ईदी अमीन

अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांग मनवाने के लिए इज़रायल के अनुरोध और युगांडाई राष्ट्रपति के निर्देश पर डेडलाइन एक जुलाई से बढ़ाकर चार जुलाई कर दी थी. यह बढ़ाई गई समय सीमा उन पर काफ़ी भारी पड़ी. इस दौरान इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद ने दुश्मनों से मुक़ाबला करने के लिए कमर कस ली. तीन जुलाई को इज़रायली कैबिनेट ने बचाव मिशन को मंजूरी दी. उसके बाद इज़रायली एयरफोर्स के सी–310 हरक्यूलस ने गुप्त रूप से रात के अंधेरे में इंटेब्बे हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी, यह जानते हुए भी कि वहां पहुंचना ख़तरे से ख़ाली नहीं है. इज़रायल का यह एयरफोर्स विमान शर्म–अल–शेख और लाल सागर के महज़ 30 मीटर के ऊपर से जा रहा था, ताकि मिस्र, सूडान और सउदी अरब के रडारों की पकड़ में न आ सके, नहीं तो इज़रायल और मोसाद के मिशन की भनक उसी वक़्त लग जाती. इस विमान के पीछे–पीछे बोइंग 707 के दो और विमान थे.

इस मिशन में लगभग एक सौ इज़रायली अधिकारियों को लगाया गया और मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंटेब्बे. इसे ऑपरेशन योनातन भी कहा जाता है. ऑपरेशन योनातन इसलिए, क्योंकि योनातन नेतान्याहू की अगुवाई में ही इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा था. योनातन नेतान्याहू मौजूदा इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बड़े भाई थे. ख़ैर, इज़रायली सेना रात के 11 बजे हवाई अड्डे पर कार्गो बे के साथ उतरी. इस बे का दरवाज़ा पहले से ही ख़ुला था. एक काले रंग की मर्सडीज़ और लैंड रोवर्स में इज़रायली सैनिक थे. मर्सडीज़ और लैंड रोवर्स को इज़रायली कमांडोज़ एयरपोर्ट टर्मिनल पर तेज़ी से दौड़ाने लगे. उस समय टर्मिनल के पास दो युगांडाई कमांडो तैनात थे और वे इस बात से वाक़िफ़ थे कि राष्ट्रपति ने एक सफ़ेद मर्सडीज़ ख़रीदी है. यहीं वे धोख़ा खा गए. उन दोनों ने गाड़ी को नियमित जांच के लिए रोका, लेकिन मर्सडीज़ में मौजूद इज़रायली कमांडो ने उन पर साइलेंसर युक्त पिस्तौल से वार कर दिया, पर उनका निशाना बुरी तरह चूक गया. यह देखकर लैंड रोवर्स में मौजूद इज़रायली कमांडो ने अपनी रशियन कलाश्निकोव यानी ए के–47 से उन्हें मार गिराया. ए के–47 की आवाज़ सुनकर अपहरणकर्ता चौकन्ने हो गए. इधर इज़रायली कमांडो भी अपनी चूक और ग़लती से सबक लेकर सतर्क हो चुके थे. इसके बाद दोनों तरफ़ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी. इस फायरिंग में इज़रायली कमांडर योनातन नेतान्याहू बुरी तरह ज़ख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत भी हो गई, यानी अब इज़रायली मिशन बग़ैर मिशन प्रमुख के संचालित हो रहा था. फिर भी सब कुछ मिशन के मुताबिक़ चल रहा था और यह सारा माजरा एयरपोर्ट टर्मिनल के पास हो रहा था, जबकि सारे बंधक एयरपोर्ट इमारत के मुख्य हॉल में थे. वहां तक पहुंचने के बाद इज़रायली सैनिकों ने सबसे पहले सभी यात्रियों को बाहर निकाला और उनसे बाक़ी बचे तीन अपहरणकर्ताओं के बारे में पूछा. यात्रियों ने हॉल से लगे एक दरवाज़े की ओर इशारा किया. उसके बाद इज़रायली कमांडो ने उधर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और उन्होंने कुछ इस तरह बाक़ी बचे तीनों अपहरणकर्ताओं को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया. इसके बाद जब इज़रायली विमान सभी यात्रियों को वापस ले जाने लगे तो युगांडाई सैनिक उन पर गोलियां बरसाने लगे. जवाब में इज़रायली सैनिकों ने भी हमला बोल दिया. नतीजतन, कई युगांडाई सैनिक काल के गाल में समा गए. इज़रायल का यह पूरा मिशन लगभग 53 मिनट तक चला, जिसमें सभी सात अपहरणकर्ता मार गिराए गए. इज़रायल की तरफ़ से मरने वालों में कमांडर नेतान्याहू थे, जबकि पांच अन्य कमांडर घायल हो गए थे. इस मिशन के दौरान क्रॉस फायर में तीन बंधकों की भी मौत हो गई. लगभग 45 युगांडाई सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. जाते–जाते इज़रायलियों ने युगांडा के 11 मिग–77 फाइटर प्लेन को भी नेस्तनाबूद कर दिया.

यहां यह ध्यान देना अहम है कि इज़रायल का मिशन यदि पूरा हो सका तो इसकी भी एक ख़ास वजह थी. दरअसल, इज़रायली कंपनियां ही 1960 और 70 के दशक में अफ्रीका के देशों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती थीं और जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था, वह भी एक इज़रायली कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई गई थी. उसी ने इज़रायली सरकार को उस इमारत की पूरी जानकारी दी, ताकि बंधकों को बचाया और मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके. इस पूरे मिशन को अंजाम देने में मोसाद ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई. मोसाद ने ही अपहरणकर्ताओं की सही तादाद और उनकी गतिविधियों की जानकारी दी, जिससे मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके. सबसे पहले मोसाद ने साज़िशकर्ताओं की सही तादाद की जानकारी जुटाई, उसके बाद वे किन–किन जगहों पर छिपे हैं इस बारे में पता किया और सबसे अहम यह कि इस पूरे घटनाक्रम में युगांडाई सेना की भूमिका क्या थी.

दरअसल, मोसाद को युगांडा पर शक़ उसी वक़्त हो गया था, जब यहूदियों को छोड़कर बाक़ी सभी यात्रियों को जबरन अपहृत विमान से उतार दिया गया था. पांच जुलाई 2006 के एसोसिएट प्रेस के मुताबिक़, मोसाद ने उन सभी यात्रियों से पूछताछ की, जिन्हें पहले आज़ाद कर दिया गया था. मोसाद के लिए अहम सूचना का प्रमुख ज़रिया साबित हुआ एक फ्रेंच–यहूदी यात्री, जिसे ग़लती से अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया. इसी यात्री ने मोसाद को अपहरणकर्ताओं की सही संख्या के बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद की कहानी तो और भी दिलचस्प है. अपहरणकर्ताओं का साथ देने वाले युगांडा ने संयुक्त राष्ट्र में इज़रायल के इस मिशन को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया.

यह कहानी एक तरह से उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी थी. फिर भी युगांडा के विदेश मंत्री ने इस मसले को सुरक्षा परिषद में उठाया और यह मांग की कि इज़रायल की कार्रवाई को युगांडा की संप्रभुता पर हमला माना जाए तथा उसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. हालांकि सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया. उसने न तो इज़रायल और न ही युगांडा के ख़िलाफ़ कोई प्रस्ताव पास किया. इस तरह एयर फ्रांस के अपहरण का यह असली ड्रामा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इज़रायल के इस मिशन में मोसाद ने अपना किरदार इस तरह निभाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इज़रायल को घेर नहीं सकी. जबकि इज़रायल ने युगांडा की धरती पर ही इस पूरे मिशन को अंजाम दिया था. यदि ऐसा मुमकिन था तो सिर्फ़ मोसाद की मदद से ही, जो इज़रायल को हर मुसीबत से निकालने में अपनी भूमिका बख़ूबी और बड़े ही शातिराना ढंग से निभाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

शराब से दिल के रोग का ख़तरा कम !

शोधकर्ताओं के मुताबिक़, रोज़ाना शराब के सेवन से पुरुषों में दिल के रोग का ख़तरा एक तिहाई कम हो जाता है. अगर आप और अधिक शराब का सेवन करते हैं तो यह दिल के रोग के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है. ग़ौरतलब है कि यह अध्ययन स्पेन में किया गया है, क्योंकि वहां के लोग अपेक्षाकृत अधिक शराब पीते हैं, मगर वहां हृदय रोग के मामले कम पाए जाते हैं. हालांकि ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को एहतियात के तौर पर देखने की सलाह दी है.

इस अध्ययन में 29 से लेकर 69 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 15,500 पुरुष और 26,000 महिलाएं थीं. लेकिन हार्ट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़, महिलाओं को अल्कोहल सेवन का फ़ायदा नहीं मिलता है. ग़ौरतलब है कि शोध में शामिल लोगों की आदतों का दस वर्षों तक अध्ययन किया गया. उन्हें शराब न छूने से लेकर रोज़ 90 ग्राम अल्कोहल सेवन करने तक के छह वर्गों में बांटा गया था. रोज़ाना 90 ग्राम अल्कोहल का सेवन सप्ताह में आठ बोतल शराब पीने के बराबर है. अनुसंधान टीम ने पाया कि रोज़ वोदका का एक शॉट तक पीने वाले लोगों में हृदय रोग का ख़तरा 35 फ़ीसदी तक कम हो जाता है, जबकि तीन से 11 शॉट तक रोज़ पीने वालों में यह ख़तरा आधा रह जाता है. महिलाओं में इस तरह के फ़ायदे नहीं दिखे, हालांकि उन्हें हृदयरोग वैसे ही कम होते हैं.

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने स्पेन में हुए अध्ययन को आंख मूंदकर ग्रहण न करने की ज़रूरत बताते हुए कहा है कि इसमें धमनी से जुड़ी बीमारियों के अलावा अन्य तरह के हृदय रोगों पर विचार नहीं किया गया है. साथ ही इसमें अधिक अल्कोहल सेवन से होने वाली अन्य बीमारियों पर भी विचार नहीं किया गया है.

अब अंतरिक्ष के लिए सीधी फ्लाइट

अंतरिक्ष में सैर करने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है. अब वे सीधी फ्लाइट के ज़रिए अंतरिक्ष में क़दम रख सकेंगे. इस यात्रा के लिए उन्हें ज़्यादा क़ीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और इसे साकार करने में लगे हैं वर्जिन कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन. उन्होंने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपनी योजना का ख़ुलासा किया है. उनके मुताबिक़, यह विमान 18 महीनों में तैयार हो जाएगा.

ब्रैंसन ने अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में अपनी योजना की घोषणा की. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्री विमान के दो हिस्से होंगे– स्पेसशिप टू और व्हाइट नाइट टू. व्हाइट नाइट, स्पेसशिप टू को धरती की कक्षा के बाहर ले जाएगा, जहां से स्पेसशिप ख़ुद पृथ्वी का चक्कर लगाएगा. इसमें बैठे यात्री इसकी खिड़कियों से बाहर झांक सकेंगे और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से वे भारहीनता महसूस करेंगे. लिहाज़ा वे विमान में तैरते रहेंगे.

इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक टिकट का दाम दो लाख डॉलर होगा. जबकि रूसी विमानों में जाने का मतलब है साढ़े चार करोड़ डॉलर खर्च करना. ब्रैंसन का मानना है कि नासा या किसी रूसी विमान में अंतरिक्ष यात्रा करना इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा महंगा होगा. ब्रैंसन ने कहा कि विमान बहुत बड़ा होगा और उसमें बहुत सारी खिड़कियां होंगी तो तैरने की जगह भी ख़ूब मिलेगी. विमान को इस तरह बनाया गया है कि वह बैडमिंटन में इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक की तरह धीरे–धीरे धरती पर लौटेगा. अन्य अंतरिक्ष यानों में तीव्र गति से जलने का जो डर रहता है, वह इसमें नहीं होगा.

माना जा रहा है कि 300 लोगों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अभी से टिकट बुक करा लिए हैं.

अज्ञात वस्तुओं की खोज के लिए नासा का नया उपग्रह

नासा ने अपना नया उपग्रह आई लांच कर दिया है. यह उपग्रह इंफ्रारेड सेंसिटिविटी से लैस है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्मांडीय वस्तु को भी देख पाने में सक्षम है. ग़ौरतलब है कि इसे किसी दूसरे कैमरे से नहीं देखा जा सकता है. द वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सपोलर या वाइज को कैलिफोर्निया के वेनदनबर्ग एयरफोर्स बेस से लांच किया गया है.

नासा ने कहा कि क़रीब नौ महीने तक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की कक्षा में रहते हुए उपग्रह ने पूरे आकाश के साथ–साथ एकाध बार शीतल तारे, काले क्षुद्रग्रह और अधिक चमकने वाली मंदाकनियों को भी स्कैन किया है.

यह उपग्रह और भी बेहतरीन सुविधाओं से लैस है. उपग्रह आई में स्पेस कैमरा के अलावा भी कई चीजें हैं. इसमें हब्बल टेलीस्कोप और अंतरिक्ष में जांच के लिए चार तरह की तरंगदैर्ध्य को पढ़ने की क्षमता है. इसके बाद परिणाम के तौर पर जो तस्वीरें आएंगी, उसे नेविगेशन चार्ट के तौर पर स्पेस कैमरा हब्बल, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हर्सल स्पेस ऑब्जर्वेटरी और नासा के आने वाले सोफिया और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में उपयोग किया जाएगा.

जेट परपल्सन लैब और वाइज के प्रोजेक्ट वैज्ञानिक पीटर इस्नहर्डट ने कहा कि इंफ्रारेड की मदद से हम काले क्षुद्रग्रह और अन्य ब्रह्मांडीय वस्तुएं, जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जान सके हैं, चाहे वे काफ़ी बड़ी या कठोर ही क्यों न हो, उन्हें आसानी से जान सकेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारी संख्या में इराकियों और अफ़ग़ानियों को मौत के घाट उतार चुके ब्लैक वाटर का आतंकी खेल पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है. अफ़वाह यह है कि पाकिस्तान की सरकार भी उससे मिली हुई है.

ब्लैक वाटर के ज़रिए पाकिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप

ब्लैक वाटर का संस्थापक ऐरिक प्रिंस

एरिक प्रिंस ख़ुद को ईसाइयों का धर्मयोद्धा मानता है. उसका मक़सद दुनिया के नक़्शे से मुसलमानों और इस्लामिक आस्था को मिटाना है. पाकिस्तान में ब्लैक वाटर को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाज़ार गर्म है.

अक़्दस वहीद

ब्लैक वाटर अमेरिकी सेना का एक निजी संगठन है. यह लालची फर्म पूरी तरह अराजकता और अपराध की प्रतीक बन चुकी है. कंपनी के संचालक न जाने कितने इराकी और अफ़ग़ानी नागरिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं. इसके पूर्व कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि ब्लैक वाटर का मालिक एरिक प्रिंस स्वयं को ईसाई धर्मयोद्धा मानता है, जिसका मक़सद दुनिया के नक़्शे से मुसलमानों और इस्लामिक आस्था को मिटाना है. प्रिंस की कंपनी इराकियों को बर्बाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अपने कर्मचारियों को इसके लिए पुरस्कृत भी करती है. ब्लैक वाटर के पांच कर्मचारियों को अमेरिका के संघीय न्यायालय के सामने ट्रायल के लिए पेश होना है. इन पर आरोप है कि इन्होंने 14 इराकियों की जघन्य हत्या की है, जबकि ब्लैक वाटर का छठा कर्मचारी पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. यह कंपनी अवैध हथियारों की तस्करी और कर चोरी के आरोपों का सामना कर रही है और इस पर युद्ध अपराधों के लिए मुक़दमा भी चल रहा है.

इससे यह निजी आर्मी आगबबूला है. अब तक इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है. एक अख़बार में छपी विस्फोटक रिपोर्ट से कुछ बदलाव आ सकता है. अख़बार का यह आरोप है कि 2007 में 17 इराकियों के कुख्यात निसौर स्क्वायर नरसंहार के बाद ब्लैक वाटर के शीर्ष अधिकारियों ने लगभग एक मिलियन डॉलर के गुप्त भुगतान की व्यवस्था की, ताकि बगदाद की नाज़ुक हालत के बावजूद वे इराक में ही बने रहें. इराकियों ने घोषणा की कि कंपनी अब इराक में काम नहीं करेगी, इसके बावजूद ब्लैक वाटर दो साल तक इराक में जमी रही. इस सच्चाई ने इराकियों को सिर्फ़ चौंकाया ही नहीं, बल्कि उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई. दरअसल, ब्लैक वाटर आज भी 200 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर इराक में बनी हुई है. इस अनुबंध को ओबामा प्रशासन द्वारा हाल ही में बढ़ाया गया. नई रिपोर्ट यदि सही है तो इससे ओबामा प्रशासन को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि इतने लंबे समय तक यह कंपनी इराक में क्या कर रही है? प्रिंस और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ क्या क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है, यह भी एक अहम मसला बन सकता है. प्रिंस पर आरोप है कि रिश्वतख़ोरी योजना में वह भी शामिल था और उसके कनिष्ठ एवं कंपनी के प्रेसिडेंट गैरी जैक्सन ने जॉर्डन में ब्लैक वाटर के हब में रक़म स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. उक्त सारी ख़बरें एक अख़बार में छपी हैं. इस तरह के क़दम अमेरिकी क़ानून में अवैध हैं. रिश्वत के लेनदेन के आरोप के समय एफबीआई की टीम बगदाद में एक आपराधिक घटना की जांच कर रही थी और इस जांच में नतीजे पर पहुंचने के लिए एफबीआई इराकी अधिकारियों, ख़ासकर इराकी गृह मंत्रालय पर निर्भर थी.

ब्लैक वाटर ने इस रिपोर्ट की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि यह पूरी तरह निराधार है. ब्लैक वाटर के पूर्व अधिकारी एवं सीआईए विशेषज्ञ कोफ़र ब्लैक ने उस अख़बार के आरोप को यह कहकर ख़ारिज़ कर दिया कि उसने रिश्वत के मसले पर प्रिंस की मुख़ालफत की थी. जैक्सन ने अख़बार को बताया कि आप कुछ भी लिखें, मुझे कुछ भी फ़र्क़ नहीं पड़ता. यह एक अविश्वसनीय तथ्य है कि ब्लैक वाटर के ख़िलाफ़ नरसंहार और दूसरे अपराधों के जितने आरोप लगे और इराकी राजनेताओं ने जितना विरोध किया, यह कंपनी उतने ही अधिक समय तक इस देश में बनी रही.

यह सिर्फ़ मार्च 2009 तक की ही बात नहीं है, क्योंकि इराकी सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह ब्लैक वाटर के ऑपरेशन के लाइसेंस को आगे नहीं बढ़ाएगी. मई में ब्लैक वाटर की जगह यह काम उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी ट्रिपल कैनोपी को दे दिया गया, लेकिन ब्लैक वाटर फिर भी इराक में बनी रही. कंपनी अमेरिकी सरकार के साथ कहीं और अपने बिज़नेस में लगी रही. आज ब्लैक वाटर अफ़ग़ानिस्तान में विदेश विभाग, सीआईए और रक्षा विभाग के लिए काम कर रही है. वहां यह अमेरिकी अधिकारियों की रक्षा करती है और कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को दिशा-निर्देश भी देती है.

पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के प्रति लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी है कि इसके ज़रिए अमेरिका उनके देश के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है. अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है कि ब्लैक वाटर के निशाने पर अब पाकिस्तानी हैं और इस मक़सद को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी अधिक कमीशन दिया गया है. यह सारा मामला उस रिपोर्ट को लेकर शुरू हुआ, जिसके आधार पर ब्लैक वाटर (यह ज़ी के नाम से भी जानी जाती है) अमेरिका द्वारा आतंकवाद के ख़िलाफ़ चल रहे युद्ध को पाकिस्तान में अंजाम देता आ रहा है. जिमी स्कैहिल ने अपनी हालिया किताब *ब्लैक वाटर* में दुनिया की सबसे ताक़तवर कंपनी के उदय और पाकिस्तान में इसकी मौजूदगी का ज़िक्र किया है. वह इस ख़तरनाक कंपनी की कुख्यात पृष्ठभूमि के बारे में तो बात करते ही हैं, साथ ही अफ़ग़ानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में 2002 से ही इसकी मौजूदगी की भी चर्चा करते हैं. ब्लैक वाटर इन इलाक़ों में ड्रोन हमले में भी अहम किरदार निभा रही है.

यह आरोप ब्लैक वाटर को ईसाइयों के संगठन अल-क़ायदा के तौर पर चित्रित कर रहा है. यदि पाकिस्तान में ऐसे संगठनों की मौजूदगी से उत्तेजना फैलती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है. अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़, ब्लैक वाटर सीआईए के आतंक विरोधी अभियान में पाकिस्तान में सक्रिय तौर पर शामिल रही है. यह मुख्य तौर पर अपने गुप्त ठिकाने से पूरे देश में काम करती है. इसी तरह ब्लैक वाटर ड्रोन हमले में भी सेना की मदद कर रही है. ब्लैक वाटर के कॉन्ट्रैक्टर ने हेलफ़ायर मिसाइल और 500 पाउंड लेज़र बम से एयरक्राफ्ट को लैस किया, जिसका इस्तेमाल सीआईए अधिकारियों द्वारा किया गया.

सीआईए द्वारा ब्लैक वाटर का इस्तेमाल ड्रोन हमले में करना एक चौंकाने वाली ख़बर है. दहशत भरी इस ख़बर के अलावा न्यूज़ रिपोर्ट किसी भी आंतरिक ख़बर को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाई है. आख़िरकार, पाकिस्तान में हो रहे ड्रोन हमले से संबंधित ख़बर कुछ दिन पहले ही सामने आई है. पाकिस्तान में ब्लैक वाटर का मिशन चाहे जिस हद तक हो, लेकिन पाक सरकार लंबे समय से इस बात को नकार रही है. संभवत: किन्हीं अटकलों के कारण ड्रोन हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार और सीआईए के बीच समझौतों को कई बार ख़ारिज़ कर दिया गया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने न सिर्फ़ आपसी समझौते किया, बल्कि जब तक हमला जारी रहा, उन्होंने हमले की आलोचना करना भी बंद कर दिया. इस वजह से न सिर्फ़ अमेरिका विरोधी आवाज़ें उठीं, बल्कि इसने पाकिस्तान की एकता और संप्रभुता पर भी सवाल उठा दिया है. इसने पाकिस्तान सरकार और सेना द्वारा निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है. दरअसल, हक़ीक़त यह है कि यदि पाकिस्तान सरकार अमेरिका से अपने समझौते को लगातार नकार रही है तो भी पाकिस्तानी अवाम इसे आसानी से मानने वाली नहीं है. डॉ. शीरन माज़री और हामिद मीर जैसे कुछ मीडियाकर्मियों ने लगातार इस मसले को उठाया है. अपने कार्यक्रमों के ज़रिए वे लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह वे इन मामले में अपनी भूमिका बख़ूबी निभा रहे हैं.

अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है कि आर्मी हेड क्वार्टर, पेशावर और हाल में रावलपिंडी मस्जिद में इसी संगठन ने हमले करवाए हैं. ब्लैक वाटर लोगों में तो तनाव फैला ही रही है, साथ ही यह कई प्रोविंस में भी सौहार्द्र बिगाड़ने का काम कर रही है. यही वह संगठन है, जिसने इराक में शिया और सुन्नी के बीच मतभेद पैदा किया. ईरान में जनदुल्लाह (पीपुल्स रेसिसटेंट मूवमेंट ऑफ़ ईरान) को भी इसी से मदद मिल रही है. अमेरिकी सरकार हर मुमकिन तरह से कुख्यात ब्लैक वाटर की मदद कर रही है. अमेरिकी सरकार की इस दोहरी नीति से मैं हैरान हूं. एक तरफ़ अमेरिकी यह साबित कर रहे हैं कि वे पाकिस्तानी लोकतंत्र के साथ हैं, जबकि दूसरी ओर वे ही इसकी क़ब्र भी खोद रहे हैं. एक तरफ़ वे पाकिस्तान की संप्रभुता और सम्मान की बात करते हैं, लोगों की इच्छाओं की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे हर मुमकिन तरीक़े से पाकिस्तान की उसी संप्रभुता और सम्मान का चीरहरण करते हैं. पाकिस्तान सरकार के इस रवैये पर मेरा सख़्त एतराज़ है. अफवाह तो यह भी है कि सरकार भी उनसे मिली हुई है. सरकार अमेरिकी दूतावास के तौर पर इस्लामाबाद में दुश्मनों को पनाह दे रही है. यह महज़ एक दूतावास नहीं है, बल्कि वास्तव में पाकिस्तानियों की हत्या की योजना बनाने वाली जगह है.

यहां मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूं, जिससे सरकार के निर्णय लेने की क्षमता का पता चलता है. मूसा हसन ईरानी हैं और वह शैराज़ में रहते हैं. वह एक व्यापारी थे और उन्होंने कुछ मशीनरी अमेरिका से ख़रीदी. वह बिज़नेस के सिलसिले में अमेरिका गए. वह जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर तीन बजे सुबह उतरे. एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें रोका और उनकी जांच-पड़ताल करनी शुरू कर दी. अमेरिकी अधिकारी घंटों उनसे पूछताछ करते रहे और जब तक मूसा बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती नहीं हो गए, उनसे पूछताछ चलती रही. उन्होंने 18 हज़ार डॉलर अस्पताल के बिल के तौर पर चुकाया. वह वापस ईरान लौट आए और यहां उन्होंने ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये के लिए कोर्ट में एक याचिका दाख़िल की और मांग की कि अमेरिकी लोगों के साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए, जैसा मुस्लिमों के साथ अमेरिका में होता है. उन्होंने कहा कि क्यों एक मुसलमान को फिंगर प्रिंट और दूसरी आधारहीन जानकारियां देने की ज़रूरत पड़ती है. साथ ही इसकी वजह से अपमान भी झेलना पड़ता है. अमेरिकी जब ईरान आते हैं तो उन्हें भी फिंगर प्रिंट और वैसी तमाम जानकारियां देनी चाहिए.

19 नवंबर 2006 को अमेरिकियों के लिए ईरान में यह एक क़ानून भी बन गया. सभी अमेरिकी जब ईरान में प्रवेश करते हैं तो फिंगर प्रिंट देना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है. यही वह साहस और शक्ति है, जो निर्णय लेने के लिए होनी चाहिए. कुछ हिम्मत की ज़रूरत पाकिस्तान को भी है. पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तानी लोगों की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए. उन्हें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वे सरकार में हमारी सेवा के लिए हैं, न कि हम पर शासन करने के लिए. अमेरिका को भी हमारे मामले में दख़ल देना बंद करना चाहिए और उन्हें अपने काम से ही मतलब होना चाहिए.

(लेखिका पाकिस्तान की पत्रकार हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

MURUGAPPA GROUP
BSA MOTORS e-Scooters

BSA मोटार्स आ गया
सबके दिलों पे छा गया।

BSA MOTORS की हर एक इलैक्ट्रीक स्कूटर की खरीद पर पाईये
"एक साल की बैट्री वारंटी" एवम् "Rs. 4000/- का कैश कार्ड मुफ्त"।

Conditions apply##
*Ex. showroom Price starting from Rs.15,450/- for Smile in Delhi after subsidy & cash card.
*$ Battery Warranty of 12 months / 12000 km's whichever is earlier & applicable.
*# Savings Vary from model to model.

SHAHDARA: Binsar Auto Mobiles, 954 - E, Main 100 Ft Road, Babarpur Extn.Shahdara. Phone: 011-22831100 / 22831400/9911994444/9911450121. **NAJAFGARH: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No. 1, Block – G, Gopal Nagar. Phone: 011 - 28015634 / 28010709/ 09958019000/9212365634. **DWARKA-MAIN PALAM DABRI ROAD: CNS Retail Pvt Ltd,** D - 70/5, Main Palam Dabri Road, Mahavir Enclave. Phone: 011 – 28011702/ 45017150/09818239724/ 9212275634/ 9212170006. **NANGLOI: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No 18, Ram Nagar Colony, Main Najafgarh Road, Nangloi. Phone: 9971734599 / 9213899686. **KRISHNA NAGAR: Agrawal Motors,** A-1/14. Krishna Nagar, Chachi Building Chawk,Near Lal Quarter Market. Phone: 011 – 22452829/09312835117. **KAROL BAGH: Imperial Cycles,** 53/2, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh. Phone: 011-65461542/ 28722276/25717886/9811453355. **ASHOK NAGAR: New Golden Cycle Store,** 36/13, Ground Floor, Ashok Nagar. Phone: 9810807183. **NOIDA: Agrawal Motors,** B-41 & 42, Sector 16 , Near Mirula's Hotel, Gautam Budh Nagar. Phone: 0120-4249906/ 4232242/9312835117/ 09350906906. **ROHINI: Rocky Autolinks,** F 18/61, Rohini, Sector 8. Phone: 9811032353 (Opening Shortly)

मीना और महादेव मिसाल हैं उन लोगों के लिए, जो असफल होने पर क़िस्मत को कोसते हुए घर बैठ जाते हैं. हिम्मत और धैर्य के सहारे दोनों ने न सिर्फ ख़ुद को, बल्कि कई अन्य लोगों को भी एक नया जीवन दिया.

सिरसिया गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हैं

उमाशंकर मिश्र

स्वरोज़गार के सफल प्रयोग ने पलायन के कारण उजड़ते गांव नगला सिरसिया (भरतपुर) को एक बार फिर से आबाद कर दिया है. इसका श्रेय वहां के धाकड़ जाति के पुरुषों एवं महिलाओं को जाता है.

पायल, ज़ंजीर और घुंघरुओं के अलावा विभिन्न आभूषणों में जड़े जाने वाले नगीनों के उत्पादन में महारत हासिल कर राजस्थान के भरतपुर ज़िले के सिरसिया गांव की महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है. इस पहल से एक तरफ़ जहां जीविकोपार्जन आसान हो गया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आत्मसम्मान पूर्ण एवं स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर भी मिला है. धाकड़ जाति बहुल सिरसिया की बेहतरी का सूत्र तलाशने वाली इन महिलाओं की बदौलत आज पूरे गांव की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है.

कृषि की बढ़ती लागत और घटती पैदावार के साथ प्राकृतिक आपदाओं का दंश भी कई बार इस गांव के लोगों को झेलना पड़ा, जिसके चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया था. लेकिन आज गांव की महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी खुश हैं. इनकी खुशहाली की एक वजह यह भी है कि कभी अपने ही ज़िले में पहचान के लिए जूझने वाले नगला सिरसिया की ख्याति आज देश की सीमाओं से बाहर विदेशों तक फैल गई है. खेती पर इनकी निर्भरता अब लगभग समाप्त हो गई है. साठ परिवारों वाले इस गांव की आबादी लगभग एक हज़ार है, जिसमें सभी धाकड़ जाति के हैं. इन लोगों का मुख्य कार्य खेतीबाड़ी रहा है, लेकिन कृषि योग्य ज़मीन की कम उपलब्धता के कारण सिरसिया के लोगों के सामने जीवनयापन के साधन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी. एक समय ऐसा भी था, जबकि यहां अधिकांश घरों में फांके पड़ते थे. धाकड़ जाति को मेहनतकश माना जाता है. आज उसी मेहनत के बलबूते प्रत्येक परिवार में स्वरोज़गार कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है. जो परिवार अपना काम नहीं करते, वे दूसरों के यहां काम करने जाते हैं. इतना ही नहीं, आसपास के गांवों और कस्बों से भी लोग यहां काम करने आते हैं. अधिकतर लोगों ने पूरे बदलाव के सूत्रधार मीना और महादेव के यहां काम सीखने के बाद ख़ुद का काम शुरू कर दिया है. अब सभी सुखी हैं तो गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा भी है. बच्चे पढ़ रहे हैं. जिन लड़कियों की शादी हो गई, उन्होंने ससुराल में अपना काम शुरू कर दिया है. शहरों की ओर पलायन के इस दौर में सिरसिया एक उदाहरण बन गया है कि अगर हालात से लड़ने का जज़्बा हो तो अपने घर–गांव में रहकर भी जीवनयापन किया जा सकता है. सिरसिया में बदलाव के मुख्य सूत्रधार मीना और महादेव हैं. इनकी कहानी ग्रामीणों के संघर्ष का एक वृत्तचित्र है, जो दूसरों को जीवनयापन के लिए उद्यमीय कौशल की सीख लेने की प्रेरणा देता है. विश्व प्रसिद्ध ताज़ नगरी आगरा में पली–बढ़ी मीना की शादी राजस्थान के भरतपुर ज़िले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ग्यारह के पास स्थित छोटे से गांव नगला सिरसिया में हुई. पति और परिवार के पास मामूली खेती के अलावा आजीविका का कोई सहारा नहीं था. तंगहाल परिवार में बहुत जल्दी ही मीना को अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे में मीना को अपने पिता के घर में किया जाने वाला आर्टिफिशियल चेन बनाने का काम याद आया. मीना अपने मायके गई और घरवालों के सहयोग से एक मशीन ले आई. कच्चे माल की व्यवस्था भी उसने वहीं से की. मीना बताती है कि गांव में कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया, मगर पति ने उसका पूरी तरह से सहयोग किया. मीना घर में अपना काम करने लगी. देखते ही देखते उसके घर की दशा सुधरने लगी. मीना को देखकर आसपास की महिलाओं के मन में भी यह काम करने की चाह पैदा हुई. मीना ने इस काम को सिखाने और बढ़ाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया. उसने गांव की महिलाओं को अपने घर पर ही काम देना शुरू कर दिया.

जब काम बढ़ने लगा तो उसने और मशीनें ख़रीद लीं. इसी बीच ग़ैर सरकारी संस्था लुपिन ह्यूमन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के लोगों ने आकर उससे संपर्क किया. लुपिन की मदद से मीना को 10 हज़ार रुपये का ऋण मिल गया. इसके बाद तो मीना का काम चल निकला. उसने कच्चा माल ख़रीद कर गांव की महिलाओं को काम पर लगा दिया. जल्दी ही ऋण की अदायगी कर देने पर एक बार फिर उसे 15 हज़ार रुपये का ऋण मिल गया. अब तो मीना से सीखने वाली सविता, कमला, सावित्री एवं साधना ने भी अपना अलग से काम डाल लिया है. आज गांव की अधिकांश महिलाएं खेती और परिवार देखने के साथ ही चेन बनाने का काम कर रही हैं. गांव में घुंघरू और पायल बनाने का काम भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है. कभी इन महिलाओं को ख़ुद श्रृंगार का सामान बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, आज वही अपने हाथों से वह सब कुछ दूसरों के लिए तैयार करते समय सुख का अनुभव करती हैं. उन्हें अपने इस काम में परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग मिलता रहता है. जिन लोगों के पास ज़मीन है, वे साथ में खेती का काम भी करते हैं.

सिरसिया के महादेव सिंह 1990 में वाणिज्य स्नातक की डिग्री लेने के बाद 1996 तक एक प्राइमरी विद्यालय में 400 रुपये मासिक पगार पर अध्यापन करते रहे. एक दिन बीमार महादेव के घर प्रबंधक का यह फ़रमान पहुंचा कि आज विद्यालय नहीं आ सकते तो कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है. बीमार महादेव करते भी क्या? अगली सुबह तक उनकी नौकरी जा चुकी थी. महादेव ने अपने मित्र सुरेश को परेशानी बताई और दोनों ने दूसरे दिन जयपुर जाकर कोई काम तलाशने की योजना बनाई. राजधानी की चकाचौंध में कई दिनों तक खाक छानने के बाद दोनों दोस्त जब थक गए तो जौहरी बाज़ार के एक व्यापारी ने इन्हें अपने नगीने की मशीन पर काम दे दिया. एकदम अनजाने काम को दोनों ने कुछ दिनों तक मन लगाकर किया. धीरे–धीरे जब इन्होंने उस काम को करने की दक्षता हासिल कर ली तो फिर अपने गांव में ही एक मशीन ख़रीद कर ले आए. आज इनके पास 30 कारीगर यह काम कर रहे हैं. लुपिन संस्था के सहयोग से महादेव ने अपने कारखाने को प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर लिया है. आज यहां दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं. इस तरह नगीने की घिसाई का काम सिरसिया से आसपास के गांवों में भी फैल गया.

400 रुपये मासिक की नौकरी करने वाले महादेव धाकड़ अब महीने में चालीस हज़ार रुपये तक कमाने लगे हैं. साथ ही दर्ज़नों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का संतोष भी इनके चेहरे पर साफ़ झलकता है. मीना और महादेव के प्रयासों से सिरसिया में बदलाव की ऐसी बयार बही कि बेरोज़गार युवकों का पलायन रुक गया है. न केवल आसपास के कस्बों के कई बेरोजगार युवक यहां इन कामों को सीख रहे हैं, बल्कि दूसरे गांवों से सिरसिया आकर मज़दूरी करने वालों की भी तादाद अच्छी–ख़ासी है.

महादेव सिंह का कहना है कि यदि दलालों से मुक्ति मिल जाए तो इस काम का मुनाफ़ा बढ़ सकता है. इससे कारीगरों को मिलने वाली मज़दूरी भी बढ़ाई जा सकती है. आज नगीने तराशने वाले एक कारीगर को सौ से लेकर डेढ़ सौ रुपये तक मिल जाते हैं. वही चेन का काम करने वाले दो सौ से लेकर तीन सौ रुपये तक कमा लेते हैं. सिरसिया में तराशे गए नगीनों को जयपुर के जौहरी बाज़ार में हाथोंहाथ लिया जाता है. गांव के कारीगर जयपुर से कच्चा माल लाते हैं और तराशने के बाद वापस जौहरी बाज़ार के सेठों के यहां देकर अपना मेहनताना ले आते हैं. इसी तरह से चेन निर्माण के काम में कच्चा माल मुख्यत: आगरा से लाया जाता है और चेन बनाने के बाद वापस वहीं भेज दिया जाता है. आगरा में चेन पर सुंदर पॉलिशिंग एवं पैकिंग होने के बाद उसे देश भर के बाज़ारों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है. अपने कारोबार के लिए कच्चा माल लाने और बिक्री की बेहतर संभावनाएं तलाशने के लिए कुछ लोगों का रोज़ाना बाहर आना–जाना लगा ही रहता है.

आज पूरा गांव महादेव और मीना के मुरीद हैं. बुज़ुर्ग रामकिशन कहते हैं कि कम खेती और बढ़ती लागत से जीवनयापन मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत से घर–परिवार का कायाकल्प कर दिया है. गांव के लोग मीना के बारे में यह कहते नहीं थकते कि आगरा की इस बेटी ने गांव को एक नयाजीवन दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. सगे–संबंधियों से मुलाक़ात होगी. शासन–सत्ता का भरपूर सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का जोख़िम न लें. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
यात्रा और देशाटन के योग हैं. सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार मिलेगा. व्यवसाय में वृद्धि होगी. यदि आपको अभी हाल ही में नौकरी मिली है तो डरने की आवश्यकता नहीं है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
विवाहित लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है. आप अपनी समस्त जीवन शक्ति को एकत्र करके विरोधी भावनाओं को शांत करेंगे. कार्य–व्यापार के लिहाज़ से मिलाजुला समय है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आपको अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए. धन प्रबंध की आवश्यकता पड़ सकती है. इस समय स्थायित्व की आवश्यकता है. जनसंपर्क के माध्यम से अधिक धन कमाने की योजना बनाएंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
यह सप्ताह आपके लिए कई उपलब्धियां लेकर आएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है. मित्रों से व्यवसायिक व्यवहार चलेगा. लेनदेन भी होता रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
संतान पक्ष की परेशानियों में कमी आएगी. दूसरी तरफ पितृपक्ष को लाभ होगा. मंगल की स्थिति धन संचय के लिहाज़ से सही नहीं है. खानपान संबंधी सावधानियां बरतें. यात्रा के योग हैं.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
जीवन को सार्थक करने वाली कोई नई बात सामने आ सकती है. कुंभ राशि में आया वृहस्पति आपके लाभ भाव को भी देख रहा है. अच्छी आमदनी होने की संभावना है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आपकी पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे. यह भी संभव है कि आपका कार्य स्थान बदल जाए. संपत्ति में अचानक वृद्धि होगी. पारिवारिक मामलों में सतर्क रहें, क़लह का सामना करना पड़ सकता है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. अपनी मनपसंद वस्तु ख़रीदेंगे. आपकी राशि बलवान है, कई ग्रहों की उपस्थिति है. यात्राएं स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हैं. भाइयों से संबंधों में खटास आएगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
किसी शत्रुतापूर्ण प्रयास से नुकसान हो सकता है. आपके विरुद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है. विदेश यात्रा के भी लक्षण हैं. ख़र्चा होने के आसार हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आपके जीवन में जो सबसे प्रमुख है, उसके लिए कुछ करने का मन करेगा. बहुमूल्य उपहार प्राप्त करेंगे. आपके लिए सही समय है, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. चार पहिया वाहन ख़रीद सकते हैं.

मीन (21 फ़रवरी से 20 मार्च)
विपरीत चल रहे ग्रह अच्छे नवांशों में आते ही अनुकूल असर दिखाएंगे. सप्ताह के अंत में किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे. परिवार के साथ पर्यटन के योग हैं. काम में मन लगेगा.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

हरिद्वार के इतिहास और परंपराओं पर अनेक लोगों ने कलम चलाई है, पर प्राय: उस सारी सामग्री में मौलिकता और शोध की कमी दिखाई पड़ती है. समग्रता और पूर्णता का अभाव है.

बंद कमरे में यौनेच्छा का विस्फोट

अनंत विजय

हिंदी में अनुवाद की स्थिति अच्छी नहीं है. विदेशी साहित्य को तो छोड़ दें, अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे श्रेष्ठ साहित्य भी हिंदी में अपेक्षाकृत कम ही उपलब्ध हैं. अंग्रेज़ी में लिखे जा रहे रचनात्मक लेखन को लेकर भी हिंदी के प्रकाशकों में ख़ासा उत्साह नहीं है. हाल के दिनों में पेंग्विन प्रकाशन ने कुछ अच्छे भारतीय अंग्रेज़ी लेखकों की कृति का अनुवाद प्रकाशित किया है, जिनमें नंदन नीलेकनी, नयनजोत लाहिड़ी, अरुंधति राय की रचनाएं प्रमुख हैं. पेंग्विन के अलावा हिंदी के भी कई प्रकाशकों ने इस दिशा में पहल की है, लेकिन उनका यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है. राजकमल प्रकाशन ने भी विश्व क्लासिक शृंखला में कई बेहतरीन उपन्यासों और किताबों का प्रकाशन किया था, लेकिन उसकी रफ़्तार भी बाद के दिनों में धीमी पड़ गई. राजकमल के अलावा संवाद प्रकाशन, मेरठ ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है. सिर्फ़ कुछ प्रकाशनों की पहल से इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है. हालत यह है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकों या लेखिकाओं की पुस्तकें भी हिंदी में मुश्किल से मिलती हैं. लेकिन हाल के दिनों में हिंदी के प्रकाशकों ने अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है और वहां जाकर विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों के हिंदी में प्रकाशन अधिकार ख़रीदने की पहल शुरू की है. नतीजा यह हुआ कि हिंदी में भी विश्व की चर्चित कृतियों के प्रकाशन में इज़ाफ़ा होता दिखने लगा है.

राजकमल प्रकाशन के साथ अब वाणी प्रकाशन ने भी इस दिशा में ठोस और सार्थक पहल की है. वाणी प्रकाशन ने वर्ष 2004 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त एल्फ्रीडे येलिनिक की कृति *दी क्लावीयरश्पीलेरिन* का हिंदी अनुवाद *पियानो टीचर* के नाम से छापा है. इस कृति का अनुवाद विदेशी भाषा साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका *सार संसार* के मुख्य संपादक और जर्मन भाषा के विद्वान अमृत मेहता ने किया है. एल्फ्रीडे येलिनिक ऑस्ट्रिया कम्युनिस्ट पार्टी की लगभग डेढ़ दशक तक सदस्य रह चुकी हैं. नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में येलिनिक की आक्रामकता ने उन्हें ऑस्ट्रिया की राजनीति में एक नई पहचान दी, लेकिन कालांतर में उनका राजनीति से मोहभंग हुआ और वह पूरी तरह से लेखन की ओर मुड़ गईं. जब येलिनिक ने लेखन में हाथ आज़माए तो यहां भी उनकी भाषा काफ़ी आक्रामक रही. येलिनिक ने लगभग पचास वर्ष पूर्व के विएना के नैतिक और सामाजिक पतन को अपने लेखन का विषय बनाया तथा उस पर जमकर लेखन किया. येलिनिक की रचनाओं की थीम और उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा को लेकर आलोचकों ने उन पर जमकर हमले किए. एल्फ्रीडे येलिनिक पर बहुधा यह आरोप लगता रहा है कि कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के समाज में व्याप्त विकृतियों और कुरीतियों को अश्लील भाषा में अपने साहित्य में अभिव्यक्ति दी.

दरअसल येलिनिक ने अपने साहित्य में फीमेल सेक्सुअलिटि, फीमेल अब्यूज और विपरीत सेक्स के बीच जारी द्वंद को प्रमुखता से लेखन का केंद्रीय विषय बनाया. नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति *पियानो टीचर* में भी येलिनिक ने मानवीय संबंधों में क्रूरता और शक्ति प्रदर्शन के खेल को बेहद संजीदगी से उठाया है और बग़ैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे पाठकों के सामने कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं.

एल्फ्रीडे येलिनिक का यह उपन्यास *पियानो टीचर* अंग्रेज़ी में 1988 में प्रकाशित हुआ, जिसमें पियानो टीचर ऐरिका कोहूट के जीवन में कामुकता और हिंसा की गाथा को लेखिका ने बेहद शिद्दत से सामने रखा. तीस साल से ज़्यादा की हो चुकी अनब्याही ऐरिका कोहूट अपनी मां की महत्वाकांक्षा की शिकार हो जाती है. सातवें आसमान पर पहुंची मां की महत्वाकांक्षा ने अपनी बेटी को कला की वेदी पर बलिदान करने का प्रण लिया हुआ है. पिता की मृत्यु के पश्चात जब वह बड़ी हो रही होती है तो मां ने उसके आसपास का वातावरण कुछ इस तरह बनाया कि बेटी को यह लगने लगा कि घर और मां के अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं है. उसकी सोच, कल्पना एवं इच्छाओं में सिर्फ़ और सिर्फ़ मां रही.

ऐरिका को उसकी मां बचपन से ही पियानो वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने की घुट्टी पिलाती रहती. उसे बार–बार यह एहसास कराया जाता कि प्रसिद्धि के लिए अपनी सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को दफ़न कर देना चाहिए.

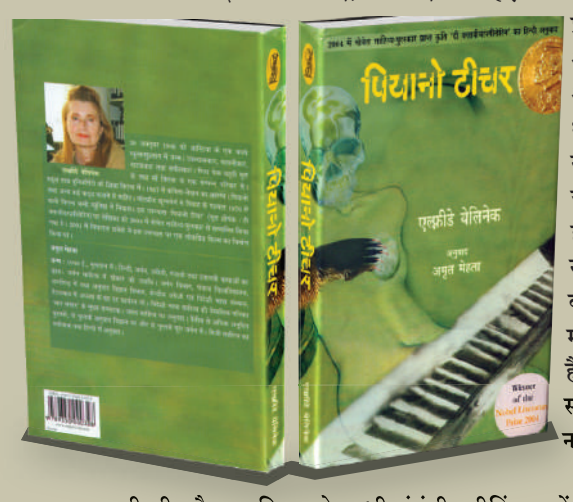

जब वह बच्ची थी और उसकी उम्र के सभी संबंधी स्वीमिंग पूल और अन्य जगहों पर मस्ती करते थे तो मां उसे कमरे में बंद कर रियाज़ करवाती थी. लेकिन विएना जैसे शहर में संगीत के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता थी कि तमाम मेहनत और पाबंदियों के बावजूद ऐरिका सिर्फ़ संगीत शिक्षिका ही बन पाती है. सारे शहर और आसपास के लोगों के लिए तो ऐरिका एक आदर्श बेटी है, जिसने अपनी मां की ख़ातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया है, लेकिन मां के लिए ऐरिका उसके एकाकी जीवन में एक ऐसे खिलौने की तरह है जिसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सेक्सुअल डिजायर को कुचल कर वह उस पर अपना निरंकुश नियंत्रण कायम रखना चाहती है. लेकिन जैसे–जैसे ऐरिक की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी दमित इच्छाएं उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लगती हैं.

एक दिन शाम को वह घर लौटती है और अपने लिए ख़रीदे कपड़े बेहद उत्साह के साथ अपनी मां को दिखाती है. नए कपड़े देखते ही ऐरिका की मां भड़क जाती है और फ़िज़ूलख़र्ची पर उसे लंबा–चौड़ा भाषण पिला देती है. वह बेटी से बेहद रूखे अंदाज़ में यह कहती है कि कपड़ों पर ख़र्च करना व्यर्थ है. कपड़ों का फैशन तो हर दिन बदल जाता है और इन चीजों पर ख़र्च करना फ़िज़ूलख़र्ची है. वह ऐरिका को आगे से इसका ध्यान रखने की नसीहत देती है. वह ऐसी ही सख्ती सेक्स को लेकर अपनाती है और गाहे–बगाहे उसे लेक्चर देती रहती है. तरह–तरह से समझाती है कि सेक्स बेकार है, इससे भटकाव होता है और यह लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है. सेक्स पर मां द्वारा लगाई गई पाबंदी की वजह से वह इस कदर कुंठित हो जाती है कि संगीत विद्यालय से लौटते हुए अश्लील फ़िल्में और लाइव सेक्स शो देखना शुरू कर देती है. चोरी छुपे पार्कों में संभोगरत स्त्री–पुरुषों को देखती है. हस्तमैथुन करते लड़कों को देखने में उसे सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है. लेकिन यह सब देखकर जब उसके अंदर की कामेच्छा बेहद प्रबल हो जाती है तो वह घर के बाथटब में लेटकर अपने यौनांग को काट डालती है और उससे होने वाले दर्द में एक प्रकार के आनंद का अनुभव करती है. लेकिन पाबंदियों और नसीहतों से ऐरिका कोहूट के मन में विद्रोह की चिंगारी भी भड़कने लगती है.

ऐरिका का जीवन अजीबोग़रीब समझौतों से भरी एक ऐसी लड़की की दास्तान है, जो अपनी ही मां की बंदिशों की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो जाती है. इन्हीं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में जी रही ऐरिका को अचानक एक दिन यह एहसास होता है कि उसका एक छात्र क्लेम्मर उस पर आसक्त है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रयासरत भी है. युवा छात्र क्लेम्मर अपने से बड़ी उम्र की अपनी शिक्षिका के बंजर शरीर को भोगना चाहता है और अपने व्यवहार और प्रणय निवेदनों से ऐरिका के अंदर धधक रहे सेक्स की ज्वालामुखी का विस्फोट करवाने में सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन पाबंदियों के बीच जी रही ऐरिका के जीवन का इतना हिस्सा निकल चुका होता है कि उसे यह लगने लगता है कि वह उन वजहों से सेक्स नहीं कर सकती, जो आम स्त्री–पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनने का आधार होती हैं. इन मनोभावों के बीच जब एरिका संभोग के लिए तैयार होती है तो उसे लगता है कि वह कामेच्छा पर क़ाबू पा सकती है और किसी भी हालत या परिस्थिति में बेक़ाबू नहीं हो सकती है.

हर तरह की भावनाओं पर क़ाबू पाना इस उपन्यास की सेंट्रल थीम है, लेकिन जब उसकी भावनाएं अपने युवा छात्र का साथ पाकर बेक़ाबू हो जाती हैं तो वह क्लेम्मर को सशर्त संभोग की इजाज़त देती है. शर्त यह कि सहवास के पहले उसका पुरुष साथी उस पर जमकर शारीरिक अत्याचार करे. पहले उसे बिस्तर से बांध दे, फिर उसकी जमकर पिटाई करे और इन तमाम जुल्मों के बीच उसके साथ सेक्स करे.

बेहद सधे हुए कथानक का यह उपन्यास पियानो टीचर एक लड़की की भावनाओं और मां की महत्वाकांक्षाओं की ज़बरदस्त अभिव्यक्ति है, लेकिन नारीवादी आंदोलन के लोग येलनिक पर नारीवाद के विरोधी होने का आरोप भी जड़ते रहे हैं. येलनिक की नज़र में नारी उत्पीड़न तो है, लेकिन इस वजह से लेखिका कोई अहम या अलग दर्ज़ा देने को तैयार नहीं है. अनुवादक अमृत मेहता का दावा है कि पियानो टीचर में पाठकों का परिचय एक ऐसे क्रूर समाज से होगा, जिसमें हिंसा और समर्पण है. शिकार और शिकारी भी है. लेकिन उपन्यास को पढ़ते हुए मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि हिंदी में स्त्री विमर्श का परचम लहराने का दंभ भरने वाले लेखक–लेखिकाएं कब इस तरह की रचनाओं का सृजन कर पाएंगे. जब हमारे यहां स्त्री विमर्श की सुगबुगाहट चल रही थी, उस वक़्त पश्चिम में स्त्री विमर्श की आंधी चल रही थी.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय जनता अनेकता में एकता की मिसाल

हिंदू संस्कृति जिस धरती पर समृद्ध हुई, उसकी आबादी के बारे में हम जान चुके हैं कि वह मूलत: चार जातियों का मिश्रण रही है. इन्हीं जातियों के बीच के वैवाहिक संबंधों ने हमारी संस्कृति को बहुरंगा स्वरूप प्रदान किया. विविधता में एकता हमारी सांस्कृतिक पहचान रही है. न सिर्फ़ जातीय, बल्कि भाषाई आधार पर भी भारत की विविधता ग़ौर के क़ाबिल है. अलग–अलग क्षेत्रों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं. उत्पत्ति के लिहाज़ से उन्हें अलग–अलग भाषाई समूहों में वर्गीकृत किया जाता है. इन भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, अपना साहित्य है और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी.

भाषाशास्त्रियों ने इस देश में बोली जाने वाली भाषाओं को कई वर्गों में विभाजित किया है. 76.4 फ़ीसदी लोग आर्य भाषा समूह की बोली बोलते हैं, 20.6 फ़ीसदी द्रविड़ और 3 फ़ीसदी लोग शबर–कराती भाषाभाषी माने गए हैं. मंगोल जाति के लोग तिब्बती–चीनी परिवार की भाषाएं बोलते हैं. इस भाषा पर आर्य भाषाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है. तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं हैं, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बोली जाती हैं. द्रविड़ भाषाओं के अनेक शब्द और प्रयोग आर्य भाषाओं में आ गए हैं, जबकि संस्कृत के अनेक शब्द द्रविड़ भाषाओं में मिल गए हैं. फिर भी भारत के दक्षिणी राज्यों में उक्त चार भाषाएं ही प्रचलित हैं. दक्षिण भारत से बाहर भी दो जगहों पर द्रविड़ भाषा बोले जाने के सबूत हैं. यह इस बात का सबूत है कि द्रविड़ लोग कभी भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैले थे. उदाहरण के तौर पर, बलूचिस्तान की ब्रहुई भाषा द्रविड़ समूह की भाषा मानी जाती है, जबकि झारखंड के प्रमुख आदिवासी ओरांव जो भाषा बोलते हैं, वह भी द्रविड़ों से मिलती–जुलती है. भाषाओं के वर्गीकरण के संबंध में कई विवाद भी हैं. भाषाशास्त्रियों में इस बात को लेकर मतभिन्नता है कि ब्रहुई और ओरांव भाषाएं सच में द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं या किसी और परिवार की. आदिवासियों के बीच और भी कई बोलियां प्रचलित हैं, जो वर्गीकरण की दृष्टि से ऑष्ट्रिक एवं आग्नेय भाषा समूह में रखी जाती हैं.

हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमी और कश्मीरी आदि आर्य भाषाएं बताई गई हैं, जो संस्कृत की परंपरा से उत्पन्न हुई हैं. भारत से बाहर आर्य भाषाओं का संबंध इंडो–जर्मन भाषा समूह से है. प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, केल्ट, त्युतनी, जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं के साथ हमारी संस्कृति का बहुत निकट का संबंध था और वह नाता आज भी है. लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी और अब इटली, फ्रांस और स्पेन में उसकी वंशज भाषाएं मौजूद हैं. प्राचीन केल्ट की मुख्य वंशज आजकल की गैलिक यानी आयरलैंड की भाषा है. जर्मन, ओलंदेज(डच), अंग्रेज़ी, डेन और स्वीडिश आदि भाषाएं जर्मन या त्युतनी परिवार की हैं. आधुनिक रूस एवं पूर्वी यूरोप की भाषाएं स्लाव परिवार की हैं. इन सब भाषाओं का परिवार आर्य वंश कहलाता है. इंडो–जर्मन परिवार की भाषाओं में जो समानता है, उसी से यह अनुमान लगाया गया है कि प्राय: समस्त यूरोपीय भाषाएं उसी भाषा परिवार से निकली हैं, जिस परिवार के भारतीय आर्य थे. यही नहीं, ऋग्वेद केवल भारतीय आर्यों का ही नहीं, बल्कि विश्व भर के आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है. वेद समूची मनुष्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है. 19वीं सदी में जब इस सत्य का प्रचार हुआ, तब विश्व भर के अनेक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने लगे और इसी अध्ययन के परिणामस्वरूप आर्य वंश के विस्तृत इतिहास

की रचना की जाने लगी. संस्कृत को सभी आर्यों की मूल भाषा सिद्ध करते हुए मैक्समूलर ने लिखा था कि संसार भर की आर्य भाषाओं में जितने भी शब्द हैं, वे संस्कृत की सिर्फ़ पांच सौ धातुओं से निकले हैं.

विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में जातियों की जो पहचान की गई है, उसका उल्लेख करते हुए डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि भारतीय जनसंख्या की रचना जिन लोगों को लेकर हुई है, वे मुख्यत: तीन भाषाओं–ऑष्ट्रिक अथवा आग्नेय, द्रविड़ और इंडो–यूरोपीय (हिंद–जर्मन) में विभक्त किए जा सकते हैं. नीग्रो से लेकर आर्य तक इस देश में जो भी आए, उनकी भाषाएं इन भाषाओं के भीतर समाई हुई हैं. असल में, भारतीय जनता की रचना आर्यों के आगमन के बाद ही पूरी हुई. उसे ही हम आर्य या हिंदू सभ्यता कहते हैं. आर्यों ने भारत में जातियों और संस्कृतियों का जो समन्वय किया, उसी से हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ. बाद में मंगोल, यूनानी, यूची, शक, आभीर, हूण और तुर्क जो भी आए, इसमें विलीन होते चले गए. सच में रक्त, भाषा और संस्कृति हर लिहाज़ से भारत की जनता अनेकता में एकता की मिसाल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आज अरबों रुपये में संपन्न होते हैं कुंभ

चर्चा कुंभनगर की

डॉ.कमलकांत बुधकर

यूं तो कुंभ का इतिहास बड़ा पुराना है, पर यह धार्मिक–पौराणिक मिथकों के रूप में ही अधिक प्राप्त होता है. धार्मिक हिंदू जगत की परंपरा है कि देश के चार धर्मस्थलों पर कुंभ का आयोजन होता आया है. किसी ज़माने में यह आयोजन व्यवस्थाओं की दृष्टि से केवल साधु–संन्यासियों और पंडे–पुजारियों की देखरेख में आम जनता स्वयं ही कर लेती होगी. तत्कालीन राजे–रजवाड़े, रियासतदार और सामंत–श्रीमंत लोग भी इस आयोजन में निजी पुण्यार्जन के लिए शरीक होते थे. अपने साथ–साथ वे आम जनता के लिए भी कुछ साधन–सुविधाएं और अपने स्तर पर कुछ सुरक्षा धर्मकार्य मानकर जुटा देते होंगे, लेकिन कुंभ जैसे विराट जनपर्वों की कोई एकीकृत समवेत व्यवस्था किसी के ज़िम्मे होती थी, ऐसा उल्लेख अभी तक तो नहीं मिला है.

लेकिन हां, हरिद्वार के महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं का पहला उल्लेख हमें मुग़लकाल के इतिहास ग्रंथ खुलासातुत्तवारीख जो संभवत: 1695 में लिखा गया, में मिलता है. तवारीखकार इसमें लिखता है, हालांकि धर्मग्रंथों के अनुसार गंगा अपने स्रोत से गंगासागर तक सर्वत्र पूजनीय है, पर हरिद्वार इसके तट पर बसे सभी नगरों में सर्वप्रमुख है. हर साल जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, यहां बैसाखी का वार्षिक मेला लगता है और इसी के साथ विशेषकर बारह साल बाद जिस साल गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब यहां दूरदराज से बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं. वे मानते हैं कि यहां आकर दाढ़ी–मूंछ और बाल मुंडवाना, गंगास्नान करना, दान देना आदि श्रेष्ठ करणीय कार्य हैं. यही नहीं, अपने मृत परिजनों की अस्थियों का प्रवाह गंगा में करना भी मृतकों की मुक्ति का साधन है. इसी तरह का मिलता–जुलता वर्णन 1759 में लिखे गए चहर–गुलशन नामक इतिहास ग्रंथ में मिलता है. ग्रंथकार लिखता है, हरिद्वार में बैसाखी मेले में बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं. जब सूर्य मेष और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब यह मेला कुंभ कहलाता है. तब लाखों सामान्यजन, फ़कीर और संन्यासी यहां एकत्र होते हैं. जो बैरागी फ़कीर आते हैं, वे संन्यासियों के साथ ही जुड़ जाते हैं. इन आरंभिक वर्णनों के अलावा कोई ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण कुंभ के विषय में उपलब्ध नहीं है. यूं तो हरिद्वार, यहां के इतिहास

और परंपराओं पर अनेक लोगों ने कलम चलाई है, पर प्राय: उस सारी सामग्री में मौलिकता और शोध की कमी दिखाई पड़ती है. समग्रता और पूर्णता का अभाव है. इस दृष्टि से मुझे अमेरिकी शोधकर्ता डॉ. जेम्स जी लॉख्टफेल्ड का कार्य प्रेरक और प्रभावशाली लगता है, जिन्होंने 1992 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध हरिद्वार को ही अपना मुख्य विषय बनाते हुए प्रस्तुत किया था. उनके अनुसार, 1867 के हरिद्वार कुंभ के दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं. कुंभ मेलों की व्यवस्था शासन–प्रशासन द्वारा किए जाने की शुरुआत उज्जैन में 1740 में तब हुई, जब मालवा पर राणोजी सिंधिया का राज था. वह सिंधिया राज के संस्थापक थे. उल्लेख है कि अपने शासनकाल में उन्होंने ही इस महान मेले की राजकीय व्यवस्था की शुरुआत की थी.

मेले की सरकारी व्यवस्थाएं आरंभ होने से पहले भी हरिद्वार के मेले का दस्तावेजी उल्लेख यहां आए यात्रियों और देशी–विदेशी पर्यटकों ने ख़ूब किया है. ऐसे अनेक पर्यटक हरिद्वार आए, जिन्होंने हरिद्वार के बैसाखी और कुंभ मेले देखने के बाद अपने रोचक यात्रा संस्मरणों में उन्हें उकेरा. इन यात्रियों और उनके संस्मरणों का ज़िक्र तो हम चर्चा के अगले अंकों में करेंगे, पर फ़िलहाल यह बताते चलें कि उनके वर्णनों ने हरिद्वार के मेलों का चित्र तो हमारे सामने रखा ही है. 1796 में हरिद्वार आए अंग्रेज़ यात्री हार्डविक ने लिखा है कि तब उसने यहां पच्चीस लाख यात्री देखे. 1808 में आए फैलिक्स विंसेंट रेपर ने हरिद्वार आए यात्रियों की संख्या का अनुमान बीस लाख लगाया. इसी तरह विभिन्न दस्तावेज, जिनमें तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, बताते हैं कि 1820 में चालीस लाख, 1832 में लाखों, 1844 में बीस से तीस लाख, 1855 में तीस लाख और 1867 में बारह लाख से अट्ठारह लाख तक यात्री हरिद्वार आए थे. डॉ. जेम्स जी लॉख्टफेल्ड का कहना है और लगता भी है कि यात्रियों की उक्त संख्याएं विवादित हो सकती हैं. हरिद्वार आज भी अन्य तीन कुंभनगरों की तुलना में क्षेत्रफल और आकार में छोटा है तो अब से ढाई–तीन सौ साल पहले के हरिद्वार में स्नानपर्व पर बीस–तीस लाख स्नानार्थियों का जुटना अकल्पनीय ही लगता है. प्रयाग का कुंभ मेला क्षेत्र मुख्य शहर से बाहर और अत्यंत विस्तृत है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1812–13 में पूरे साल में इलाहाबाद आए स्नानार्थियों की संख्या 2,18,732 थी. अब तब का इलाहाबाद का सरकारी आंकड़ा अगर पूरे साल में ढाई लाख से भी कम है तो हरिद्वार में दो, तीन या चार मिलियन लोगों का स्नानपर्वों पर आना सचमुच अविश्वसनीय होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से चमत्कार ही माना जाएगा.

लेकिन इस चमत्कार का एक बड़ा कारण केवल कुंभ मेला न होकर हरिद्वार का उसी अवसर पर लगने वाला सालाना वाणिज्य या व्यापार मेला भी था, जो अब लुप्त हो गया है. उस मेले में देश–विदेश के व्यापारी अपना माल बेचने के लिए हरिद्वार आते थे. उसमें अरबी घोड़े, ईरानी कालीन, काबुल–कंधार के मेवे ही नहीं, ग़ुलाम तक बेचे और ख़रीदे जाते थे. विडंबना ही थी कि एक उम्दा अरबी घोड़ा हज़ार–पंद्रह सौ की क़ीमत का होता था, जबकि ग़ुलाम की क़ीमत दस से पंद्रह रुपये हुआ करती थी. इसलिए 1867 के हरिद्वार कुंभ से ही इसके सरकारी व्यवस्था में चले जाने के प्रमाण मिलते हैं. डॉ. जेम्स जी. लॉख्टफेल्ड द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों के अनुसार, 1867 में कुंभ मेले पर कुल सरकारी ख़र्चा 56,666 रुपये, 1879 में कुल 39,335 रुपये, 1891 में 68,975 रुपये और 1903 में 73,166 रुपये हुआ था. सर्वाधिक व्यय तब भी पुलों के निर्माण और सड़कों पर ही होता था. एक बड़ी राशि हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए ख़र्च की जाती थी. जबकि आज के कुंभ ख़र्चों पर दृष्टि डाली जाए तो वे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हज़ारों रुपये के ख़र्च के स्थान पर अब इक्कीसवीं सदी की शुरुआत तक आते– आते अरबों रुपये के होने लगे हैं. .

फर्क़ शायद इतना ही है कि तब अधिकारी और ठेकेदार मिलकर आटे में नमक मिलाते रहे होंगे, पर आज के अधिकारी और ठेकेदार नमक में आटा मिलाने के अभ्यासी हैं. कुंभ तब भी होता था, कुंभ अब भी हो रहा है.

kk@budhkar.in

ट्रॉली नहीं, स्कूटर बैग

कभी आपने ट्रॉली बैग की सवारी की है? अगर नहीं, तो फिर अपने ट्रॉली बैग पर लंबी ड्राइव के लिए तैयार हो जाइए. अंतरराष्ट्रीय कंपनी सैमसोनाइट और माइक्रो मोबिलिटी ने मिलकर एक नया बैग बनाया है, जो स्कूटर में तब्दील हो जाता है. अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो हम आपको दूसरे तरीक़े से बताते हैं. रितिक रोशन की फ़िल्म *कोई मिल गया* तो आपको याद ही होगी. उस फ़िल्म में रितिक अपने दोस्तों की टोली और एलियन जादू के साथ एक स्कूटर पर घूमते हुए गाना गाते हैं. ठीक वैसा ही मिनी स्कूटर है यह बैग. हालांकि पहली नज़र में यह एक सामान्य पहियों वाला ट्रॉली बैग ही लगेगा. लेकिल जैसे ही आप इसके टूल्स और फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि यह कैसे स्कूटर में तब्दील हो जाता है. इसके स्टैंड के नीचे एक डिवाइस लगी है, जिसे खोलते ही ट्राई स्टैंड खुल जाता है. इसके नीचे वाले ट्राई स्टैंड पर आप आराम से खड़े हो सकते हैं और इसका ऊपरी स्टैंड, जिसे पकड़कर ट्राली बैग को हम कैरी करते हैं, हैंडल का काम करता है. कंपनी के निदेशक का कहना है कि उन्हें अक़्सर अपने ग्राहकों से इस तरह के सुझाव मिलते थे. कई बार तो मज़ाक में ही लोग कहते कि काश! भारी भरकम बैग को पहियों से खींचने के बजाय इस पर सवार होकर ड्राइव करने की सुविधा होती तो बात ही अलग होती. इसी बीच उन्हें विचार आया कि बैग मोबिलिटी के क्षेत्र में यह चमत्कार हो सकता है. क्यों न कोई ऐसी तक़नीक ईज़ाद की जाए जिससे बैग को खींचने के बजाए उस पर सवार हुआ जा सके. इस बाबत उन्होंने माइक्रो मोबिलिटी कंपनी से बात की. कंपनी को यह विचार काफ़ी रोचक लगा और उसने बिना देर किए इस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी. परिणाम सबके सामने है. इस बैग के प्रयोग से वैसे तो सभी को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी उम्रदराज लोगों को. अक़्सर बुज़ुर्ग, महिला और शारीरिक तौर पर कमज़ोर लोग यात्रा के दौरान अपने भारी-भरकम सामान को लेकर परेशान हो जाते हैं. ऐसे में यह बैग उनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आएगा. बाज़ार में शॉपिंग से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक आसानी से इस बैग के ज़रिए पहुंचा जा सकता है. इसमें सामान रखने की जगह का भी बख़ूबी ध्यान रखा गया है. बैग में कपड़ों के अलावा लैपटॉप, कैमरा और अन्य ज़रूरी सामान रखने की भी सुविधा है. वजन में भी यह बहुत हल्का है. इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा.

घर में सिनेमाघर

घर में परिवार के साथ पॉपकार्न खाते हुए फ़िल्म देखने का मज़ा ही अलग है. टीवी की छोटी स्क्रीन और प्लाज़्मा में वह आनंद नहीं आता, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में आता है, लेकिन टिकट बुकिंग और सिनेमाघरों की भीड़भाड़ देखकर परिवार के साथ जाना मुश्किल हो जाता है. इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए एप्टेक कंपनी आपके लिए लेकर आई है मोबाइल सिनेमा डीवीडी प्रोजेक्टर. इस कॉम्पेक्ट प्लेयर में आपको बड़े परदे पर फ़िल्म देखने का सुख मिलेगा. इसमें डीवीडी प्लेयर इनबिल्ट है और साथ ही साउंड स्पीकर भी. स्टाइलिश लुक वाले इस प्रोजेक्टर में कई ख़ूबियां हैं. मसलन इसमें एलइडी तक़नीक का प्रयोग किया गया है, जो आपके बिजली के बिल को नियंत्रित करेगा. इसके अलावा इस प्रोजेक्टर पर आप 127 सेंटीमीटर के डायगनल साइज़ पर फ़िल्म का आनंद ले सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलेगी. इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत है इसका कराके सिंग एलोंग प्लेयर. जी हां इस प्लेयर की मदद से आप अपने मनपसंद गीतों को प्ले करके उसके साथ धुन से धुन मिलाकर गा सकते हैं. इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन का जैक दिया गया है, जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर चल रहे गानों के बोल देखकर माइक्रोफोन के ज़रिए गा सकते हैं. लेकिन माइक्रोफोन आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा. इसके साथ आपको मिलेगा एक मेन केबल वायर, जिसका प्रयोग आप इस मोबाइल प्रोजेक्टर को प्लग करने में करेंगे. इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए एक मैनुअल यूजर्स गाइड बुक मिलेगी, जिससे इसके सभी फीचर्स को समझने में मदद मिलेगी. और आप बन जाऐंगे रिमोट फ्रेंडली. वैसे इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है. बस, आपको डीवीडी को इंसर्ट करना है और बाकी सारे कमांड इसकी फ्रंटबॉडी पर देखकर आप प्रोजेक्टर को प्ले कर सकते हैं. इसकी बनावट इस तरह की है कि इसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. इसका वजन मात्र 1180 ग्राम है. इतना हल्का और प्यारा मीडिया प्रोजेक्टर आपको कहां से मिलेगा? बेडरूम हो या डायनिंग रूम, जहां मन चाहे इसका आनंद उठाया जा सकता है. इसमें वे सारे फ़ीचर्स हैं, जो एक ख़ास मीडिया प्लेयर में होते हैं. मसलन ज़ूम, रिकॉर्ड, बेस्ट ऐस्पेक्ट रेसियो और टीएफटी स्क्रीन. इंतज़ार मत कीजिए और 159 डॉलर चुकाकर इसे घर ले आइए.

एप्पल का गोल्डन आईपॉड

एक समय था, जब लोगों को गीत-संगीत सुनने के लिए रेडियो पर निर्भर रहना पड़ता था. उसके बाद सेलफोन आया और फिर आया आईपॉड का ज़माना. युवाओं पर आईपॉड का क्रेज़ इस क़दर छाया कि वह मोबाइल पर हावी होने लगा. आज लोग इसके लिए 1.92 मिलियन डॉलर तक ख़र्च करने को तैयार हैं. यक़ीन नहीं आता! जी हां, क़ीमत ही कुछ ऐसी है, लेकिन यह सौ फ़ीसदी सच है. सुप्रसिद्ध कंपनी एप्पल ने अभी हाल ही में आईपॉड टच सुप्रीम को बाज़ार में उतारा है. इस सुप्रीम की इतनी क़ीमत क्यों है, इसका भी हम ख़ुलासा करते हैं. इस सुप्रीम आईपॉड की पूरी बॉडी 22 कैरेट के सॉलिड गोल्ड से बनी हुई है और इसमें 149 ग्राम सोने का प्रयोग हुआ है. जबकि एप्पल के लोगो की डिज़ाइन में 21 ग्राम सोना और 51 हीरे जड़े गए हैं. अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यह कोई ऐसा वैसा आईपॉड नहीं है. इतना ही नहीं, सामने वाली बॉडी में लगभग 300 हीरों का प्रयोग किया गया है. सबसे ख़ूबसूरत है इसका नेवीगेटर, जिसके सारे बटनों में 16 ग्राम सोने का प्रयोग हुआ है. इन सब ख़ूबियों के अलावा इसके फ़ीचर्स भी किसी से कम नहीं हैं. रेडियो के एफएम और एएम के साथ-साथ इसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है. आप अपने बेहतरीन चुने हुए गीतों का कलेक्शन डीजे म्यूजिक में मिक्स कर सकते हैं. मेमोरी की तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हैं, क्योंकि इस आईपॉड में आपकी सुविधा के अनुसार मेमोरी ऐक्सपेंडल क्षमता पर विशेष ध्यान दिया गया है. आप चार जीबी से लेकर 16 जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं. इतनी मेमोरी में तो आप हज़ारों गाने और वीडियो स्टोर कर सकते हैं. इसका डिस्प्ले भी कम नहीं है. और तो और आप इसका प्रयोग एक स्टोरेज डिवाइस की तरह भी कर सकते हैं. मतलब आप अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे सीवी डाटा और अपने गुप्त दस्तावेज़ों को इसमें स्टोर कर सकते हैं. पासवर्ड के ज़रिए दूसरों की पहुंच से भी इसे सुरक्षित रख सकते हैं. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता कि यह एक परफेक्ट गैज़ेट है. हालांकि इतने बेहतरीन फ़ीचर्स और अट्रैक्टिव लुक के बावजूद यह एक विशेष वर्ग की पहुंच में ही है. क्योंकि आम आदमी इसके स्थान पर 10-20 हज़ार में उपलब्ध अन्य आइपॉड लेने में रूचि दिखाएगा. लेकिन अगर एप्पल कंपनी के निदेशक की मानें तो भविष्य में इसके दाम घटने की उम्मीद की जा सकती है. पर इतना तो तय है कि अगर इसका दाम घटेगा तो बहुत सारे हीरे और सोने की मात्रा में ज़रूर कटौती होगी. तब तक शाही अंदाज़ के लोग इसका भरपूर लुत्फ़ तो उठा ही सकते हैं.

भारत में फूजी का 3-डी कैमरा

फूजी फ़िल्म ने कैमरा निर्माण के क्षेत्र में एक क़दम और आगे बढ़ते हुए अपना 3-डी कैमरा भारतीय बाज़ार में उतारा है. यह कोई आम कैमरा नहीं है. इसके फ़ीचर्स ऐसे हैं, जिन्हें सुनकर आप चौंक सकते हैं. इसके ज़रिए आप थ्री डायमेंशनल पिक्चर ले सकते हैं. आपको सिर्फ़ क्लिक करने भर की देर होगी. मतलब यह कि त्रिआयामी यानी 3-डी तस्वीरें देखने के लिए आपको किसी विशेष चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जापान की दिग्गज़ कंपनी फूजी फ़िल्म की भारतीय इकाई द्वारा पेश किए गए इस कैमरे से आप न सिर्फ़ 3-डी तस्वीरें, बल्कि उन तस्वीरों के प्रिंट भी ले सकते हैं. इस कैमरे के लिए आपको 39,999 रुपये चुकाने पड़ेंगे. कैमरे की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें दो लेंस लगे हुए हैं. इतना ही नहीं, इसमें दो सेंसर टेक्नोलॉजी है. साथ ही ऐसा प्रोसेसर लगा हुआ है, जो दो अलग-अलग तस्वीरों को एक त्रिआयामी तस्वीर के रूप में दिखाता है. इसके अलावा इसमें आठ इंच का स्क्रीन है, जिसकी मदद से आप तस्वीरों को आसानी से देख सकते हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

नई दिल्ली में हीरो होंडा की नई बाइक सीबी ट्वीस्टर के लांच के मौक़े पर होंडा मोटर इंडिया के सीईओ मासाहिरो ताकादेगावा और होंडा मोटर साइकिल व स्कूटर इंडिया के सीईओ शिंजी अवोयामा.

एचटीसी का टैटू एंड्रॉइड मोबाइल

सेलफोन के दीवानों के लिए बाज़ार में एचटीसी ने अपना नया हैंडसेट उतारा है. यह निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों पर ख़रा उतरेगा. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कंपनी का कहना है. वैसे एचटीसी का टैटू एंड्रॉइड काफ़ी हल्का हैंडसेट है और इसका लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव है.

एचटीसी ने भारतीय बाज़ार में सबसे कम दाम का एंड्रॉइड हैंडसेट उतारा है. यह हैंडसेट काफ़ी छोटा है, लेकिन आप इसके आकार पर मत जाइए, क्योंकि इसके फ़ीचर्स ऐसे-वैसे नहीं हैं. इसके ख़ास फ़ीचर्स ही एचटीसी को दूसरे हैंडसेट्स से अलग करते हैं. एचटीसी को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे यह काफ़ी आकर्षक नज़र आता है. इतना ही नहीं, इस्तेमाल करने में भी यह अन्य मोबाइल की तुलना में काफ़ी आसान है. इसका 2.8 इंच का टचस्क्रीन 240.320 पिक्सल रेजोल्यूशन और स्क्रीन रोटेशन के फ़ीचर एक्सीलेरोमीटर को सपोर्ट करता है. इसका बटन सिस्टम आसान और सुविधाजनक है. एचटीसी एंड्रॉइड वी 1.6 और एचटीसी सेंस से लैस है. टैटू में 528 मेगाहट्र्ज (एमएचजेड) का प्रोसेसर लगा हुआ है. एचटीसी टैटू के साथ रेडियो की भी सुविधा है. यह बहुत जल्द ही नौ चैनलों को स्कैन और सेव करता है. इतना ही नहीं, इसमें वायस रिकॉर्डर भी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईपीएल से प्रेरित होकर भारतीय फुटबॉल संघ भी लीग का प्रारूप तैयार करने जा रहा है. उम्मीद है कि संघ के साथ खेल और खिलाड़ियों की भी क़िस्मत अब संवर सकेगी.

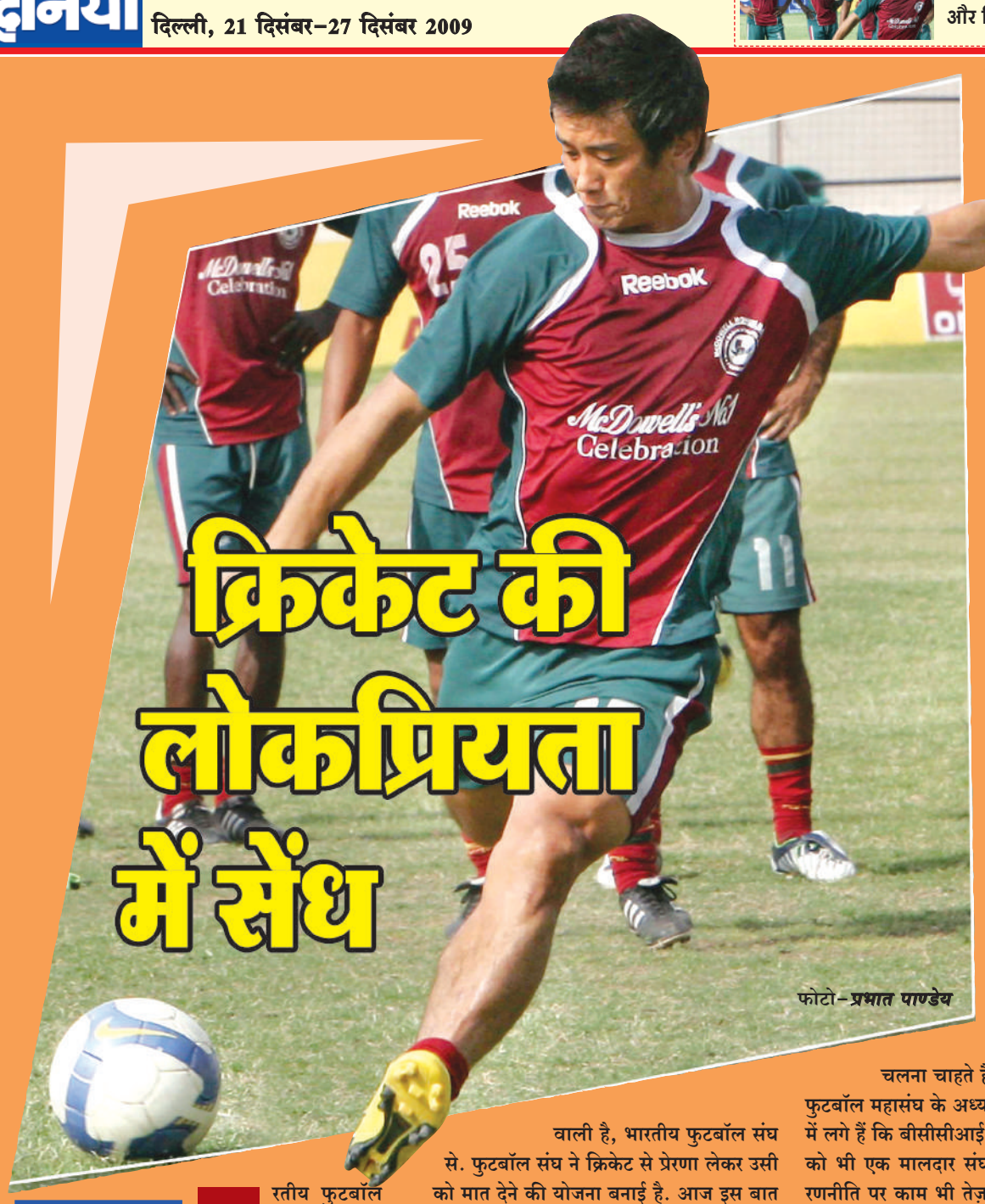

क्रिकेट की लोकप्रियता में सेंध

फोटो – प्रभात पाण्डेय

चंदन कुमार

भारतीय फुटबॉल में व्यापक बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है. यदि ऐसा हो गया तो क्रिकेट को जुनून की हद तक चाहने वाले इस देश में फुटबॉल का खेल एक कड़ी चुनौती बनकर उभरेगा. तब बीसीसीआई भारत में किसी खेल को संचालित करने वाला एकमात्र शक्तिशाली बोर्ड नहीं रह जाएगा. उसे ज़बर्दस्त चुनौती मिलने वाली है, भारतीय फुटबॉल संघ से. फुटबॉल संघ ने क्रिकेट से प्रेरणा लेकर उसी को मात देने की योजना बनाई है. आज इस बात से हर कोई इत्तेफाक़ रखता है कि टी–20 ने क्रिकेट की तस्वीर बदल कर रख दी है. क्रिकेट के इस छोटे स्वरूप के ज़रिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल रही. घरेलू क्रिकेट में इस तरह के प्रयोग ने स्टेडियम में अच्छी ख़ासी संख्या में दर्शकों को खींचा. यही वजह है कि अब कई खेल क्रिकेट के इसी प्रयोग के नक्शेक़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले अपनी खस्ताहाली से उबरने के लिए हॉकी ने आईपीएल की तर्ज़ पर लीग मैचों की शुरुआत करने की बात कही. आईपीएल के नक्शेक़दम पर चलने वालों की सूची में अब जल्द ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नाम भी जुड़ने वाला है. फुटबॉल संघ भारतीय फुटबॉल में क्रांतिकारी बदलाव लाने की योजना बना रहा है. भारतीय फुटबॉल के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय फुटबॉल संघ भी आईपीएल की तर्ज़ पर फुटबॉल लीग शुरुआत करने की सोच रहा है. संघ के सूत्रों के मुताबिक़, इस लीग का पूरा पैटर्न आईपीएल जैसा होगा, यानी इसमें भी खिलाड़ियों और टीमों की नीलामी की जाएगी. दरअसल, आईपीएल की शुरुआत शरद पवार की देखरेख में ललित मोदी ने की थी, जिससे भारतीय खिलाड़ियों सहित बोर्ड को भी करोड़ों का मुनाफ़ा हुआ था. लगता है कि पवार साहब के नक्शेक़दम पर प्रफुल्ल पटेल भी चलना चाहते हैं. पटेल इस समय भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं और वह इस कवायद में लगे हैं कि बीसीसीआई की तरह कैसे फुटबॉल संघ को भी एक मालदार संघ बनाया जाए. उनकी इस रणनीति पर काम भी तेज़ गति से चल रहा है.

आईपीएल की मुंबई और बेंगलुरू टीम के मालिक मुकेश अंबानी और विजय माल्या से इस मसले पर बातचीत चल रही है, क्योंकि इन दोनों ने टीमें ख़रीदने की इच्छा जताई है. वहीं सलमान ख़ान भारतीय फुटबॉल के ब्रांड एंबेसडर हैं और पिछले दिनों आईपीएल टीम ख़रीदने की इच्छा जता चुके हैं. लेकिन, अब कयास यह लगाया जा रहा है कि वह क्रिकेट की जगह फुटबॉल लीग की कोई एक टीम ख़रीद सकते हैं यानी क्रिकेट को कड़ी टक्कर देने के लिए फुटबॉल पूरी तरह तैयार है.

chandan@chauthiduniya.com

केरल एक्सप्रेस श्रीसंथ की शानदार वापसी

फोटो – पीटीआई

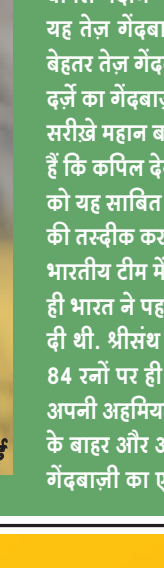

कानपुर में भारत ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में हराकर एक नया कीर्तिमान बनाया. इस मैच एक ओर जहां भारतीय खिलाड़ियों में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने शतक जड़े, वहीं इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट मैचों में अपनी जीत का सैंकड़ा भी पूरा किया. शतक के साथ ही गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक बल्लेबाज़ भी बन गए और इस जीत के साथ भारत भी दक्षिण अफ़्रीका के साथ संयुक्त रूप से नंबर एक पर पहुंच गई. इस मैच का यदि पहला और दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाज़ों के नाम रहा तो तीसरे और चौथे दिन गेंदबाज़ों ने श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों की अच्छी ख़बर ली. ख़ासकर भारतीय टीम में 19 महीने बाद शामिल किए गए एस श्रीसंथ ने. दरअसल, भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों के एक के बाद एक निराशाजनक प्रदर्शन के कारण कई दफ़ा जीत की दहलीज़ पर आकर भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. पहले टेस्ट में ईशांत की कुंद पड़ती गेंदों से टीम को जब कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ तो मजबूरन श्रीसंथ को दूसरे टेस्ट के अंतिम ग्यारह में शामिल करना पड़ा. श्रीसंथ ने इस मौक़े को जाया नहीं होने दिया. केरल एक्सप्रेस श्रीसंथ की आग उगलती गेंदों ने श्रीलंकाई बल्लेबाज़ी को न सिर्फ़ बांधकर रख दिया, बल्कि उनके सामने किसी भी बल्लेबाज़ की चल नहीं पाई. श्रीसंथ ने इस मैच में कुल छह विकेट चटखाकर भारत की जीत चौथे दिन ही सुनिश्चित कर दी. यह बेहद ही दिलचस्प बात है कि श्रीसंथ की जिन तेज़ और ख़तरनाक गेंदों ने भारतीय टीम को सौवें मैच में जीत दिलाई, वह बचपन में लेग ब्रेक गेंदबाज़ी करते थे और भारतीय लेग ब्रेक गेंदबाज़ अनिल कुंबले उनके आदर्श हुआ करते थे. बदक़िस्मती से श्री संथ स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो अस्पताल में भर्ती हैं. जब स्वस्थ होकर एक बार फिर वह वापस मैदान पर लौटेंगे तो उम्मीद की जानी चाहिए की भारतीय टीम का यह तेज़ गेंदबाज़ अपने ग़ैर ज़िम्मेदराना रवैये की वजह से कम और एक बेहतर तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर अधिक जाना जाऐगा. श्रीसंथ में एक अव्वल दर्ज़े का गेंदबाज़ बनने की क़ाबिलियत और माद्दा दोनों है. सुनील गावस्कर सरीख़े महान बल्लेबाज़ भी इस बात से इत्तेफाक़ रखते हैं. तभी तो वह कहते हैं कि कपिल देव के बाद श्रीसंथ ही एकमात्र विशुद्ध तेज़ गेंदबाज़ हैं. श्रीसंथ को यह साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करता है. बात 2006 के दक्षिण अफ़्रीका दौरे की है. इस दौरे पर भारतीय टीम में श्रीसंथ भी शामिल थे और श्रीसंथ की गेंदबाज़ी की बदौलत ही भारत ने पहली बार किसी टेस्ट में अफ़्रीका को उसी की सरज़मीं पर मात दी थी. श्रीसंथ ने उस मैच में कुल पांच विकेट लेकर अफ़्रीकी टीम को महज़ 84 रनों पर ही चलता कर दिया था. यानी श्रीसंथ को जब भी मौक़ा मिला अपनी अहमियत उन्होंने साबित की, लेकिन अब ज़रूरत है कि श्रीसंथ मैदान के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर गंभीरता दिखाएं और स्वयं को तेज़ गेंदबाज़ी का एक चमकता सितारा साबित कर दिखाएं.

spice
www.spice-mobile.com
अब सब खल्लास!
मल्टी–सिम M-4580 की आकर्षक कीमत और भरपूर खूबियाँ करे सबको खल्लास।

M-4580
किलर खूबी: बड़ी बैट्री
25 दिनों का स्टैंड–बाइ टाइम और 10 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी–सिम (GSM/GSM)
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
वन–टच टॉर्च और करैन्सी चैकर
4 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 2149

M-5252
10 दिनों का स्टैंड–बाइ टाइम और 4 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी–सिम (GSM/GSM)
डिजिटल कैमेरा
बिल्ट–इन FM एंटेना
ड्यूअल LED टॉर्च
8 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 3049

C-5300
सभी CDMA कनेक्शन के साथ चले
बड़ी स्क्रीन
डिजिटल कैमेरा
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
एक्सपैन्डेबल मैमोरी
वन–टच टॉर्च
BEST BUY PRICE: Rs. 2999

बड़ी स्क्रीन | बड़ी मैमोरी | बड़ा साउण्ड | बड़ी बैट्री
big series
Spice Mobiles come loaded with:
emergic email2sms Mail on Mobile | Shuffle Ring tone | mGurujee | ibibo i build • i bond | REUTERS | Mobile Tracker
Registered Office: Spice Mobiles Ltd., D-1, Sector-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India. Fax: +91-120-4363845. E-mail: contactus@spicemobile.in. Spice Mobile Phones are available at all leading telecom outlets. *Conditions apply. Price features and specifications are subject to change without prior notice. Some of the listed capacity is used for phone functions and thus available capacity could be less than the quoted figure. Battery operation time may vary depending on network usage, environment, music and video formats.
www.itsaugust.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

अंग प्रदर्शन जैसे नुस्ख़े का सहारा लेने के बाद भी क़िस्मत उदिता से रूठी रही. एक फ़िल्म में वह अक्षय की नायिका बनी हैं. करियर की डूबती नैया को अब शायद इससे सहारा मिल जाए.

शादी का लड्डू अभी नहीं

रानी मुखर्जी इन दिनों काफ़ी फिट और स्लिम दिख रही हैं. यशराज बैनर की फ़िल्म *दिल बोले हड़िप्पा* की ज़रूरत के मुताबिक़ उन्होंने अपनी बॉडी पर ख़ासा ध्यान दिया और प्रशंसकों से जमकर तारीफ़ बटोरी. हालांकि रानी को इस बात का ग़म ज़रूर सता रहा है कि इतनी मेहनत के बावजूद इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा. पर उन्हें इस बात से राहत भी है कि उनके प्रशंसकों को उनका नया सेक्सी अंदाज़ ख़ूब भाया है. लेकिन रानी अपनी शादी को लेकर आए दिन उड़ने वाली अफ़वाहों से काफ़ी परेशान रहती हैं. रानी कहती हैं कि ऐसी अफवाहें उनके करियर को प्रभावित कर रही हैं. इनके चलते निर्देशक उन्हें फ़िल्म ऑफर करने से पहले कई बार सोचते हैं. रानी को लेकर फ़िल्म साइन करने में उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं वह शूटिंग के बीच में ही शादी करने न चली जाएं. क्योंकि अक़्सर ऐसा होता है कि जब अभिनेत्रियां शादी करने का फ़ैसला लेती हैं तो कई फ़िल्में अधूरी ही रह जाती हैं. जिसके चलते कई बार निर्देशकों को बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है. रानी का नाम आदित्य चोपड़ा से जोड़ कर काफ़ी कुछ ख़बरें उड़ाई गईं थीं. बड़े-बड़े निर्देशकों-अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी रानी की ज़िंदगी में ऐसा दौर पहली बार आया है कि उन्हें कोई अच्छी फ़िल्म मिलने का इंतज़ार करना पड़ा हो. रानी कहती हैं कि फ़िलहाल वह अपने करियर पर ध्यान देंगी और शादी का लड्डू कुछ समय बाद ही चखेंगी.

हाउसफुल में कैट फाइट

किसी फ़िल्म में एक से ज़्यादा अभिनेत्रियां हों तो आपस में नोकझोंक ज़रूर होती है. कुछ ऐसा ही नज़ारा साजिद ख़ान की फ़िल्म *हाउसफुल* के सेट पर देखने को मिल रहा है. इस बार कैट फाइट है लारा दत्ता और दीपिका पादुकोण के बीच. ग़ौरतलब है कि दोनों अभिनेत्रियां फ़िल्म *हाउसफुल* में स्क्रीन पर एक साथ नज़र आएंगी. फ़िल्म में इनके अलावा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, जिया ख़ान और अर्जुन रामपाल भी हैं, लेकिन लारा एवं दीपिका ने सेट पर सबको परेशान कर रखा है. दोनों फ़िल्म में अपनी-अपनी फुटेज को लेकर भिड़ गई हैं. सूत्रों का कहना है कि जबसे लारा को पता चला है कि फ़िल्म में दीपिका को उनसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, वह मीडिया में अपने रोल को लेकर अटपटे बयान देने लगी हैं. फ़िल्म की यूनिट के मुताबिक़, ज़्यादातर रोमांटिक गानों का फिल्मांकन अक्षय और दीपिका पर हुआ है. यही वजह है कि लारा, दीपिका से नाराज़ हैं. कभी कॉस्टयूम को लेकर तो कभी कोरियोग्राफी पर दोनों के नख़रे शुरू हो जाते हैं. इससे पहले भी लारा फिल्म *अंदाज़* में और दीपिका फ़िल्म *बचना ए हसीनों* में इसी तरह का हंगामा कर चुकी हैं. दोनों की इस कैट फाइट से बेचारे साजिद का क्या हाल होगा, यह आप ख़ुद समझ सकते हैं.

उदिता को अक्षय का सहारा

आपको उदिता गोस्वामी तो याद ही होंगी? जी हां वही, जिन्होंने पूजा भट्ट द्वारा निर्देशित फ़िल्म *पाप* से बॉलीवुड में प्रवेश किया था. जब फ़िल्म नहीं चली तो *ज़हर* में उन्होंने जमकर अंग प्रदर्शन का नुस्ख़ा अपनाया, लेकिन वह असफल रहीं. उसके बाद फ़िल्म *अगर* में दिखाई दीं, पर किस्सा वही ढाक के तीन पात. अब उनके डूबते करियर को खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का सहारा मिल गया है. वह अक्षय कुमार के साथ एक फ़िल्म में काम कर रही हैं. दरअसल, अक्षय की फ़िल्म *पूरब की लैला, पश्चिम का छैला* 12 सालों से डिब्बे में बंद है. अब चूंकि अक्षय का बाज़ार गर्म है, और उनकी फ़िल्मों को ख़रीदने के लिए वितरकों की कमी नहीं है. इसलिए फ़िल्म के निर्माता ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का फ़ैसला किया है. उन्हें उम्मीद है कि किसी तरह इस फ़िल्म को पूरा करके थोड़ा बहुत मुनाफ़ा तो कमाया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने फ़िल्म का नाम बदलकर *हैलो इंडिया* रख लिया है ताकि कोई इसे पुराना प्रोजेक्ट समझकर इसे नकार न दे. पहले इस फ़िल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट नम्रता शिरोडकर काम कर रही थीं, पर अब साउथ के एक अभिनेता से विवाह रचाकर वह फ़िल्मों को अलविदा कह चुकी हैं. ऐसे में इसका फ़ायदा उदिता गोस्वामी को मिल गया. कहानी में फेरबदलकर उदिता को कथानक में फिट कर दिया गया है. ऐसे में उदिता का ख़ुश होना लाज़िमी है. आख़िर उन्हें अक्षय के साथ काम करने का मौक़ा जो मिल रहा है. अभी हाल ही में उदिता ने अक्षय कुमार के साथ इस फ़िल्म के लिए लंदन में प्रोमोशनल गीत भी शूट हुआ है. जब उदिता से इस बाबत पूछा गया तो उनका कहना था कि वह हमेशा से अक्षय के साथ काम करना चाहती थीं. इस फ़िल्म से उनका सपना पूरा होगा. इस गीत के फिल्मांकन में उनके साथ मशहूर पॉप सिंगर हार्ड कौर भी दिखाई देंगी. कहानी में फेरबदल के सवाल पर उनका कहना है कि कहानी में कई रोचक बदलाव किए गए हैं. इसलिए इसे पुरानी फ़िल्म न समझिए. साथ ही फ़िल्म का संगीत भी दोबारा तैयार किया गया है. ख़ैर जो भी हो, उदिता को इस फ़िल्म से बहुत आशाएं हैं. अब अक्षय कुमार का साथ उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सोहा अली ख़ान बहन नहीं बनेंगी

भट्ट कैंप में नई नई शामिल हुई सोहा अली ख़ान मानती हैं कि इस कैंप के साथ उनकी साझेदारी लंबी चलेगी. आने वाली फ़िल्म *लाइफ गोज़ ऑन* में उन्होंने अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ स्क्रीन शेयर किया है. शूट के वक़्त सोहा ने चाहे जितने भी अच्छे शॉट दिए हों, पर एक अच्छी मां की तरह शर्मिला उन्हें नसीहत देने से नहीं चूकती थीं. नई फ़िल्म को लेकर सोहा उत्साहित हैं. मां के साथ काम करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, पर क्या वह अपने भाई सैफ अली ख़ान के साथ काम करेंगी? इस बाबत वह कहती हैं कि सुपरस्टार भाई सैफ अली ख़ान के साथ फ़िल्म करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फ़िल्म में वह सैफ की बहन का रोल कतई नहीं करेंगी. आख़िर यह रील लाइफ होगी और ज़रूरी नहीं है कि उसमें निजी रिश्तों को अहमियत दी ही जाए.

सोनाली साइज जीरो से प्रभावित नहीं

ख़ूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड में छाए साइज़ ज़ीरो के ट्रेंड से ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं. वह कहती हैं कि महिलाओं को फेमीनिन होना चाहिए और इस स्तर पर वह बिल्कुल फिट हैं. हालांकि उनका वजन पहले से आठ किलो ज़्यादा बढ़ गया है, पर उनकी छरहरी काया की वजह से इसका पता नहीं चल पाता है. इसके लिए वह शुक्रगुज़ार हैं अपनी जींस की. रुपहले पर्दे पर वापसी की चाह में सोनाली ने हाल ही में बतौर जज कुछ रियलिटी टीवी शोज भी किए थे. वह बिना साइज जीरो फिगर के स्लिम ट्रिम नज़र आती हैं. फ़िल्मों में वापसी के सवाल पर वह कहती हैं कि उनका बेटा रणवीर सयाना हो चुका है और अभी इंडस्ट्री से ज़्यादा उनके बेटे को उनकी ज़रूरत है. यही वजह है कि सोनाली कुछ टीवी कमर्शियल और शोज में नज़र आएंगी, पर फ़िल्मों से दूर ही रहेंगी. सोनाली मानती हैं कि साइज जीरो फिगर उनके लिए ठीक नहीं है.

आने वाली फ़िल्म

बोलो राम

यह फ़िल्म आगामी 31 दिसंबर को प्रदर्शित होगी. इस फ़िल्म के ज़रिए नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी अर्से के बाद एक साथ दिखाई देंगे. इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरी को भी एक महत्वपूर्ण किरदार में देखा जा सकेगा. श्री केशव फिल्म्स के गोल्डी भूटानी द्वारा निर्मित फ़िल्म *बोलो राम* से नवोदित अभिनेता ऋषि भूटानी अपनी पारी शुरू कर रहे हैं. फ़िल्म में ऋषि पर मां के क़त्ल का इल्ज़ाम है. ओमपुरी और नसीर इस मामले की ही गुत्थी को सुलझाते हैं. निर्देशन राकेश चतुर्वेदी का है और संगीत सचिन गुप्ता का है.

रात गई, बात गई

फ़िल्म *रात गई, बात गई* भी 31 दिसंबर को ही प्रदर्शित होगी. प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशन के बैनर तले बनी इस फ़िल्म को सौरभ शुक्ला ने निर्देशित किया है. इस फ़िल्म में कई सितारे कॉमेडी करते नज़र आएंगे. इनमें विनय पाठक, रनवीर शौरी और नेहा धूपिया के अलावा रजत कपूर और इरावती हर्षे जैसे सितारे दिखाई देंगे. प्रीतीश नंदी ने काफ़ी दिनों के बाद फिल्म निर्माण में वापसी की है. पिछली बार उन्होंने *चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट* का निर्माण किया था. उनकी इस नई फ़िल्म में तीन जोड़े हैं, जिनका शादी को लेकर अलग-अलग नज़रिया है. एक पार्टी में नशे में हुई एक छोटी सी ग़लती के चक्कर में सारे किरदार एक-दूसरे पर शक़ करते हैं. बस यहीं से कहानी में हास्य पैदा होता है. यह फिल्म ब्लैक कॉमेडी है. इस फिल्म संगीत अंकुर तिवारी ने तैयार किया है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

www.chauthiduniya.com

नेताओं की नई फ़ौज तैयार

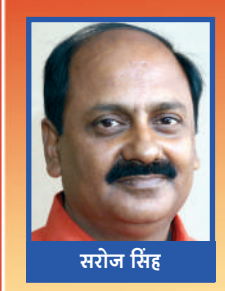

सरोज सिंह

आप गांव के किसी चौपाल में चले जाइए या फिर राजधानी पटना के सत्ता के गलियारों में, वहां राजनीतिक बहस की शुरुआत नीतीश कुमार, लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान के नामों से होती है और घंटों बाद अपनी-अपनी जिद के साथ फिर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है. पिछले दो दशकों से यही तीनों नेता बहस के हीरो रहे हैं. यह अलग बात है कि कुछ बाहुबलियों ने कुछ समय तक उनकी बादशाहत में खलल डाली और महफिल लूट ली, लेकिन सभी दलों में इस दौरान युवा नेताओं की एक ऐसी नई फ़ौज भी तैयार हुई, जिसकी आंखों में अपनी पार्टी और बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का सपना पल रहा है. नेताओं की इस नई फ़ौज के अपने आदर्श हैं, अपनी योजना और राजनीति में आगे बढ़ने की रणनीति है. उनके दिल में जहां अपने दल के बड़े नेताओं के प्रति पूरा सम्मान है, तो वहीं विरोधी दलों के नेताओं को चुनावी अखाड़े में परास्त करने की हसरत भी. पार्टी के अंदर बड़े नेताओं का झोला ढोने वाला, पिछलग्गू और चमचा जैसे न जाने कितने तानों से रोज नवाजी जाने वाली यह नई ताक़त जनता की अदालत में अगर अपनी योग्यता-क्षमता साबित कर पाई तो देर-सबेर इसी से कोई बहस शुरू होगी और ख़त्म भी.

पिछले बीस सालों में भाजपा चूंकि ज़्यादातर विपक्ष की भूमिका में रही, इसलिए उसके कई नए चेहरों को संघर्ष का मौक़ा मिला. राजनीति में बड़ा नाम करने का जज्बा रखने वाले कई नेताओं ने लालू-राबड़ी शासनकाल में जनता से जुड़े मसलों को अनेक मंचों व सड़कों पर जमकर उठाया. इस कारण जनता के बीच इन नेताओं की अपनी पहचान तो बनी ही, पार्टी के अंदर भी उनको सम्मान मिलना शुरू हो गया.

वर्ष 1987 से राजनीति में सक्रिय भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन कॉलेज छात्रसंघ के चुनाव ने उनकी दिशा ही बदल दी. अब वह डॉक्टर के बजाए संसदीय प्रणाली का हिस्सा बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं. पटना की सड़कों पर उन्होंने कई बार आंदोलन का नेतृत्व किया. राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श नेता मानने वाले मयूख उन्हीं की तरह ईमानदारी के साथ राजनीति के मानदंडों पर खरा उतरना चाहते हैं. संजय का मानना है कि भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है. वह पार्टी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठन एवं समाज की सेवा करते रहना चाहते हैं. अगर कभी सत्ता संभालने का मौक़ा मिला तो मयूख सबसे पहले बातचीत के माध्यम से नक्सलवाद का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. जनता से मिल रहे प्यार के लिए वह उसे धन्यवाद देना चाहते हैं. इसी तरह वर्ष 1990 से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली भाजपा की प्रदेश सचिव उषा विद्यार्थी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी एवं सुषमा स्वराज को अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही हैं. उन्हें अगर सत्ता की चाबी मिली तो वह महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास करेंगी. उनका मानना है कि महिलाओं को पंचायतों एवं नगरपलिकाओं में पचास प्रतिशत आरक्षण तो मिल गया, लेकिन सम्मान नहीं मिल सका. महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, इसलिए वह सबसे पहले शिक्षा में सुधार का प्रयास करेंगी. उषा अपने पिता के साथ बचपन से ही राजनीति में सक्रिय थीं. सुशील कुमार मोदी से मुलाकात के बाद वह भाजपा में शामिल हुईं. अब तो संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं. अपने काम के सहारे वह अपनी पहचान बनाना और बिहार को आगे ले जाना चाहती हैं.

मंगल पांडेय छात्र जीवन से राजनीति में आ गए. स्कूल की एक घटना उन्हें राजनीति में ले आई. दीन दयाल उपाध्याय को अपना आदर्श मानने वाले पांडेय संसदीय राजनीति का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं. उन्हें सत्ता की चाबी मिली तो वह बिहार से पलायन को रोकेंगे. पांडेय चरित्रवान कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे लाना चाहते हैं.

वर्ष 1980 से राजनीति म

सक्रिय पटना महानगर के पूर्व अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एवं कैलाशपति मिश्र को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर समाज सेवा करना चाहते हैं. छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हरेंद्र विधायक बनकर सरकारी योजनाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत लागू करवाना चाहते हैं. वह कहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की आलोचना न करे, लेकिन पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए.

इसी तरह जदयू में भी युवा नेताओं की एक बड़ी फ़ौज तैयार होकर खड़ी है और चाहती है कि जिस तरह नीतीश कुमार राज्य को आगे बढ़ाने में रात-दिन लगे हैं. ठीक उसी तरह वह भी भविष्य में राज्य की सेवा कर सकें. 2005 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कड़ी टक्कर देने वाले जदयू नेता एवं प्रदेश सचिव सतीश कुमार राघोपुर के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं. वह मुख्यमंत्री बनकर बिहार की तक़दीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं. वह वर्गवाद एवं जातिवाद को समाप्त कर समाज की अंतिम पंक्ति में जीवनयापन करने वाले नागरिकों को मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं. छात्र जीवन में कॉलेज की राजनीति करते हुए 1989 में राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने वाले सतीश कुमार, मंडल मसीहा एवं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना आदर्श मानते हैं. दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह कहते हैं कि 2005 के चुनाव में तो राबड़ी देवी कुछ मतों से जीत गईं, लेकिन 2010 के चुनाव में राघोपुर की जनता उन्हें हराएगी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद राबड़ी देवी कभी क्षेत्र में नहीं गईं.

वर्ष 1987 से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जदयू प्रवक्ता रविंद्र सिंह बिहार को आगे ले जाने के लिए पहले गांव का विकास करना चाहते हैं. वह हर गांव को राजधानी पटना की तरह सुसज्जित एवं विकसित करके शहर और गांव की खाई को पाटना चाहते हैं. रविंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं और उनके कार्यों से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं. नागेश्वर स्वराज को अगर सत्ता की चाबी मिली तो वह सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे. समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, ताकि राज्य का एक भी आदमी अशिक्षित न रहे. वह 1989 में पहली बार चौधरी देवीलाल के स्वागत में ग्रीन ब्रिगेड का पट्टा लगाकर राजनीति में कूदे तो फिर उसी में रम गए. नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानने वाले स्वराज कम से कम एक बार सांसद बनकर लोकसभा में ऐसा भाषण देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया उनकी बातों को प्रमुखता दे. युवा जदयू उपाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार, नीतीश कुमार एवं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं. वर्ष 1984 से राजनीति में सक्रिय अशोक संसदीय प्रणाली का हिस्सा बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं. उन्हें अगर सत्ता की चाबी मिली तो वह ग़रीबों को अमीरों के अत्याचार से मुक्त कराएंगे.

सत्ता में रहते राजद के युवा नेताओं के जो चेहरे छिपे थे, वे नीतीश शासनकाल में उभरने लगे हैं. लालू के हनुमान की भूमिका निभाने वाले अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह 18 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं. छोटू, लालू प्रसाद को अपना आदर्श मानते हैं. वह जीवन भर एक बेटे की तरह लालू प्रसाद और पार्टी की सेवा करना चाहते हैं. उन्हें अगर कभी सत्ता की बागडोर मिली तो बिहार को हरियाणा और पंजाब की तरह देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने की हसरत रखते हैं. छोटू को राजनीति विरासत में मिली. उनके दादा गौरी शंकर सिंह कश्यप कांग्रेस में सक्रिय रहकर समाज की सेवा करते रहे. बचपन से उनके साथ रहकर आम लोगों की सेवा करते-करते छोटू राजनीति में आ गए. उनका एक ही सपना है कि वह जनता के सुख-दु:ख में शामिल होकर उसकी समस्या का समाधान करें.

बीस वर्षों से राजनीति में सक्रिय राजद प्रदेश सचिव शक्ति सिंह यादव को अगर मौक़ा मिला तो वह सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे. अमीर हो या ग़रीब, सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराएंगे. छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्यधारा में आने वाले शक्ति सिंह लालू प्रसाद को अपना आदर्श मानते हैं. वह कहते हैं कि लालू प्रसाद ने ग़रीबों को आवाज़ के साथ सम्मान भी दिया. शक्ति एक बार शिक्षा मंत्री बनकर शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं. इसी तरह सुपौल में अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने वाले अजय कुमार का सपना मिथिला को हर मायनों में विकसित करना है. कोसी के कहर से मिथिलांचल के लोगों को हुई परेशानी से अजय कुमार इतने व्यथित हुए कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में कूदकर जनता की सेवा को अपना धर्म बना लिया. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे अजय कुमार चाहते हैं कि राजद एक बार फिर बिहार की सत्ता में लौटें. वह लालू प्रसाद को देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं. वर्ष 1990 के मंडल आयोग आरक्षण आंदोलन से राजनीति में आने वाले स्वदेश कुमार, कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं. वह सांसद बनकर गांव की जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं. सत्ता की चाबी मिली तो वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे.

लोजपा नेता शाहनवाज कैफी वर्ष 1981 से राजनीति में सक्रिय हैं. पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक होने के कारण उन्हें अपने पिता से विरासत में राजनीतिक गुण मिले. वह कॉलेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय हो गए. कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले शाहनवाज सत्ता की बागडोर मिलने पर सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं. विधायक बनकर हायाघाट में अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

संजय मयुख

भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है. मैं पार्टी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठन एवं समाज की सेवा करना चाहता हूं.

उषा विद्यार्थी

महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा में सुधार का प्रयास करूंगी.

सतीश कुमार

मैं वर्गवाद एवं जातिवाद को समाप्त कर समाज में हाशिए पर रह कर जीवनयापन करने वाले नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहता हूं.

रविन्द्र सिंह

हर गांव को राजधानी पटना की तरह सुसज्जित एवं विकसित करके शहर और गांव की खाई को पाटना चाहते हैं.

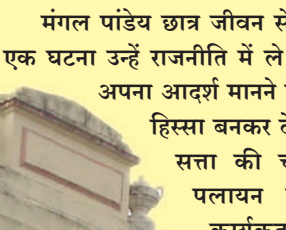

नागेश्वर स्वराज

सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे. समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, ताकि राज्य का एक भी आदमी अशिक्षित न रहे.

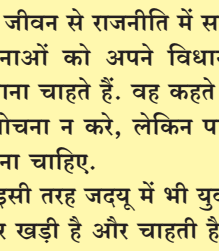

छोटू सिंह

सत्ता की बागडोर मिली तो बिहार को हरियाणा और पंजाब की तरह देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने की हसरत रखते हैं.

शक्ति सिंह

मुझे अगर मौक़ा मिला तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है. अमीर हो या ग़रीब, सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराना है.

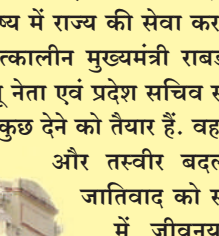

अजय सिंह

मिथिला को हर मायने में विकसित करना है. कोसी के कहर से मिथिलांचल के लोगों को बचाना है और जनता की सेवा करना है.

केशव सिंह

गांव की स्थिति में सुधार लाएंगे. अमीर-ग़रीब सबको एक समान शिक्षा देकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे.

ललन यादव

लोगों का भरोसा कांग्रेस पर लगातार बढ़ रहा है और आगामी चुनाव में पार्टी ज़रूर अपना परचम लहराएगी.

समुचित देखरेख और मरम्मत के अभाव में हक़ साहब की स्मृति के नाम पर यह आशियाना अब खंडहर मात्र ही रह गया है.

इस तरह की शादियां अक्सर टूट जाती हैं. अगर शादी नहीं भी टूटती है, तो वर और वधू के रिश्ते इतने तल्ख हो जाते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन में ज़हर घुल जाता है.

मेरे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी: शिबू सोरेन

झारखंड आंदोलन के प्रणेता और राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन वहां की ज़मीन से जुड़े रहे हैं. उन्होंने बग़ैर किसी दल से तालमेल किए अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर भाजपा–कांग्रेस दोनों को कड़ी चुनौती दी है. सोरेन ने यह दावा किया है कि झारखंडियों का कायाकल्प झामुमो ही कर सकता है. यहां के निवासियों की पीड़ा को उन्होंने नज़दीक से देखा है. सूबे के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनज़र उन्होंने चौथी दुनिया से विशेष बातचीत की. प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश:

फोटो–प्रभात पाण्डेय

झारखंड के ताज़ा राजनीतिक हालात को आप किस नज़र से देखते हैं?

हमने चालीस साल के राजनीतिक सफ़र में झारखंड की ग़रीबी, लाचारी और सामंती ज़ुल्मों का अंतहीन सिलसिला देखा है. उसके ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई लड़ी है. उसके बाद हमें झारखंड अलग राज्य के रूप में प्राप्त हुआ है. इस राज्य को सिर्फ़ लूटा गया है. हम अगर कुछ दिन और सत्ता में बने रहते तो लूट का माल किसी को लेकर नहीं जाने देते. मेरा दावा है कि झामुमो ही इस राज्य का कल्याण कर सकता है. यहां के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा झामुमो ही तय कर सकता है. जब तक भ्रष्टाचारियों को यहां से खदेड़ा नहीं जाएगा, तब तक यहां अमन–चैन नहीं आएगा.

राज्य में अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में न हुए तो किसे समर्थन देंगे?

चुनाव परिणाम आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि अगर हम सत्ता के क़रीब पहुंचे तो जो हमें वाजिब हक़ देगा, उसी को समर्थन देंगे. चुनाव के नतीजे आने के बाद हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे.

आपकी इस बात का क्या मतलब निकाला जाए?

झामुमो के समर्थन के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी. मैं यह नहीं मानता हूं कि बहुमत झामुमो को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा. यहां जनता को जो जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार दिलाएगा, उसी को हम समर्थन देंगे.

भाजपा और कांग्रेस में से किसे चुनेंगे?

हमने पहले ही कहा है कि चुनाव के बाद अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन किसके साथ करेंगे, यह हम अभी नहीं बता सकते. मुझे ही समर्थन मिल गया तो फिर किसी और को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है. चुनाव परिणाम का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ साफ़ हो जाएगा.

राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति आपका क्या नज़रिया है?

राष्ट्रीय पार्टियां ही झारखंड की दुर्गति की ज़िम्मेदार हैं. दिल्ली के इशारे पर यहां की सरकार नहीं चलाई जा सकती है. उन्हें यहां की क्षेत्रीय समस्याओं की समझ नहीं है और वे इसे समझना भी नहीं चाहते हैं. अब तक तो यही हुआ है. वे झारखंड के विकास के प्रति गंभीर नहीं रहे. दिल्ली दरबार से जुड़े लोग राज्य को लूटने में मग्न रहे. यहां का कोयला दूसरे राज्यों में बेचकर मालामाल हो गए और यहां के निवासी जंगल की लकड़ी काटकर अपना जीवन गुज़ार रहे हैं. हमारी पार्टी शुरू से इसके ख़िलाफ़ आंदोलन करती रही है. यहां के खनिजों का दोहन कर विदेशों में पैसा लगाया जा रहा है. हम यह सब नहीं चलने देंगे.

आप दो बार मुख्यमंत्री बने, फिर भी सरकार में स्थिरता नहीं रही. इसकी वजह?

हमें दो बार मुख्यमंत्री बनने का मौक़ा मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ साज़िश रचकर सहयोगियों ने हमें गच्चा दे दिया. हमें जनता की सेवा करने का ठीक से मौक़ा ही नहीं दिया गया. कांग्रेस ने तो सोची–समझी साज़िश के तहत तमाड़ में हराने का काम किया. इसलिए हमने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया. अब यह जनता के ऊपर है कि झारखंड की माटी का वह सम्मान करती है या दिल्ली से थोपे गए निर्णय को अपनाती है.

आपके पुराने साथी सूरज मंडल के आने से पार्टी में क्या फ़र्क़ नज़र आ रहा है?

सूरज हमारा पुराना साथी है. बीच में रास्ता भटक गया था, अब उसकी घर वापसी हो गई है. इससे पार्टी मज़बूत हुई है. यहां की जनता हम दोनों को दोबारा साथ देखकर उत्साहित है. इसका फ़ायदा हमें चुनाव में मिलेगा. संथाल परगना में हमारी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ है. पलामू प्रमंडल में भी हमारे पक्ष में परिणाम आएगा.

झामुमो उग्रवादियों को टिकट देकर जनता में क्या संदेश देना चाहता है?

उग्रवादी कोई विदेश से नहीं आए हैं. वे हमारे ही भाई–बंधु हैं. वह सदियों से शोषित हैं. अगर वे समाज की मुख्यधारा में आना चाहते हैं तो इसमें हर्ज़ क्या है? उन्हेंने लोकतंत्र में विश्वास जताया है, तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए. हिंसा और हथियार छोड़कर समाज के लिए कोई काम करना चाहता है, तो उसे मौक़ा मिलना चाहिए. झामुमो ने उन्हें बुलेट की जगह बैलेट की धारा में लाने की कोशिश की है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा. हमारी सरकार बनी तो उग्रवादियों से आमने–सामने की बातचीत होगी. इससे राज्य में ख़ूनख़राबा बंद होगा. उग्रवादियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनेगी. जल, जंगल, ज़मीन भी बचेंगे और हर हाथ को काम तथा हर खेत को पानी मिलेगा.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthidunya.com

झारखंड का सूरतेहाल

नेता मालामाल, जनता कंगाल

झारखंड राज्य को सबने लूटा, खूब जमकर लूटा. नेताओं और नौकरशाहों ने मिल कर सरकारी ख़ज़ाने को पूरी तरह से खंगाल डाला. जल, जंगल और ज़मीन के मामले में धनी समझा जाने वाला राज्य झारखंड खनिज और उद्योग के लिहाज़ से भी समृद्ध है, लेकिन जब सत्ता से लेकर सड़क तक लुटेरे ही बैठे हों तो संसाधन किस काम का? कोई विकास और समृद्धि के बारे में सोचने की भी ज़हमत क्यों उठाए? हां, अपनी सुविधाओं में कोई कमी न हो इसका ख्याल उन्होंने ज़रूर रखा. आज हाल यह है कि झारखंड के नेताओं को माल कमाने से फ़ुर्सत नहीं है. जनता अपनी बदक़िस्मती पर आंसू बहा रही है.

तीव्र अव्यवस्था और घोटालों के बीच झारखंड की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है. बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य गठित होने के बाद झारखंड आर्थिक लुटेरों का चरागाह बन चुका है. झारखंड राज्य के गठन का मूल उद्देश्य ही अर्थहीन हो गया है. जनता की बदहाली बढ़ी है और नेताओं की ख़ुशहाली भी बढ़ी है. आलम यह है कि जो नेता कल तक साइकिल पर चलते थे, आज वे चमचमाती कारों में सफ़र कर रहे हैं. झारखंड सरकार के विधायक, सचेतक, विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित मंत्रियों पर चार साल में 82.5 करोड़ रुपये वेतन, भत्ते व अन्य सुख–सुविधाओं पर ख़र्च हुए हैं, लेकिन जनता को बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हो सकीं. हालांकि राष्ट्रपति शासन के दौरान सूबे में कुछ काम ज़रूर हुए. मगर, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ़ अपनी तिजोरी भरने में लगे रहे.

आज़ादी के बाद सबसे बड़े घोटालों में से एक आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद मधुकोड़ा को निगरानी ब्यूरो ने अंततः चाईबासा में गिरफ़्तार कर लिया. साथ ही पूर्व मंत्री कमलेश सिंह भी हुसैनाबाद में दबोच लिए गए. हालांकि इन गिरफ़्तारियों में निगरानी ब्यूरो ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखलाई. 30 नवंबर को निगरानी अदालत ने उनके विरुद्ध गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया और उसके कुछ ही घंटे बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए. निगरानी ब्यूरो के पास इसके अलावा पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही और नलिन सोरेन के विरुद्ध भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज़ है, लेकिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उनकी गिरफ़्तारी की कोई पहल नहीं की गई थी. यदि निगरानी की यह फुर्ती स्वाभाविक थी और इसे कहीं से प्रेरित नहीं किया गया था तो उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है. दो पूर्व मंत्री एनोस एक्का और हरिनारायण सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं. राज्य में 100 करोड़ रुपये का अलकतरा घोटाला, 25 करोड़ का नमक घोटाला, 103 करोड़ का दवा और 37 करोड़ का मेडिकल उपकरण घोटाला, दस करोड़ का खाद–बीज घोटाला, 300 करोड़ का बिजली बोर्ड घोटाला, विधानसभा नियुक्ति घोटाला, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बहाली घोटाला आदि काफ़ी चर्चित रहे हैं. इसके अलावा 51 करोड़ रुपये के हेलीकाप्टर दुरुपयोग मामले की जांच चल रही है. झारखंड राज्य गठन के नौ वर्षों में हुए घोटालों पर ग़ौर करें तो कोड़ा प्रकरण समेत अब तक पांच हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी हो चुकी है. इस प्रकार की लूट ने सरकारी राजस्व को जबर्दस्त झटका लगाया है. राज्य की विडंबना देखिए कि जन प्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाओं में छह बार बढ़ोतरी की गई. वहीं विकास मद की सात हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि सरेंडर कर दी गई. सरकारी ख़र्च में भी बेतहाशा वृद्धि होती गई. वहीं विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नौकरशाहों की उदासीनता और वित्तीय अनियमितता सहित राजस्व मद में चोरी जैसे भ्रष्टाचार ने राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है. आंकड़ों पर ग़ौर करें तो राज्य गठन के वक़्त झारखंड में प्रति व्यक्ति क़र्ज़ का बोझ जहां दो हज़ार रुपये था, वह बढ़कर अब सात हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति हो गया है, जबकि सूबे का शायद ही कोई विधायक या सांसद ऐसा होगा जो करोड़पति होने की हैसियत नहीं रखता हो.

मधु कोड़ा

राज्य गठन के बाद तीन वर्षों तक झारखंड का बजट सरप्लस रहा था. 2004–05 के वित्तीय वर्ष में पहली बार घाटे का बजट पेश किया गया. तत्कालीन वित्त मंत्री मुगींद्र प्रताप सिंह ने उस वक़्त कहा था कि कैडर विभाजन नहीं होने के कारण तीन वर्षों तक सरप्लस बजट पेश किया था. उसके बाद झारखंड लगातार क़र्ज़ ले रहा है और घाटे का बजट पेश कर रहा है. अपरिपक्व विधायिका और नौकरशाहों की अदूरदर्शिता से वित्तीय प्रबंधन में संतुलन नहीं हो पा रहा है. एक तरफ़ सरकार वित्तीय घाटे को पाटने के लिए क़र्ज़ ले रही है. वहीं दूसरी तरफ़ विकास मद के करोड़ों रुपये सरेंडर किए जा रहे हैं. वित्तीय कुप्रबंधन की बानगी देखिए कि राज्य निर्माण के समय सरकार का क़र्ज़ लगभग 6.5 हज़ार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 22 हज़ार करोड़ से भी अधिक हो गया है. अभी हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सरकार के 20 विभागों द्वारा करीब 10,500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिए जाने पर निगरानी जांच की मांग की गई है. एसोसिएशन ने वित्त सचिव पर घोटाले का आरोप लगाया है. महालेखाकार के पत्र लिखे जाने के बाद भी वित्त सचिव टाल– मटोल कर रहे हैं.

झारखंड उच्च न्यायालय में भी पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कई मामले लंबित हैं. वहीं सीबीआई में, पूर्व राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रज़ी के ओएसडी अविनाश कुमार और आईएएस डॉ. प्रदीप कुमार सहित दवा घोटाले के आरोपी डॉ. विजय शंकर नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है. पूर्व मंत्रियों के निजी सचिवों द्वारा अवैध तरीक़े से अर्जित की गई अकूत संपत्ति से संबंधित मामला भी झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. पूर्व मंत्रियों पर निगरानी कोर्ट में राजीव शर्मा के शिकायत के बाद कार्रवाई की जा रही है, जबकि मंत्रियों के 11 निजी सचिवों के विरुद्ध परमेश्वर चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. इन निजी सचिवों की संपत्ति की जांच के लिए प्रार्थी ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देने की कोर्ट से अपील की है. इस क्रम में पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के निजी सचिव मनोज कुमार सिंह के यहां आयकर का छापा पड़ा, जिसमें सारण स्थित एक ग्रामीण बैंक में 14 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपोजिट के काग़ज़ात मिले. यह बिहार और झारखंड में अब तक के फिक्स्ड डिपोजिट की सबसे बड़ी रक़म थी. एसएस मनी फंड घोटाले के आरोपी बीजीपी बीडी राम का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है. हालांकि झारखंड केपूर्व मुख्य सचिव एके बसु इस मामले की फाइल पर उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की है. दवा घोटाले के दो मामले और बिजली बोर्ड में घोटाले केमामले भी निगरानी ब्यूरो के पास लंबित हैं. जांच एजेंसियां इन घोटालों की परत–दर–परत जांच में लगी हुई है. इन घोटाला नायकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है, लेकिन यह तमाम जांच–पड़ताल किस मोड़ पर जाकर ठहर जाएगी, यह कहना मुश्किल है.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthidunya.com

पृष्ठ 17 का शेष

नेताओं की नई फ़ौज तैयार

प्रदीप दूबे | बागेश्वर मालाकार | अनिल शर्मा | रामचंद्र यादव | स्वदेश कुमार | सूरज यादव

लोजपा महासचिव केशव सिंह लोकनायक जय प्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते हैं. सत्ता की चाबी मिलने पर वह गांव की स्थिति में सुधार लाएंगे. अमीर–ग़रीब सबको एक समान शिक्षा देकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे. वह विधायक बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रोफेसर सूरज यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हैं. मौर्यकालीन युग में बिहार को पूरे विश्व में जो पहचान मिली थी, वह मुख्यमंत्री बनकर उसे फिर से दिलाना चाहते हैं. बिहार को हर क्षेत्र में देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं. वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे. पार्टी में सुधार की आवश्यकता बताते हुए वह चाहते हैं कि शरद पवार किसानों के हक़ में निर्णय लें और पार्टी को जन–जन तक पहुंचाने का काम करें. इसी तरह बसपा के रामचंद्र यादव ग़रीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए रात–दिन काम करना चाहते हैं. मायावती को अपना आदर्श मानने वाले रामचंद्र चाहते हैं कि समाज के निचले तबके के लोगों के लिए ऐसी नीतियां बने, जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक हों. वह कहते हैं कि जनता मायावती के हाथों में देश की बागडोर सौंपे, ताकि समाज के हर वर्ग का कल्याण हो सके. कांग्रेस के ललन यादव की इच्छा है कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बने और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनें. ललन यादव का मानना है कि राज्य के लोगों का भरोसा कांग्रेस पर लगातार बढ़ रहा है और आगामी चुनाव में पार्टी ज़रूर अपना परचम लहराएगी.

ये कुछ ऐसे नेता हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए अपनी भूमिका तय कर रखी है. इनके अलावा भी बहुत सारे युवा चेहरे हैं, जो अलग–अलग पार्टियों में रहकर राज्य और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. किसका सितारा चमकेगा या फिर कौन रास्ते से भटक जाएगा, यह सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में नेताओं की एक ऐसी बड़ी फ़ौज तैयार हो चुकी है, जो राजनीति की पिच पर लंबी पारी खेलने को बेताब है.

feedback@chauthidunya.com

मौलाना मजहरूल हक़ का आशियाना खंडहर बना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कई दशकों तक हिन्दू–मुस्लिम एकता को नई दिशा देने वाले मौलाना मजहरुल हक़ का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. इतिहास में अब उनकी यादें ही शेष हैं. हम उनकी यादों को ज़िंदा रख सकते हैं, उनसे जुड़ी चीज़ों, इमारतों आदि की हिफ़ाज़त कर. मगर अफ़सोस कि हम ऐसा नहीं कर पाए. हक़ साहब की यादों से जुड़े उनके ऐतिहासिक 'आशियाना' और 'मज़ार' की दुर्दशा देखकर हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं. बिहार के सीवान ज़िला मुख्यालय से क़रीब 15 किमी दक्षिण स्थित एक गांव है फरीदपुर. फरीदपुर के पश्चिम में हक़ साहब का वीरान हो चला आशियाना अपने हाल पर आंसू बहा रहा है. समुचित देखरेख और मरम्मत के अभाव में हक़ साहब की स्मृति के नाम पर यह आशियाना अब खंडहर मात्र ही रह गया है. हक़ साहब फूलों के बहुत बड़े शौक़ीन थे. इसलिए उन्होंने अपने इस आशियाने के पास लगभग एक एकड़ ज़मीन पर सैकड़ों क़िस्म के फूलों की बहुत बड़ी फुलवारी लगवाई थी. मगर, देखभाल के अभाव में वाणगंगा नदी के तट पर बसे इस मज़ार और आशियाने के आसपास आज सब कुछ समाप्त है. आज तक हक़ साहब का एक भी स्मारक न तो उनके गांव फरीदपुर

में स्थापित किया जा सका है और न ही सीवान शहर में. सीवान शहर में अनेक सड़कें हैं, जिसमें कुछ का नया नामकरण भी विगत सालों में किया गया. यहां हक़ साहब के नाम पर एक सड़क तो क्या एक गली तक नहीं है. किसी बड़ी संस्था का नाम उनके नाम पर होगा, इस बारे में तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है. अलबत्ता सीवान स्थित ललित बस पड़ाव का नाम बदलकर मौलाना मजहरूल हक़ बस पड़ाव ज़रूर कर दिया गया है. सीवान रेलवे स्टेशन से पूरब पक्की सड़क चौक के पास हक़ साहब की स्मृति में बन रहे 25 फीट लंबे और 16 फीट चौड़े स्मृति स्तम्भ निर्माण अभी भी पूरा नहीं हो सका है.

22 दिसंबर, 1866 में पटना के ब्रह्मपुरा में जन्मे मौलाना मजहरूल हक़ का इंतकाल 2 जनवरी, 1930 को हो गया. हक़ साहब निनिहाल फरीदपुर में पले–पढ़े और वहीं उनका बचपन बीता. युवावस्था में वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े. उन्होंने अपनी कर्मभूमि अपने ननिहाल फरीदपुर को ही बनाया. इस गांव का पूरा नाम 'रमना फरीदपुर' है. इसी गांव में 1902 में हक़ साहब ने अपना आशियाना बनवाया था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. हक़ साहब के परिवार के लोग पटना में रहते हैं. उनके पौत्र अब्दुल फ़ारूक़ी एवं वारिश अली फारूक़ी ने बताया कि पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए दो एकड़ 27 डिसमिल ज़मीन पूर्व सरकार को दे दी गई है, जिसका हलफ़नामा भी 23 नवंबर, 2008 को कर दिया गया है. 24 नवंबर, 2008 को अंचलाधिकारी हसैनगंज को खाता खेसरा सहित ज़मीन का ब्यौरा भी दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि ज़िले एवं प्रमंडल से जो फाइलें पटना जाती हैं, उसके मुख्य काग़ज़ात भी गायब हो जाते हैं!

धनंजय मिश्र
feedback@chauthidunya.com

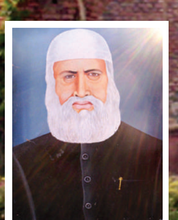

मौलाना मजहरूलहक

वरमाला पहनाओ, नहीं तो गोली खाओ

बंदूक की नोंक पर शादी

कोसी और मिथिलांचल इलाक़े में बंदूक की नोंक पर शादी कराने की परंपरा धीरे–धीरे ज़ोर पकड़ती जा रही है. इस तरह की शादी को समाज के लोगों द्वारा पकड़ौआ शादी की संज्ञा दी गई है. बावजूद इसके अधिकतर लोग इसे जघन्य अपराध नहीं मानते हैं. हालांकि इस तरह की शादियां अक्सर टूट जाती हैं. अगर शादी नहीं भी टूटती है, तो वर और वधू के रिश्ते इतने तल्ख हो जाते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन में ज़हर घुल जाता है. फिर भी इस तरह की शादियों का सिलसिला थमने के बजाय ज़ोर पकड़ रहा है.

एक अनुमान के मुताबिक़ इन इलाक़ों में प्रतिवर्ष लगभग 80–85 जोड़े की शादी बंदूक की नोंक पर होती है. इतना ही नहीं इस तरह की शादी कराने के लिए कई गिरोह इस इलाक़े में सक्रिय हैं. अगर अन्य जगहों की बातों को छोड़ दिया जाए तो खगड़िया एवं बेगूसराय में पकड़ौआ शादी कराने के लिए कम से कम आधा दर्ज़न गिरोह सक्रिय हैं. ऐसा नहीं है कि इस तरह का रिवाज समाज में बन गया हो, लेकिन दहेज लेने–देने पर प्रतिबंध के बावजूद जब लड़कियों की शादी वगैर दहेज के संभव नहीं हो पाती है, तो बेबस लड़कियों के पिता और अन्य परिजनों इस तरह की शादी कराने के लिए गिरोह के सदस्यों से सम्पर्क करते हैं और सोची– समझी योजना के तहत लड़के का अपहरण कर उसकी शादी करा दी जाती है.

पकड़ौआ शादी के लिए सक्रिय गिरोह के सदस्यों से जब संपर्क साधा गया, तो पहले गिरोह के सदस्यों ने खुलकर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जब उनसे नज़दीकियां बढ़ाई गईं, तो इन लोगों ने हक़ीक़त बयां करना शुरू कर दिया. सबसे आश्चर्य की बात यह कि इस तरह की शादी कराने में जुटे गिरोह के सदस्य इसे अपराध नहीं मानते. पकड़ौआ शादी कराने वाले गिरोह से ताल्लुक़ात रखने वाले बेगूसराय ज़िले के रामदीरी निवासी अशोक की बातों पर अगर ग़ौर करें तो इस तरह की शादी के लिए लड़के वालों द्वारा जब वधू पक्ष के लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, तो उस वक़्त इस तरह की शादी के लिए लड़की पक्ष वाले विवश हो जाते हैं. फिर लड़के को किसी तरह जाल में फांसकर उसे लड़की वालों के हवाले कर दिया जाता है. ग़ौरतलब है कि जब तक शादी हो नहीं जाती है, तब तक स्थिति पर नियंत्रण रखना गिरोह के सदस्यों का दायित्व होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद माहौल पर क़ाबू रखना लड़की पक्ष के लोगों की ज़िम्मेदारी बन जाती है. अधिकतर वधू पक्ष के लोग शादी होने के बाद औक़ात के हिसाब से वर पक्ष के लोगों को ख़ुश करने के लिए नकदी और अन्य सामान देते हैं. अशोक ने एक मर्मस्पर्शी कहानी सुनाते हुए कहा कि बेगूसराय ज़िले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में रधिया नाम की एक लड़की, जो बेहद ग़रीब परिवार से आती थी, दिखने में तो वह काफी सुन्दर थी, लेकिन जगह–जगह भटकने के बाद भी उसके पिता रामबालक सिंह अपनी बिटिया के लिए योग्य वर की तलाश नहीं कर पा रहे थे. ऐसा नहीं था कि लड़के वाले उसे पसंद नहीं करते थे. पसंद तो सभी करते थे, लेकिन जब दान–दहेज की बात सामने आती थी, तो रामबालक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती थी. रामबालक दहेज देने के मामले में अपने को बेबस बताते थे. जिससे लड़के वाले शादी करने से मना कर देते थे. इस तरह का वाक्या बार–बार सामने आने के बाद रामबालक टूट गए. रधिया आत्महत्या तक की बात सोचने लगी थी. बाप–बेटी की स्थिति देखकर गांव के लोगों ने रधिया की पकड़ौआ शादी कराने की ठान ली, लेकिन सवाल यह था कि आख़िर किससे और कैसे रधिया की शादी होगी. किसी ने रामबालक को पकड़ौआ शादी कराने वाले गिरोह से संपर्क करने की सलाह दी. उन्होंने अपनी सारी स्थिति से गिरोह के सदस्यों को वाक़िफ़ कराया. गिरोह के सदस्यों ने बग़ैर राशि लिए रधिया की शादी कराने के लिए हामी भर दी. एक धनाढ्य परिवार के लड़के को देखा गया. वर पक्ष के द्वारा दहेज के रूप में मांगी गई रक़म देने के प्रति रज़ामंदी भी दिखा दी गई. इस बहाने लड़के तथा उनके परिजनों की पारिवारिक कुंडली मिलाई गई. फिर एक दिन मौक़ा ताड़कर लड़के का अपहरण कर लिया गया और रधिया की शादी करा दी गई. शादी के बाद लड़के वालों ने अपने रसूख़ का हवाला देकर रधिया को छोड़ देने की बात की, लेकिन समाज के अन्य लोगों ने रधिया के पति और ससुरावालों पर ऐसा दबाव बनाया कि रधिया की ज़िंदगी संवर गई. अशोक बताते हैं कि किसी ग़रीब लड़की का हाथ पीले कर उन लोगों ने आख़िर क्या गुनाह किया. अशोक के मुताबिक़ उनके 17 सदस्यीय गिरोह के द्वारा सात वर्षों में कम से कम डेढ़ सौ लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है. अगर वर पक्ष के द्वारा दहेज के नाम पर वधू पक्ष के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाय और बग़ैर दहेज के शादी होने लगे तो फिर पकड़ौआ शादी कराने के लिए लोग विवश ही क्यों होंगे. इसी तरह खगड़िया ज़िले के मुफ़स्सिल थाना अंतर्गत भदास गांव के मनोज महतो का भी इस तरह के गिरोह से अच्छे संबंध हैं. मनोज के मुताबिक़ समाज में जिस तरह दहेज के लिए वधू पक्ष के लोगों के साथ सलूक किया जाता है, वह उसके ख़िलाफ़ है.

इसलिए समाज की किसी लड़की की शादी दहेज के कारण नहीं होती है, तो स्वजातीय लड़के का अपहरण कर ऐसी लड़कियों से शादी करा दी जाती हैं. मनोज बोलते–बोलते बहुत कुछ कह गए. उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी के आलम में लोग इस तरह के गिरोह से जुड़ते जा रहे हैं. ''रिस्क कम, मुनाफ़ा अधिक'' पाने की चाहत में भी बेरोज़गार लोग इस गिरोह से जुड़ते जा रहे हैं. इस तरह के कारोबार में लगे लोगों का मानना है कि किसी लड़की की शादी कराना महापुण्य माना जाता है. यही सोचकर लोग ग़रीब लड़कियों की शादी पकड़कर लाए गए लड़कों के साथ कराने से परहेज़ नहीं करते हैं. मनोज के मुताबिक़ कुरूप लड़की अगर अमीर घराने की होती है, तो लड़के को अपहरण करने के एवज में उन्हें मुंहमांगी रक़म दी जाती है. वह दावे के साथ कहते हैं कि वे लोग दहेज लोभियों से कहीं बढ़िया इसलिए हैं क्योंकि रुपये पाने की चाहत में वह लड़की वालों को परेशान नहीं करते हैं. लड़की वालों की जैसी हैसियत होती है, उसी के हिसाब से रक़म मांगी जाती है.

राजेश विन्हा
feedback@chauthidunya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 21 दिसंबर–27 दिसंबर 2009

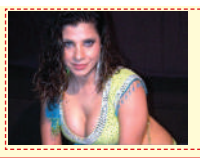

संभावना अपनी आइटम गर्ल वाली छवि से ख़ुश हैं. उन्होंने फ़िल्म *शोले* के भोजपुरी संस्करण में हेलन पर फ़िल्माए गए मशहूर गीत *महबूबा ओ महबूबा* पर जमकर वाहवाही बटोरी थी.

अंग प्रदर्शन से एतराज़ नहीं : संभावना

संभावना कहती हैं कि उन्हें भोजपुरिया हेलन कहलाना अच्छा लगता है. उन्हें इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है कि उन पर फ़िल्माए गए गीतों में अंग प्रदर्शन की लोग आलोचना करते हैं. उन्हें तो बस इस बात से ख़ुशी है कि उनकी लोकप्रियता बरक़रार है.

अपने ज़माने की मशहूर डांसर हेलन से तो सभी वाक़िफ़ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भोजपुरी फ़िल्मों में भी एक हेलन है? जी हां, इस नई हेलन का नाम है संभावना सेठ. अपने बिंदास डांस और अंग प्रदर्शन के लिए मशहूर संभावना को आजकल लोग इसी नाम से पुकारते हैं. सबसे अहम बात यह है कि संभावना मैडम भी इस नाम से काफ़ी ख़ुश हैं. वह कहती हैं कि मुझे ख़ुद को भोजपुरिया हेलन कहलाना अच्छा लगता है. उन्हें इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है कि लोग उन पर फ़िल्माए गए गीतों में अंग प्रदर्शन की आलोचना करते हैं. वह कहती हैं कि अगर उनके गानों में कोई अश्लीलता होती तो दर्शकों में वे इतने लोकप्रिय न होते. रही बात अंग प्रदर्शन की, तो उन्हें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों बाबा रामदेव ने अपने एक वक्तव्य में यह बात कही थी कि युवाओं को ऐसी अभिनेत्रियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी नहीं, सड़ी अभिनेत्रियां हैं. इसका जवाब भी संभावना ने अपने बिंदास अंदाज़ में दिया था. संभावना अपनी आइटम गर्ल वाली छवि से ख़ुश हैं. उन्होंने फ़िल्म *शोले* के भोजपुरी संस्करण में हेलन पर फ़िल्माए गए मशहूर गीत *महबूबा ओ महबूबा* पर जमकर वाहवाही बटोरी थी. तबसे लोग उनकी तुलना हेलन से करने लगे. ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ़ इसी छवि में क़ैद रहना चाहती हैं. उन्होंने कई हिंदी फ़िल्मों में कुछ भूमिकाएं भी की हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता न मिलने की वजह से वह थोड़ा निराश हो गई थीं. अब वह जल्द ही भोजपुरी फ़िल्मों में ख़ूबसूरती के जलवे दिखाने के साथ ही अपनी अभिनय क्षमता का प्रमाण भी देंगी.

पुश्तैनी बसेरे पर वन विभाग की मार

कहां जाएं कैमूर की तलहटी में बसे गांवों के हज़ारों लोग?

कहते हैं कि धरती पर रहने वाले हर जीव को उसका पुश्तैनी बसेरा प्यारा होता है. इस विषय पर कई तरह की कहानियां और फ़िल्में बनीं. हालांकि उक्त कहानियां और फ़िल्में महज़ एक गांव या मोहल्ले पर आधारित होती हैं, लेकिन यहां बात फ़िल्मों और कहानियों की नहीं हो रही है. कैमूर पहाड़ी और उसकी तलहटी में बसे 139 गांवों में रहने वाले हज़ारों लोगों के सामने अपने बसेरे को लेकर यक्ष प्रश्न मुंह बाए खड़ा है. वन अधिनियम की ऐसी मार पड़ी है कि संचुरी इलाक़े में बसे 25 गांवों को कभी भी विस्थापित होकर पहाड़ से नीचे उतरना पड़ सकता है. उनके पुरखों ने पहाड़ के ऊपर और घने जंगलों के बीच काफ़ी लंबे-चौड़े भूखंड पर अपने तरीक़े से बसेरों का निर्माण कराया था, जिनमें वे चैन से सोते थे. इतना ही नहीं, जंगली जानवरों की दोस्ती और मिलने वाली स्वच्छ हवा का मज़ा भी कुछ और था. अब उनकी खुशियों पर वन विभाग की तिरछी नज़र पड़ गई है. पर्यावरण के ख़तरे का हवाला देकर इन गांवों को संचुरी इलाक़े से विस्थापित करके पहाड़ के नीचे लाने की सरकारी कवायद शुरू हो गई है. जब इन गांवों में रहने वाले लोग पहाड़ से उतरकर घुटन भरे मैदानी वातावरण में आएंगे, तब उनके सामने सरकार की ओर से मुआवज़े, ज़मीन के बदले ज़मीन और रोज़गार की बातें भी होंगी. लेकिन, सदियों से कैमूर की पहाड़ी पर स्वछंद विचरण करने वालों के लिए न तो उपयुक्त वातावरण होगा और न ही स्वतंत्रता.

ग़ौरतलब है कि रोहतास ज़िले के दक्षिणी हिस्से में यदुनाथपुर से लेकर भुलडी तक प्राचीनतम कैमूर पहाड़ी के ऊपर स्थित सपाट मैदान में जंगलों से घिरे कम से कम तीन दर्ज़न गांव हैं, जहां के लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से पीने का पानी लाते हैं. वे पशुपालन एवं जंगली जड़ी-बूटियां चुनकर अपना जीवनयापन करते हैं. इस काम में वे पारंगत हैं, लेकिन जब उन्हें मूल बसेरे से बेदख़ल किया जाएगा तो लाज़िमी है कि उनके पुश्तैनी रोज़गार पर भी असर पड़ेगा. नया वातावरण भी उनके लिए ठीक वैसे ही होगा, जैसे जंगलों में विचरण कर रहे हिरणों को क़ैद कर दिया गया हो. सरकारी कवायद यह है कि संचुरी और ननसंचुरी दोनों ही इलाक़ों में पड़ने वाले कैमूर पहाड़ी के उन 139 गांवों को विस्थापित करके कहीं और ले जाया जाए. हालांकि यह कवायद अभी काग़ज़ों तक ही सिमटी है, अगर इस पर अमल हुआ तो आंदोलन होना तय है. मालूम हो कि इन सभी गांवों में लड़ाकू खरवार जाति के लोग रहते हैं. फ़िलहाल वे सरकार की इस योजना से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

माओवादियों के बुलंद हौसले

एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के ख़िलाफ़ निर्णायक अभियान चला रखा है, वहीं दूसरी तरफ माओवादी भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं. वे सरकार को धता बताते हुए दिनदहाड़े अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है. बिहार-झारखंड की सीमा से सटे गया ज़िले के डुमरिया प्रखंड की छकरबंधा पंचायत के ढकपहरी जंगल में दो दिसंबर को जनमूर्ति छापामार सेना (पीएलजीए) की नौवीं वर्षगांठ धूमधाम से दिन के उजाले में मनाई गई, जिसमें माओवादियों के शीर्ष नेताओं के अलावा एक हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया. 18 घंटे तक चले इस कार्यक्रम की भनक पुलिस को नहीं लगी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर ज़िले में ख़ुफ़िया विभाग के होने का क्या औचित्य है?

माओवादियों के कार्यक्रम स्थल पर चार जनरेटरों के अलावा आधा दर्ज़न से अधिक लाउडस्पीकर भी लगाए गए थे. माइक से माओवाद के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे. पूरे इलाक़े में उनकी आवाज़ गूंज रही थी, जिससे आसपास के ग्रामीण डरे-सहमे थे. शहीद कामरेड राहुल उर्फ लाहोर झंडा मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सबसे पहले माओवादियों ने अपने दिवंगत साथियों को लाल सलाम किया. सभास्थल पर पुलिस न पहुंचे, इसके लिए पहाड़ पर माओवादियों का मारक दस्ता तैनात था. चारू मजूमदार, कन्हाई चटर्जी, लेनिन, एंगेल्स एवं मार्क्स की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया.

भाकपा (माओवादी) के बिहार-झारखंड एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ स्पेशल एरिया कमेटी के जोनल कमांडर प्रशांत ने कहा कि हम सभी इस वर्षगांठ पर उपस्थित होकर अपने मिशन को और मज़बूती से अंजाम देने का संकल्प लेते हैं. कार्यक्रम में सब जोनल कमांडर अंसारी, मुलायम, सत्यम, प्लाटून इंचार्ज अभय एवं रोहित और झारखंड के चतरा, पलामू, औरंगाबाद, भोजपुर एवं गया आदि क्षेत्रों से आए माओवादी नेताओं ने भाग लिया. विदित हो कि भाकपा (माओवादी), एमसीसी और पीएलजीए दो दिसंबर 2000 को मिले थे. इसी अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है. कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सामूहिक भोज की भी व्यवस्था की गई थी. माओवादियों का सशस्त्र दस्ता अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार था. सबसे मज़ेदार तथ्य यह है कि डुमरिया समेत आसपास के अन्य प्रखंडों के लोगों को माओवादियों के इस कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. वादियां लाल सलाम से घंटों गूंजती रहीं, लेकिन पुलिस को यह गूंज सुनाई नहीं पड़ी. यही नहीं, दो दिन बाद भी पुलिस कार्यक्रम स्थल तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकी. हालांकि गया ज़िले के शेरघाटी अनुमंडल के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पर्याप्त सशस्त्र बल और पूरी रणनीति के बिना ऊपर से ही घोर नक्सली क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने की मनाही है. ऐसे में हम लोग आख़िर क्या कर सकते हैं?

सुनील कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

आदिवासियों को अधिकार होंगे सपने साकार

आदिवासियों को वन भूमि का हक़
वनोपज पर अधिकार तथा उचित दाम
भूमिहीनों को भूमि का पट्टा
अति पिछड़ी जन-जातियों की शासन में सीधी भर्ती
बिना उचित पुनर्वास के विस्थापन नहीं

कांग्रेस

चुनिए उन्हें, जिन्हें देश ने चुना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी।

CRAYONS